चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 06 जून–12 जून 2011 | मूल्य 5 रुपये

उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का एक काला अध्याय

पेज-3

ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं...

पेज-4

दंगों के इतिहास में हाशिमपुरा-मलियाना

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

लाइन में खड़ा किया गोली मारी और लाशें बहा दीं

मई 1987 का मेरठ दंगा देश पर लगा काला धब्बा है. दंगे सभ्य समाज की निशानी नहीं हैं. यह सभ्य समाज का एक अपवाद है. अगर सरकारी तंत्र ही इस अपवाद के लिए गुनाहगार हो तो मामला बेहद संगीन हो जाता है. इससे भी आगे यह मामला असभ्य बन जाता है, जब क़ानून गुनाहगारों को सज़ा देने के बजाय गुनाहगारों के साथ खड़ा नज़र आने लगता है. चौथी दुनिया ने सबसे पहले हाशिमपुरा के राज़ को दुनिया के सामने रखा था. इस उम्मीद से रखा था कि गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी. 25 साल होने को हैं. इंतज़ार जारी है. देश चलाने वालों से, प्रधानमंत्री से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यही प्रार्थना है कि इस काले दाग़ को देश के दामन से धोने का कष्ट करें...

-संपादक

मनीष कुमार

अगर न्याय में देरी का मतलब न्याय से वंचित होना है तो यह कह सकते हैं कि मेरठ के मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है. मई 1987 में हुआ मेरठ का दंगा पच्चीसवें साल में आ चुका है. इस दंगे की सबसे दर्दनाक दास्तां मलियाना गांव और हाशिमपुरा में लिखी गई. ख़ाकी वर्दी वालों का जुर्म हिटलर की नाजी आर्मी की याद दिलाता है. मलियाना और हाशिमपुरा की सच्चाई सुनकर रूह कांप जाती है. देश की क़ानून व्यवस्था पर यह एक ऐसा काला धब्बा है, जिस पर विश्वास नहीं होता है. यह कैसे संभव है कि निहत्थे और मासूम लोगों को गोली मारने वाले गुनाहगार आज़ाद घूम रहे हैं और जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को खो दिया, वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. मलियाना के गुनाहगारों को सज़ा मिलना तो दूर, ढंग से न्यायिक प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है. मलियाना गांव के लोग बात करते ही फफक पड़ते हैं. कहते हैं कि साहब, बहुत देर हो गई. अब तक तो सिर्फ़ दो-तीन गवाहों को ही सुना गया है. इस मामले में क़रीब 73 गवाह हैं. सभी गवाहों की बात पूरी होते-होते तो सब लोग मर जाएंगे. क्या इंसाफ़ हमारी क़ब्र पर डालेंगे? मेरठ के मलियाना गांव जाइए या फिर हाशिमपुरा जाकर देखिए. इन दोनों गांवों में शायद ही ऐसा कोई परिवार है, जिस पर 1987 के दंगे का ज़ख्म नहीं है. दुकान पर बैठा शख्स कहेगा कि मेरे अब्बू को दंगाइयों ने मार दिया. चाय वाला अपने भाई की मौत का दर्द बताएगा. कोई अपना ज़ख्म दिखाने लग जाएगा. राह से गुज़रते किसी से भी मिलिए, सबके दिलों में दंगे की याद ताज़ा है. अपने खोए हुए परिवारजनों का चेहरा याद है. विधवा हुई औरतें जवान से बूढ़ी हो गईं. जब उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और थरथराते होंठों से शब्द निकलते हैं तो कलेजा फट जाता है.

1987 का मेरठ दंगा खाकी वर्दी की बर्बरता का सबसे काला अध्याय है. हाशिमपुरा और मलियाना के आरोपी प्रोविंसियल आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी पीएसी के जवान हैं. उन पर हाशिमपुरा के चालीस से ज़्यादा निहत्थे मुस्लिम नौजवानों की गोली मारकर हत्या का आरोप है. वे मलियाना गांव में तलाशी के बहाने घुस कर लोगों पर गोली चलाने के आरोपी हैं. किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मनाक़ बात है कि 22-23 मई, 1987 की घटना पर कोर्ट का अब तक कोई फ़ैसला नहीं आया है. गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिली. यह सिर्फ़ न्याय में देर होने वाली बात नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया की कुटिलता का ऐसा उदाहरण है, जो बताता है कि हमारे देश का सरकारी तंत्र ख़ाकी वर्दी वालों की बर्बरता को लेकर कितना सजग है.

सच्चाई यह है कि आज़ादी के बाद जितने भी दंगे हुए, उनमें से मलियाना और हाशिमपुरा की घटना ने मुसलमानों की चेतना को सबसे ज़्यादा झकझोरा है. मुसलमानों को लगने लगा कि सरकारी तंत्र ही उनका दुश्मन है, उन पर हमला करता है. पहली बार मुसलमान बेसहारा महसूस करने लगे. क़ानून व्यवस्था से उनका भरोसा उठ गया. मेरठ के दंगों से यह पहली बार समझ में आया कि स्टेट स्पोंसर्ड दंगा किसे कहते हैं. किसी भी दंगे में पुलिस का क्या रोल होता है. ऐसा नहीं कि दंगों में पुलिस का ऐसा रोल पहली बार देखा गया, लेकिन पहली बार उसका इतना नग्न रूप दुनिया के सामने आया. अफ़सोस तो इस बात का है कि इस बटालियन को बैन करने, इसके अधिकारियों और जवानों को सज़ा देने के नाम पर किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया. जब यह दंगा हुआ, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे. जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में एक जांच दल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और राजीव गांधी को जांच रिपोर्ट के साथ पत्र भी लिखा, लेकिन दोनों ने उनके पत्रों को नज़रअंदाज़ कर दिया. राजीव गांधी के बाद कई प्रधानमंत्री आए. ऐसे भी प्रधानमंत्री, जिन्होंने मेरठ का दौरा किया, मलियाना गए, हाशिमपुरा गए, लेकिन यहां के लोगों को न्याय नहीं मिल सका. सरकार की यह लापरवाही आपराधिक है. यह घटना के प्रति सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट ग्रुप्स की उदासीनता को भी दर्शाता है. क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाए और गुनाहगारों को सज़ा दे. पच्चीस साल का वक़्त कम नहीं होता. इंतजार की भी हद होती है. कौन कितना इंतजार करे और क्यों करे. अब तो यही कहना पड़ेगा कि इस दंगे के गुनाहगारों की सूची में सरकार भी शामिल हो गई.

हाशिमपुरा देश का अकेला मुस्लिम मुहल्ला है, जिसके हर घर से किसी न किसी को पीएसी की बर्बर कार्रवाई की बलि चढ़ना पड़ा. क़रीब चार सौ व्यस्क पुरुषों को शरीर की एक न एक हड्डी तुड़वानी पड़ी. क़रीब चार दर्जन लोग अपाहिज हो गए. विधवाओं की आंखों में आंसू और मर्दों के शरीर पर गहरे ज़ख्म हाशिमपुरा के धरोहर हैं. जब भी कोई अजनबी इस मुहल्ले में दाखिल होता है तो भीड़ लग जाती है. लोग पूछते हैं कि दंगे के बारे में पूछने आए हो? हमने कहा, हां. पूछा, कहां से आए हो? हमने कहा कि चौथी दुनिया से. उस बूढ़े ने कहा, काफ़ी दिनों के बाद आए हो. सबसे पहले तो चौथी दुनिया ही हमारी आपबीती को दुनिया के सामने लाया था, वरना किसकी हिम्मत थी कि कोई सरकार और पीएसी के ख़िलाफ़ ख़बर छाप दे.

मेरठ के बीचोबीच बसा हाशिमपुरा कोई बड़ा मुहल्ला नहीं है. बस दो गलियां हैं. पीएसी ने जिन लोगों की हत्या की, उनमें ज़्यादातर मज़दूर थे, ग़रीब थे. आज भी इस मुहल्ले में बेरोज़गारी है. कोई ठेला चलाता है, कोई मज़दूरी करता है. दंगे की वजह से हाशिमपुरा समय से कई साल पीछे छूट गया. एक तो यहां के लोग पीएसी के जुल्म के शिकार हुए, फिर सरकार ने इसे संवेदनशील इलाक़ा घोषित कर दिया.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

राइफल की गोली. धड़ाधड़...धड़ाधड़... गोलियों की बारिश हो गई. उसमें मैं बच गया. मेरे दोनों तरफ़ वालों को लग गई थी गोली. तब एक पीएसी का जवान चढ़ा और उसने हाथ पकड़ कर खींचा और नीचे उतारा. मैंने कहा, मत मारो मुझे, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं. वे नहीं बाज़ आए. मैंने एक हाथ छुड़ाकर राइफल का मुंह पकड़ लिया. उन्होंने मेरा हाथ मोड़कर पीछे को दबा दिया और गोली चला दी. मेरे पेट को पार कर गई गोली. मैं यह कहकर गिर पड़ा, हाय अल्लाह, मैं मर गया...

25 साल

दंगे के दौरान आगजनी और लूटपाट से हुए नुक़सान का अंदाज़ा लगाना तो वैसे भी बेहद मुश्किल काम है. जले और लुटे हुए सामानों की क़ीमत तो जोड़ी जा सकती है, लेकिन पच्चीस साल से लगातार बहते आंसुओं की क़ीमत लगाने की हिम्मत किसकी है? ईद और रमजान में ख़ुशियों की जगह घर के चिराग़ के गुम होने की पीड़ा की क़ीमत कौन लगाएगा? सरकार ने तो हद ही कर दी. चालीस हज़ार रुपये में सब कुछ बराबर कर दिया और उसे ही न्याय समझ लिया.

हाशिमपुरा सामूहिक हत्याकांड का चश्मदीद

22 मई, 1987 का मनहूस दिन. बेहद गर्मी थी. बहुत सालों बाद मेरठ में ऐसी गर्मी पड़ी थी. शहर में दंगा हो रहा था. कर्फ्यू भी लगा था. लोग अपने घरों में ही थे. किसी को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि अगले कुछ घंटों में हाशिमपुरा इतिहास के सबसे काले अध्याय का हिस्सा बनने जा रहा है. क़रीब दो बजे मिलेट्री और पीएसी तलाशी के बहाने मुहल्ले में दाख़िल हुई. लोग अलविदा की नमाज़ पढ़ रहे थे. हर घर में पीएसी पहुंची और जितने भी मर्द थे, उन्हें घर से बाहर आने को कहा गया.

चौथी दुनिया को इस घटना के चश्मदीद उस्मान ने बताया, बाहर निकालने के बाद बल्ली गली में लाकर बैठाया गया. वहां काफ़ी आदमी बैठे हुए थे. पुलिस ने सबको कहा कि चलो, हाथ ऊपर करो और हाथ ऊपर उठाकर हमें सड़क पर लाकर बैठा दिया गया. जब हम सड़क पर आए तो पता चला कि पूरे मुहल्ले को ही गिरफ्तार कर लिया है. बूढ़े और बच्चे अलग बैठे थे और जवानों की टोलियां अलग बना रखी थीं. मिलेट्री, पीएसी और पुलिस सब लोग मौजूद थे. मैं बच्चों में पहुंच गया. उन्होंने कहा कि बूढ़ों और बच्चों को छोड़ देंगे. जब जवान-जवान भरकर भेज दिया तो बूढ़ों और बच्चों का नंबर आया तो मुझे उसमें से छांट लिया गया. मतलब जो तगड़ा दिखा, उसे एक तरफ़ निकाल लिया. जब हम खड़े हुए तो वहां सैकड़ों लोग खड़े थे. मेरे आगे जो चार-पांच खड़े थे, उनको मैं जानता था. वे मुहल्ले के ही थे. एक हाज़ी मुस्तकीम, एक आर टी दफ्तर के यासीन, एक सलीम और कदीर चायवाला. ये मेरे आगे खड़े थे. क़रीब आठ-साढ़े आठ का टाइम हो गया था, रात का. हमें छांट कर एक तरफ़ खड़ा किया और पीएसी का ट्रक मंगाया और हमसे कहा कि इसमें चढ़ो. ताला खोला और उसमें हमें भेड़-बकरियों की तरह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मुरादनगर में गंगनहर के किनारे इसी जगह पर हाशिमपुरा के लोगों को मारा गया.

"Cotton ki Jhappi!"

T.T.

Healthy Innerwear

Vest • Brief • Bra-Panties • T-Shirts

Ph. : 011-45060708, E-mail: export@tttextiles.com

नौशाद अली उस वक़्त स्कूल में पढ़ते थे. माहौल ख़राब था तो उन्हें घर में बंद कर दिया गया. उनके घर के सामने वाले घर में दो लोगों की गोलियां लगने से मौत हो गई.

लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और लाशें बहा दीं

पृष्ठ एक का शेष

जब भी शहर में माहौल ख़राब होता है तो सबसे पहले पुलिस हाशिमपुरा की नाकाबंदी कर देती है. बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आना था तो पुलिस ने हाशिमपुरा को घेर लिया. पता नहीं, अधिकारियों के दिमाग़ में यह कौन सी बीमारी है कि वे मुसलमानों को ही दंगे की वजह मानते हैं. अजीब बात है कि जो लोग पीड़ित हैं, सरकार ने उन्हें ही गुनाहगार बना दिया. इससे हुआ यह कि इस मुहल्ले में मकान तो हैं, लेकिन कोई किराएदार नहीं आता. जबसे दंगा हुआ है, यहां की ज़मीन और घरों की क़ीमत न के बराबर है. यहां के लोग कहते हैं कि हाशिमपुरा के चारों तरफ़ प्रॉपर्टी की क़ीमत आसमान छू रही है, लेकिन इस मुहल्ले में कोई ख़रीददार नहीं आता. मुहल्ले के लड़के मेरठ शहर में कहीं नौकरी मांगने जाते हैं तो मुहल्ले का नाम बताते ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है. मतलब यह कि शहर के लोग भी हाशिमपुरा के लोगों को शक की निगाहों से देखते हैं.

हाशिमपुरा में हमारी मुलाकात ज़ुल्फ़िक़ार नासिर और नईम से हुई. नईम आठवीं कक्षा में पढ़ते थे, जब उन्हें पीएसी उठा ले गई थी. हट्टा-कट्टा था तो पीएसी वाले इसे भी पकड़ ले गए, लेकिन जब ट्रक में गोलियां चलीं तो इसके आगे जो शख़्स था, उसका ख़ून और आंतें इसके शरीर पर चिपक गईं. यह चुपचाप लेट गया. पीएसी वालों को लगा कि यह मर चुका है, उठाकर नहर में फेंक दिया. जब ट्रक चला गया, तब नासिर और नईम वहां से एक साथ वापस निकले थे. ज़ुल्फ़िक़ार नासिर ने राजीव गांधी से मुलाकात भी की. नासिर ने बताया कि मुलाकात के दौरान उसने पूरी घटना बताई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, तब मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने सीबीसीआईडी से एक जांच कराई, जिसने रिपोर्ट देने में 7 साल लगा दिए. तब तक लोग इस घटना को भूल गए. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट ने 1987 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हाशिमपुरा के पीड़ितों को 40,000 रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया. लेकिन गुनाहगारों को सज़ा कैसे मिले, इस बात पर कोई मामला नहीं बना. जब सीबीसीआईडी की रिपोर्ट आई तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया. हाशिमपुरा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इन्होंने कोर्ट से यह याचना की कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और गुनाहगारों को सज़ा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं की. कोर्ट ने कहा कि यह मामला आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं आता है और इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो. आखिरकार हाशिमपुरा के लोगों ने 15 फरवरी, 1995 को लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर की. सीबीसीआईडी की रिपोर्ट में पीएसी और पुलिस के 60 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ़ 19 लोगों पर ही मुक़दमा चलाने की अनुमति दी. 19 में से अब सिर्फ़ 16 ज़िंदा हैं. सभी निचली रैंक के हैं. वैसे सरकार ने इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की, यह किसी को पता नहीं है. 2002 से तीस हज़ारी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, अभी भी चल ही रही है. 25वें साल में भी फ़ैसला नहीं आया है. हाशिमपुरा के लोगों को लगता है कि वे अभिशप्त बन गए हैं. उनकी मदद के लिए सरकार ने तो कुछ नहीं किया, मुस्लिम संगठनों ने भी कोई मदद नहीं की. हाशिमपुरा के लोग ग़रीब ज़रूर हैं, लेकिन उनका जज़्बा ग़रीब नहीं है. ये लोग चंदा करके न्याय के लिए लड़ रहे हैं.

1983 के मेरठ दंगे के दौरान मलियाना शांत रहा. यहां हिंदू-मुसलमान हमेशा से साथ-साथ रहे हैं, लेकिन 1987 में मलियाना को किसी की नज़र लग गई. उस दिन अजीब सा माहौल था. अफ़वाहों का बाज़ार गर्म था. लोग कह रहे थे कि यहां गिरफ्तारियां होंगी. शक सच सबित हो गया, जब पुलिस ने ग्यारह बजे के क़रीब पूरे गांव को घेर लिया और तलाशी के नाम पर लोगों को घर से बाहर निकालना शुरू किया. पीएसी के जवान गोलियां चलाने लगे. सिर पर गोली, गले में गोली, सीने पर गोली. जिसे भी गोली लगी, वहां लगी, जहां लगने के बाद बचना नामुमकिन है. तीन घंटे तक गोलियां चलती रहीं.

मलियाना: अब तो न्याय मिलने की उम्मीद भी नहीं है

1983 के मेरठ दंगे के दौरान मलियाना शांत रहा. यहां हिंदू-मुसलमान हमेशा से साथ-साथ रहे हैं, लेकिन 1987 में मलियाना को किसी की नज़र लग गई. उस दिन अजीब सा माहौल था. अफ़वाहों का बाज़ार गर्म था. लोग कह रहे थे कि यहां गिरफ्तारियां होंगी. शक सच सबित हो गया, जब पुलिस ने ग्यारह बजे के क़रीब पूरे गांव को घेर लिया और तलाशी के नाम पर लोगों को घर से बाहर निकालना शुरू किया. पीएसी के जवान गोलियां चलाने लगे. सिर पर गोली, गले में गोली, सीने पर गोली. जिसे भी गोली लगी, वहां लगी, जहां लगने के बाद बचना नामुमकिन है. तीन घंटे तक गोलियां चलती रहीं. सबसे पहले सत्तार वल्द मोहम्मद अली के घर को लूटा गया. इस परिवार के लगभग 11 लोग मारे गए. उनकी लाशों को कुएं में डालकर उन पर नमक डाल दिया गया. इसके बाद दंगे की आग पूरे गांव में फैल गई. यहां पुलिस ने दहशत फैलाने के लिए एक घर को जला दिया. मकान के साथ-साथ इस परिवार के छह लोग जलकर राख हो गए. इस घर में चार बच्चे थे. जब लाशें निकाली गईं तो सबसे छोटा बच्चा मां की गोद से सटा मिला. देखते ही देखते मलियाना गांव के सौ-सवा सौ मकानों में आग लगा दी गई. क़रीब 73 लोगों की मौत हुई, जबकि सरकारी आंकड़े यह संख्या बहुत ही कम बताते हैं. दंगाइयों में आसपास के लोगों के अलावा बाहर के भी कई लोग थे.

घटना के तुरंत बाद मोहम्मद याकूब ने थाने में एफआईआर की. सोचा कि कम से कम दंगाइयों को क़ानून से सज़ा मिल जाए. जिन पुलिसवालों ने बेगुनाहों की जान ली है, उन्हें सज़ा मिल जाए, लेकिन यह पता नहीं था कि इस दंगे से ज़्यादा गहरा घाव न्याय दिलाने वाले संघर्ष से मिलने वाला है. मोहम्मद याकूब ने बताया कि हमने 93 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर की थी, 75 गवाह हैं. बीस साल बीत गए, यह पता ही नहीं चला कि मामले का क्या हुआ, हमारी एफआईआर कहां गई, उन पीएसी के जवानों पर क्या कार्रवाई हुई. इतने लोग मारे गए, लेकिन किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए. बीस साल के बाद हमें कोर्ट से सम्मन आया कि आपके मामले की सुनवाई होने वाली है. हम फिर अदालत पहुंचे, अपना वकील किया. जो कुछ कर सके, वह किया. पहले ही दिन विपक्ष के वकील ने कहा कि इसमें एफआईआर नहीं है. जब तक एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी नहीं होगी, तब तक मुक़दमा नहीं चलेगा. उसके बाद जज ने पूछताछ की. पता करने की कोशिश की कि किसने ग़ायब की, कहां खो गई यह एफआईआर. फिर हम थाने गए और पूछा कि 23 मई, 1987 को हमने एक एफआईआर की थी, उसकी कॉपी चाहिए. थानेदार ने कहा कि हमारे पास नहीं है. हम सिर्फ़ पांच साल का ही रिकॉर्ड रखते हैं. हम सारे काग़ज़ात अदालत में जमा कराकर साइन करा लेते हैं. अब तो हमारे पास न रिकॉर्ड है और न हम कुछ बता सकते हैं. हमने हर जगह चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक एफआईआर का पता नहीं चल सका है. इसके बाद जज ने कहा कि जो गवाह हैं, उन्हें पेश करो. हमने वकील साहब को पेश किया, उनकी गवाही चली. वह फास्ट ट्रैक कोर्ट था. हर हफ्ते तारीख़ लगती थी. एक साल तक एक ही आदमी की गवाही हुई. फिर एक साल बाद दूसरी गवाही पेश की गई. ऐसे तो पचहत्तर साल लग जाएंगे. पच्चीस साल ऐसे भी हो गए हैं. आने वाले पचहत्तर सालों में न तो कोई मुजरिम रहेगा और न कोई गवाह बचेगा. इतनी तो उम्र किसी की है नहीं. एक बात और, इस मामले को फिर फास्ट ट्रैक से दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया. वह फास्ट ट्रैक है नहीं. इस कोर्ट में जब पहुंचे तो जज ने पूछा कि एफआईआर कहां है तुम्हारी. मैं यह मुक़दमा नहीं चलाऊंगा. पहले एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लाओ. अब मैं कहां से लाऊं. यह तो आपका काम है. आप इसे ढूंढो. तो इस मामले को पेंडिंग में डाल दिया गया. अब चार महीने हो गए हैं, न तो नक़ल मिली है, न मुक़दमे की कोई कार्रवाई हो रही है. इस तरीक़े से कहां से इंसाफ़ मिलेगा?

इस मामले के पहले गवाह से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो देखा, वह कोर्ट में बताया. मुक़दमा इतना सुस्त चल रहा है कि क्या इंसाफ़ होगा. 25 साल में आज तक इतना भी नहीं हुआ कि हमारे ज़ख्मों को ज़रा सा भी मरहम मिलता कि हां, हमारे साथ ज़ुल्म हुआ और गुनाहगारों को सज़ा मिली. और अगर मिल भी गई तो क्या हमारी क़ब्र पर रखेंगे इंसाफ़? न जाने कितनी आंखें बंद हो गईं इसी इंतज़ार में. इस मामले के पहले गवाह वकील साहब ने बताया कि 23 मई को नौ बजे तक माहौल बिल्कुल शांत था. फिर ग्यारह बजे पीएसी ने शराब का ठेका लुटवाया. पुलिस ने ताला तोड़ा और दंगाई शराब लूटकर ले गए. इसके बाद मलियाना में पुलिस और दंगाइयों का क़हर शुरू हुआ. दंगाइयों के साथ पुलिस मुस्लिम आबादी वाले इलाक़े में घुस गई. पहले पथराव हुआ. पथराव में रेलवे लाइन के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ. रेलवे लाइन मलियाना से काफ़ी दूर है. मतलब यह कि दंगाइयों ने पहले से ही पत्थरों का इंतज़ाम किया था. दंगे की प्लानिंग पहले ही हो गई थी. वह कहते हैं कि मैं उस वक़्त अपने घर की छत पर था. इधर-उधर देख रहा था कि कहां क्या हो रहा है. गोकुल लाला की छत पर पीएसी के जवान तैनात थे. वे गोली चला रहे थे. मुझे यह नहीं लगा कि इतनी दूर से मुझे गोली लग सकती है. मुझे दो गोलियां लगीं. एक पेट में और दूसरी हाथ में. माहौल इतना ख़राब था, इतनी बदहवासी का था कि किसी को यह मालूम नहीं था कि बेटी कहां है, पति कहां है, मां कहां है, बेटा कहां है. और तो और, जो लोग बच कर भाग रहे थे, उन पर पीएसी डंडे चला रही थी. बहुत बुरा हाल था. कोई फ़रियाद भी कर रहा था तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था.

नौशाद अली उस वक़्त स्कूल में पढ़ते थे. माहौल ख़राब था तो उन्हें घर में बंद कर दिया गया. उनके घर के सामने वाले घर में दो लोगों की गोलियां लगने से मौत हो गई. नौशाद अली कहते हैं कि दंगाई पहले घर लूट रहे थे, फिर आग लगा रहे थे. चार बजने के बाद गोलियों की आवाज़ थम गई. लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया. उन्हें याद है कि वह अपने घर से बाहर निकल कर मैदान की ओर जा रहे थे. उनके दस क़दम आगे एक लड़की जा रही थी. अचानक एक गोली चली और उसकी मौत हो गई. गोली पीएसी के एक जवान ने चलाई थी. जब पीएसी वालों ने देखा कि ज़्यादा लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तब उन्होंने गोलियां चलानी बंद कर दीं.

गांव वाले कहते हैं कि पीएसी और पुलिस वालों ने तीन घंटे की छूट दे रखी थी. एक गांव वाले ने यह भी बताया कि यहां भी हाशिमपुरा की तरह घटना होते-होते बच गई. यहां भी पीएसी वालों ने लाइन में खड़ा कर दिया था. अंसार कहते हैं कि हम सात-आठ लोग थे. हमारी कमीजें उतरवा कर पीछे हाथ बांधकर लाइन में खड़ा करा दिया. पीएसी का एक अधिकारी कह रहा था कि इन्हें लाइन में लगाकर गोली मार दो और नहर में फेंक दो, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे थे. कई लोग वहां आ गए. हमें छोड़ दिया गया, अगर देर हो गई होती तो हमें भी मारकर नहर में फेंक देते.

क़रीब चार बजे गोलियों की आवाज़ें थम गईं. हर तरफ़ से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं. लोग गांव के बीचोबीच एक तालाब के पास खड़े हो गए. उनमें घायल भी थे. वहां पुलिस और अधिकारी भी खड़े थे. डीएम और एसपी सब आ चुके थे. जब उनसे कहा गया कि जो लोग ज़ख्मी हैं, उन्हें तो कम से कम अस्पताल पहुंचा दो. उनका जवाब यह था कि हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है. इस दंगे में घायल हुए लोगों को अभी भी याद है कि वे लोग साढ़े छह बजे अस्पताल पहुंचे थे. वहां भी इनके साथ दुर्व्यहार हुआ. बड़े-बड़े नेता आए, उन्होंने आश्वासन दिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया. कुछ मुस्लिम नेता तो अब यह भी कहने लगे हैं कि क्यों मलियाना के पीछे पड़े हो. मलियाना के दंगे से जुड़ी कई बातें अनोखी और शर्मनाक़ हैं. इस दंगे की कोई भी फोटो नहीं है. एक फोटोग्राफर ने छिपकर मलियाना में मारे गए लोगों की तस्वीरें ली थीं, लेकिन एक पीएसी वाले की नज़र पड़ गई और उसने कैमरा छीन लिया और रील निकाल कर फेंक दी.

यह सचमुच अनोखी बात है. पीएसी के जवानों ने मलियाना और हाशिमपुरा में मौत का जो तांडव किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया? किस अधिकारी या नेता ने इसकी मंजूरी दी थी, कांग्रेस की राज्य सरकार क्या कर रही थी? मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया गया, अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? केंद्र में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते यह सब कैसे हो गया? क्या यह संभव है कि किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार को पता न चले? मलियाना और हाशिमपुरा की घटना और चश्मदीद गवाहों के बयानों से यह साफ़ होता है कि सब कुछ नियोजित था. काफ़ी दिनों से प्लानिंग हो चुकी थी. नाज़ियों से भी भयंकर घटना को अंजाम देने वाली पीएसी और पुलिस के किसी भी अधिकारी को सज़ा नहीं मिली, बल्कि कुछ को तो बाक़ायदा प्रमोशन मिला और वे आज भी नौकरी कर रहे हैं. क्या यही है सेकुलर देश का सरकारी तंत्र और न्याय? किसी भी दंगे का पच्चीस साल बाद आकलन करना बड़ा कठिन काम है. यह काम कठिन और भी हो जाता है, जब दंगे के गुनाहगार आज़ाद घूम रहे हों. दंगे की मार सबसे ज़्यादा पेट पर पड़ती है. दंगे के बाद मलियाना और हाशिमपुरा में रोज़ी-रोटी का सिलसिला बिगड़ गया. दंगे के दौरान आगजनी और लूटपाट से हुए नुक़सान का अंदाज़ा लगाना तो वैसे भी बेहद मुश्किल काम है. जले और लुटे हुए सामानों की क़ीमत तो जोड़ी जा सकती है, लेकिन पच्चीस साल से लगातार बहते आंसुओं की क़ीमत लगाने की हिम्मत किसकी है? ईद और रमजान में ख़ुशियों की जगह घर के चिराग़ के गुम होने की पीड़ा की क़ीमत कौन लगाएगा? सरकार ने तो हद ही कर दी. चालीस हज़ार रुपये में सब कुछ बराबर कर दिया और उसे ही न्याय समझ लिया.

manish@chauthiduniya.com

हाशिमपुरा सामूहिक हत्याकांड का चश्मदीद

पृष्ठ एक का शेष

भर लिया. भरने के बाद, हम उस ट्रक में पचास-पचपन से कम नहीं थे, पूरा ट्रक भरा हुआ था. पीएसी वाले राइफलें लेकर पीछे खड़े हो गए और हमें नीचे बैठा दिया. हम पर डंडा बजाया कि मुड़ कर मत देखो, आगे देखो. ट्रक चलता रहा, काफ़ी देर तक चलता रहा. हमें पता नहीं कि किधर को चल रहा है. यह भी पता नहीं कि कहां जा रहा है. काफ़ी देर बाद ट्रक रुक गया. ट्रक मुरादनगर के गंगनहर पर जाकर रुका. वहां बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, वह आम का पेड़ था. पास में खजूर के पेड़ थे. पीएसी वाले उतर गए. किसी ने कहा कि ट्रक की लाइट बंद कर दो. फिर एक आदमी को उतारा और उसे गोली मार दी. हमें समझ में आ गया कि अब सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे. तब फिर उन्होंने एक और आदमी को नीचे उतारा. उसे भी गोली मार दी. मरना तो अब भी था और मरना तो जब भी था. लोगों को यह हुआ कि मर तो रहे ही हैं, ट्रक से बाहर कूद जाओ. जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने ट्रक के अंदर गोली चला दी. राइफल की गोली. धड़ाधड़...धड़ाधड़... गोलियों की बारिश हो गई. उसमें मैं बच गया. मेरे दोनों तरफ़ वालों को लग गई थी गोली. तब एक पीएसी का जवान चढ़ा और उसने हाथ पकड़ कर खींचा और नीचे उतारा. मैंने भागने की कोशिश की तो दो आदमी आकर खड़े हो गए और मुझे पकड़ लिया. मैंने कहा, मत मारो मुझे, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं. वे नहीं बाज़ आए. वह आ ही रहा था मारने के लिए कि मैंने एक हाथ छुड़ाकर राइफल का मुंह पकड़ लिया. इस तरह पकड़ रखा था, जहां से गोली निकलती है. उन्होंने मेरा हाथ मोड़कर पीछे को दबा दिया और गोली चला दी. मेरे पेट को पार कर गई गोली. मैं यह कहकर गिर पड़ा, हाय अल्लाह, मैं मर गया...मैं नीचे गिर पड़ा तो उसने कहा, इसे पानी में फेंक दो. दो आदमियों ने मेरे हाथ पकड़े और एक ने टांग. हिंडोले करके मुझे पानी में फेंक ही रहे थे कि दूसरी गोली मेरी टांग में लग गई. पानी में गिरने से पहले ही पानी ने मुझे उठा दिया. मैंने तैरने की कोशिश की, लेकिन मुझसे तैरा नहीं गया. मैं पानी में आगे की ओर बढ़ने लगा और किनारे लग गया. घास पकड़ कर लटका रहा. पीएसी वाले पानी में गोलियां मार रहे थे. आवाज़ें आ रही थीं गिरने की भी, गोलियों की भी. फिर जब इतनी देर हो गई तो मैंने देखा कि अब किसी चीज की आवाज़ नहीं है. न गोली की, न पानी में गिरने की यानी वे चले गए थे. मैंने पानी से निकलने की कोशिश की. दो हाथ और एक टांग काम कर रहे थे. मैं निकलने में कामयाब हो गया. निकल कर ऊपर आ गया तो वहां मैंने देखा कि दो लड़के और पड़े हैं गोली लगे हुए. वे कराह रहे थे. दो लड़के और आए थोड़ी देर बाद. उसी ट्रक के थे. एक ज़ुल्फ़िक़ार नासिर और दूसरा नईम था. दोनों हमारे ही मुहल्ले के थे. इनमें से एक के पेट से गोली निकली थी और एक साफ़ बचा हुआ था. हमसे चला नहीं जा रहा था. उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तीनों को तो हम एक साथ नहीं ले जा सकते, गांव से लोगों को लेकर आते हैं, फिर उठाकर ले जाएंगे. वे गांव पहुंचे या नहीं पहुंचे, पता नहीं. दो घंटे बीत गए. वे नहीं आए. काफ़ी देर हो गई. अलविदा का दिन था, नक्कारा होता है कोई दो-ढाई बजे के टाइम. नक्कारे की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि यहां कोई मुसलमानों का गांव है आसपास में. कोई आएगा सुबह को, तो ले जाएगा उठाकर...अपने मन में सोचा. उसके थोड़ी देर बाद सामने से रोशनी चमकी. मुझे पता नहीं चला कि क्या चीज है. ट्रक है, कार है, बुलेट है या स्कूटर है. मेरे बराबर में आई तो मैंने हाथ देकर रोक लिया. जैसे उन्हें रोका तो वह दारोगा था. उसके पीछे दो लोग और बैठे थे. दारोगा ने कहा कि क्या है बे. मैंने कहा कि मुझे पीएसी वालों ने गोली मार दी, नहर में फेंक दिया, निकल कर ऊपर आया हूं. तो उन्होंने आसपास देखा और कहा कि बेटा, घबराओ मत, मैं तुझे अभी ले जाऊंगा उठाकर. एक को बुलेट से भेज दिया और यह कहा कि थाने में खड़ी जीप ले आओ. फिर जीप आई. हम सबको जीप में डाल लिया गया. बाकी लोग बेहोश थे, मैं होश में था. पुलिस वालों ने कहा कि बेटा, मुझे उम्मीद है कि तू बच जाएगा. तुम पीएसी वालों का नाम मत लेना. मैंने कहा, और क्या कहूं जी? उन्होंने कहा कि तुम यह कहना कि मैं अपने भैया को देखने गया था गेट के पास. वहां बलवा हुआ, मुझे गोली लग गई. तब किसी चीज में मुझे डाला और ले जाकर पानी में फेंक दिया. पानी में मुझे होश आया. मैं निकल कर बाहर आ गया तो पता चला कि यह मुरादनगर की गंगनहर है. वहां से पुलिस मुझे उठाकर लाई. यही बयान देता रहा तो तेरी जान बच जाएगी. हम तुझे अस्पताल ले जा रहे हैं. वे मुझे अस्पताल लाए, मेरा इलाज कराया. फिर दिल्ली के एम्स में भेज दिया. वहां एक महीना इलाज चला. एक महीने बाद मैं वापस आ गया.

1987 के मेरठ दंगे की तस्वीर, जो अपनी कहानी ख़ुद बयान कर रही है. पीएसी के जवान मुसलमानों को घेरे में लिए हुए हैं. फोटो खींचने वाले प्रवीन जैन का कहना है कि इनमें से कोई भी ज़िंदा अपने घर को वापस नहीं लौटा.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 13
दिल्ली, 06 जून–12 जून 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

विशेष संवाददाता
सरोज कुमार सिंह (बिहार)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

पुलिया पर पहुंचते-पहुंचते वी बी सिंह की मोटरसाइकिल की हेडलाइट जब नहर के किनारे स्थित सरकंडे की झाड़ियों पर पड़ी तो उन्हें गोलियों की आवाज़ का रहस्य समझ में आया.

25 साल

हाशिमपुरा उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का एक काला अध्याय

मेरठ दंगा

नईम

ज़ुल्फ़िक़ार नासिर

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

विभूति नारायण राय मई 1987 में ग़ाज़ियाबाद के एसएसपी थे. 22/23 मई, 1987 की रात में मुरादनगर और दिल्ली से सटे मकनपुर में क्या घटा, जानिए ख़ुद उनकी ज़ुबानी...

विभूति नारायण राय

जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते. एक दु:स्वप्न की तरह वे हमेशा आपके साथ चलते हैं और कई बार तो क़र्ज़ की तरह आपके सिर पर सवार रहते हैं. हाशिमपुरा भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही अनुभव है. 22/23 मई, 1987 की आधी रात दिल्ली–ग़ाज़ियाबाद सीमा पर मकनपुर गांव से गुज़रने वाली नहर की पटरी और किनारे उगे सरकंडों के बीच टार्च की कमज़ोर रोशनी में ख़ून से लथपथ धरती पर मृतकों के बीच किसी जीवित को तलाशना... सब कुछ मेरे स्मृति पटल पर किसी हॉरर फिल्म की तरह अंकित है. उस रात दस–साढ़े दस बजे हापुड़ से वापस लौटा था. साथ में ज़िला मजिस्ट्रेट नसीम जैदी थे, जिन्हें उनके बंगले पर उतारता हुआ मैं पुलिस अधीक्षक निवास पर पहुंचा. निवास के गेट पर जैसे ही कार की हेडलाइट्स पड़ी, मुझे घबराया हुआ और उड़ी रंगत वाला चेहरा लिए सब इंस्पेक्टर वी बी सिंह दिखाई दिया, जो उस समय लिंक रोड थाने का इंचार्ज था. मेरा अनुभव बता रहा था कि उसके इलाक़े में कुछ गंभीर घटा है. मैंने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया और नीचे उतर गया.

वी बी सिंह इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए सुसंगत तरीक़े से कुछ भी बता पाना संभव नहीं लग रहा था. हकलाते हुए और असंबद्ध टुकड़ों में उसने जो कुछ मुझे बताया, वह स्तब्ध कर देने के लिए काफ़ी था. मेरी समझ में आ गया कि उसके थाना क्षेत्र में कहीं नहर के किनारे पीएसी ने कुछ मुसलमानों को मार दिया है. क्यों मारा? कितने लोगों को मारा? कहां से लाकर मारा? स्पष्ट नहीं था. कई बार उसे अपने तथ्यों को दोहराने के लिए कहकर मैंने पूरे घटनाक्रम को टुकड़े–टुकड़े जोड़ते हुए एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की. जो चित्र बना, उसके अनुसार वी बी सिंह थाने में अपने कार्यालय में बैठा हुआ था कि लगभग 9 बजे उसे मकनपुर की तरफ़ से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी. उसे और थाने में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों को लगा कि गांव में डकैती पड़ रही है. आज तो मकनपुर गांव का नाम सिर्फ़ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है. आज गगनचुंबी आवासीय इमारतों, मॉल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों वाले मकनपुर में 1987 में दूर–दूर तक बंजर ज़मीन पसरी हुई थी. इसी बंजर ज़मीन के बीच की एक चक रोड पर वी बी सिंह की मोटरसाइकिल दौड़ी. उसके पीछे थाने का एक दारोगा और एक अन्य सिपाही बैठे थे. वे चक रोड पर सौ गज भी नहीं पहुंचे थे कि सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया. अगर उन्होंने समय रहते हुए अपनी मोटरसाइकिल चक रोड से नीचे न उतार दी होती तो ट्रक उन्हें कुचल देता. अपना संतुलन संभालते–संभालते जितना कुछ उन्होंने देखा, उसके अनुसार ट्रक पीले रंग का था और उस पर पीछे 41 लिखा हुआ था. पिछली सीटों पर खाकी कपड़े पहने कुछ लोग बैठे हुए दिखे. किसी पुलिसकर्मी के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि पीएसी की 41वीं बटालियन का ट्रक कुछ पीएसी कर्मियों को लेकर गुज़रा था. पर इससे गुत्थी और उलझ गई. इस समय मकनपुर गांव में पीएसी का ट्रक क्यों आया था? गोलियों की आवाज़ के पीछे क्या रहस्य था? वी बी सिंह ने मोटरसाइकिल वापस चक रोड पर डाली और गांव की तरफ बढ़ा. मुश्किल से एक किलोमीटर दूर जो नज़ारा उसने और उसके साथियों ने देखा, वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला था. मकनपुर गांव की आबादी से पहले चक रोड एक नहर को काटती थी. नहर आगे जाकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर जाती थी. जहां चक रोड और नहर एक–दूसरे को काटते थे, वहां पुलिया थी.

पुलिया पर पहुंचते–पहुंचते वी बी सिंह की मोटरसाइकिल की हेडलाइट जब नहर के किनारे स्थित सरकंडे की झाड़ियों पर पड़ी तो उन्हें गोलियों की आवाज़ का रहस्य समझ में आया. चारों तरफ़ ख़ून के धब्बे बिखरे पड़े थे. नहर की पटरी, झाड़ियों और पानी के अंदर ताजा ज़ख्मों वाले शव पड़े थे. वी बी सिंह और उनके साथियों ने घटनास्थल का मुलाहिज़ा कर अंदाज़ लगाने की कोशिश की कि वहां क्या हुआ होगा? उनकी समझ में सिर्फ़ इतना आया कि वहां पड़े शवों और रास्ते में दिखे पीएसी के ट्रक में कोई संबंध ज़रूर है. साथ के सिपाही को घटनास्थल पर निगरानी के लिए छोड़ते हुए वी बी सिंह अपने साथी दारोगा के साथ वापस मुख्य सड़क की तरफ़ लौटा. थाने से थोड़ी दूर ग़ाज़ियाबाद–दिल्ली मार्ग पर पीएसी की 41वीं बटालियन का मुख्यालय था. दोनों सीधे वहीं पहुंचे. बटालियन का मुख्य द्वार बंद था. काफ़ी देर बहस करने के बावजूद संतरी ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी. तब वी बी सिंह ने ज़िला मुख्यालय आकर मुझे बताने का फ़ैसला किया. जितना कुछ आगे टुकड़ों–टुकड़ों में बयान किए गए वृतांत से मैं समझ सका, उससे स्पष्ट हो गया था कि जो घटा है, वह बहुत ही भयानक है और दूसरे दिन गाजियाबाद जल सकता था. पिछले कई हफ्तों से बगल के ज़िले मेरठ में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे और उसकी लपटें ग़ाज़ियाबाद पहुंच रही थीं. मैंने सबसे पहले ज़िला मजिस्ट्रेट नसीम जैदी को फोन किया. वह सोने ही जा रहे थे. उन्हें जगने के लिए कहकर मैंने ज़िला मुख्यालय पर मौजूद अपने एडिशनल एसपी, कुछ डिप्टी एसपी और मजिस्ट्रेटों को जगाया और तैयार होने के लिए कहा. अगले चालीस–पैंतालिस मिनटों में सात–आठ वाहनों में लदे–फंदे हम मकनपुर गांव की तरफ़ लपके. नहर की पुलिया से थोड़ा पहले हमारी गाड़ियां खड़ी हो गईं. नहर के दूसरी तरफ़ थोड़ी दूर पर ही मकनपुर गांव की आबादी थी, लेकिन तब तक कोई गांव वाला वहां नहीं पहुंचा था. लगता था कि दहशत ने उन्हें घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया था. थाना लिंक रोड के कुछ पुलिसकर्मी ज़रूर वहां पहुंच गए थे. उनकी टार्चों की रोशनी के कमज़ोर वृत्त नहर के किनारे उगी घनी झाड़ियों पर पड़ रहे थे, पर उनसे साफ़ देख पाना मुश्किल था. मैंने गाड़ियों के ड्राइवरों से नहर की तरफ़ रुख़ करके अपनी हेडलाइट्स ऑन करने के लिए कहा. लगभग सौ गज चौड़ा इलाक़ा प्रकाश से नहा उठा. उस रोशनी में मैंने जो कुछ देखा, वह वही दु:स्वप्न था, जिसका ज़िक्र मैंने शुरू में किया है.

गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनियां झाड़ियों से टकरा कर टूट-टूट जा रही थीं, इसलिए टार्चों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था. झाड़ियों और नहरों के किनारे ख़ून के थक्के अभी पूरी तरह से जमे नहीं थे, उनमें से ख़ून रिस रहा था. पटरी पर बेतरतीबी से शव पड़े थे, कुछ पूरे झाड़ियों में फंसे तो कुछ आधे तिहाई पानी में डूबे. शवों की गिनती करने या निकालने से ज़्यादा ज़रूरी मुझे इस बात की पड़ताल करना लगा कि उनमें से कोई जीवित तो नहीं है.

गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनियां झाड़ियों से टकरा कर टूट–टूट जा रही थीं, इसलिए टार्चों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था. झाड़ियों और नहरों के किनारे ख़ून के थक्के अभी पूरी तरह से जमे नहीं थे, उनमें से ख़ून रिस रहा था. पटरी पर बेतरतीबी से शव पड़े थे, कुछ पूरे झाड़ियों में फंसे तो कुछ आधे तिहाई पानी में डूबे. शवों की गिनती करने या निकालने से ज़्यादा ज़रूरी मुझे इस बात की पड़ताल करना लगा कि उनमें से कोई जीवित तो नहीं है. सबने अलग–अलग दिशाओं में टार्चों की रोशनियां फेंक–फेंक कर अंदाज़ लगाने की कोशिश की कि कोई जीवित है या नहीं. बीच–बीच में हम हांक भी लगाते रहे कि यदि कोई जीवित हो तो उत्तर दे, हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं, उसे अस्पताल ले जाएंगे, पर कोई जवाब नहीं मिला. निराश होकर हममें से कुछ पुलिया पर बैठ गए. मैंने और ज़िलाधिकारी ने तय किया कि समय खोने से कोई लाभ नहीं है. हमें दूसरे दिन की रणनीति बनानी थी, इसलिए जूनियर अधिकारियों को शवों को निकालने और ज़रूरी लिखा–पढ़ी करने के लिए कहकर हम लिंक रोड थाने के लिए मुड़े ही थे कि नहर की तरफ़ से खांसने की आवाज़ सुनाई दी. सभी ठिठक कर रुक गए. मैं वापस नहर की तरफ़ लपका. फिर मौन छा गया. स्पष्ट था कि कोई जीवित था, लेकिन उसे यक़ीन नहीं था कि जो लोग उसे तलाश रहे हैं, वे मित्र हैं. हमने फिर आवाज़ें लगानी शुरू कीं, टार्च की रोशनी अलग–अलग शरीरों पर डालीं और अंत में हरकत करते हुए एक शरीर पर हमारी नज़रें टिक गईं. कोई दोनों हाथों से झाड़ियां पकड़े आधा शरीर नहर में डुबोए इस तरह पड़ा था कि बिना ध्यान से देखे यह अंदाज़ लगाना मुश्किल था कि वह जीवित है या मृत! दहशत से बुरी तरह वह कांप रहा था और काफ़ी देर तक आश्वस्त करने के बाद यह विश्वास करने वाला कि हम उसे मारने नहीं बचाने वाले हैं, जो व्यक्ति अगले कुछ घंटे हमें इस लोमहर्षक घटना की जानकारी देने वाला था, उसका नाम बाबूदीन था. गोली उसे छूते हुए निकल गई थी. भय से नि:श्चेष्ट होकर वह झाड़ियों में गिरा तो भाग–दौड़ में उसके हत्यारों को यह जांचने का मौक़ा नहीं मिला कि वह जीवित है या मर गया. दम साधे वह आधा झाड़ियों और आधा पानी में पड़ा रहा और इस तरह मौत के मुंह से वापस लौट आया. उसे कोई ख़ास चोट नहीं आई थी और नहर से चलकर वह गाड़ियों तक आया. बीच में पुलिया पर बैठकर थोड़ी देर सुस्ताया भी.

लगभग 21 वर्षों बाद जब हाशिमपुरा पर एक किताब लिखने के लिए सामग्री इकट्ठा करते समय मेरी उससे मुलाक़ात हुई, जहां पीएसी उसे उठा कर ले गई थी तो उसे याद था कि हमने पुलिया पर बैठे किसी सिपाही से मांगकर उसे बीड़ी दी थी. बाबूदीन ने जो बताया, उसके अनुसार उस दिन अपरान्ह तलाशियों के दौरान पीएसी के एक ट्रक पर बैठाकर चालीस–पचास लोगों को ले जाया गया तो उन्होंने समझा कि उन्हें गिरफ़्तार कर किसी थाने या जेल ले जाया जा रहा है. मकनपुर पहुंचने के लगभग पौन घंटा पहले एक नहर पर ट्रक को मुख्य सड़क से उतार कर नहर की पटरी पर कुछ दूर ले जाकर रोक दिया गया. पीएसी के जवान कूदकर नीचे उतर गए और उन्होंने ट्रक पर सवार लोगों को नीचे उतरने का आदेश दिया. अभी आधे लोग ही उतरे थे कि पीएसी वालों ने उन पर फायर करना शुरू कर दिया. गोलियां चलते ही ऊपर वाले गाड़ी में ही दुबक गए. बाबूदीन भी उनमें से एक था. बाहर उतरे लोगों का क्या हुआ, वह सिर्फ़ अनुमान ही लगा सकता था. शायद फायरिंग की आवाज़ आसपास के गांवों में पहुंची, जिसके कारण आसपास से शोर सुनाई देने लगा और पीएसी वाले वापस ट्रक में चढ़ गए. ट्रक तेज़ी से बैक हुआ और वापस ग़ाज़ियाबाद की तरफ़ भागा. यहां वह मकनपुर वाली नहर पर आया और एक बार फिर सबसे उतरने के लिए कहा गया. इस बार डर कर ऊपर दुबके लोगों ने उतरने से इंकार कर दिया तो उन्हें खींच–खींचकर नीचे घसीटा गया. जो नीचे आ गए, उन्हें पहले की तरह गोली मारकर नहर में फेंक दिया गया और जो डर कर ऊपर दुबके रहे, उन्हें ऊपर ही गोली मारकर नीचे ढकेला गया. बाबूदीन जब यह विवरण बता रहा था तो हमने पहले घटनास्थल का अंदाज़ लगाने की कोशिश की. किसी ने सुझाव दिया कि पहला घटनास्थल मेरठ से ग़ाज़ियाबाद आते समय रास्ते में मुरादनगर थाने में पड़ने वाली नहर हो सकती है. मैंने लिंक रोड थाने के वायरलेस सेट से मुरादनगर थाने को कॉल किया तो स्पष्ट हुआ कि हमारा सोचना सही था. कुछ देर पहले ही मुरादनगर थाने को भी ऐसी ही स्थिति से गुज़रना पड़ा था. वहां भी कई शव नहर में पड़े मिले थे और कुछ लोग जीवित थाने लाए गए थे.

इसके बाद की कथा एक लंबा और यातनादायक प्रतीक्षा का वृतांत है, जिसमें भारतीय राज्य और अल्पसंख्यकों के रिश्ते, पुलिस का ग़ैर पेशेवराना रवैया और घिसट–घिसट कर चलने वाली उबाऊ न्यायिक प्रणाली जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं. मैंने 22 मई, 1987 को जो मुक़दमे ग़ाज़ियाबाद के थाना लिंक रोड और मुरादनगर पर दर्ज कराए थे, वे पिछले 21 वर्षों से विभिन्न बाधाओं से टकराते हुए अभी भी अदालत में चल रहे हैं और अपनी तार्किक परिणति की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

दंगाइयों ने घरों में आग लगा दी, लोगों को ज़िंदा जला दिया, औरतों को तलवार से काटा गया, बच्चों को भी आग में फेंक दिया गया. आलम यह था कि लोगों को दफ़नाने के लिए जगह कम पड़ गई.

ज़ख़्म आज भी ताज़ा हैं...

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में

सभी फोटो-***प्रभात पाण्डेय***

फ़िरदौस ख़ान

वक़्त बदला, हालात बदले, लेकिन नहीं बदली तो, ज़िंदगी की दुश्वारियां नहीं बदलीं. आंसुओं का सैलाब नहीं थमा, अपनों के घर लौटने के इंतज़ार में पथराई आंखों की पलकें नहीं झपकीं, अपनों से बिछड़ने की तकलीफ़ से बेहाल दिल को क़रार न मिला. यही है मेरठ के दंगा पीड़ितों की दास्तां. मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई, 1987 और मलियाना गांव में 23 मई, 1987 को हैवानियत का जो नंगा नाच हुआ, उसके निशान आज भी यहां देखे जा सकते हैं. इन दंगों ने यहां के बाशिंदों की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया. औरतों से उनका सुहाग छिन गया. बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया. कई घरों के चिराग़ बुझ गए. दंगाइयों ने घरों में आग लगा दी, लोगों को ज़िंदा जला दिया, औरतों को तलवार से काटा गया, बच्चों को भी आग में फेंक दिया गया. आलम यह था कि लोगों को दफ़नाने के लिए जगह कम पड़ गई. यहां के क़ब्रिस्तान की एक-एक क़ब्र में तीन-तीन लोगों को दफ़नाया गया. मरने वाले ज़्यादा थे और मातम करने वाले कम. जो ज़िंदा बचे, वे भी ज़िंदा लाश बनकर रह गए. बरसों तक कानों में अपनों के चीख़ने-चिल्लाने की आवाज़ें गूंजती रहीं. इंसानों से आबाद एक पूरी बस्ती श्मशान में बदल चुकी थी, जहां सिर्फ़ आगज़नी और तबाही का ही मंज़र था.

मलियाना के मोहम्मद यूनुस अपने भाई महमूद का खंडहर हो चुका मकान दिखाते हुए कहते हैं कि कभी यहां एक ख़ुशहाल परिवार रहता था, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, लेकिन आज सिर्फ़ वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है. 23 मई को दंगाइयों ने इस घर को आग लगा दी थी. इस आग में उनके भाई महमूद, भाभी नसीम और चार बच्चे आरिफ़, वारिस, आफ़ताब और मुस्कान जलकर मर गए. जब मकान से लाशें निकाली गईं तो उनके भाई और भाभी ने अपने बच्चों को सीने से लगाया हुआ था. इस मंज़र को देखकर रूह तक कांप उठी. बाद में इन लाशों को इसी तरह ही दफ़ना दिया गया. इस हादसे में उनकी भतीजी तरन्नुम बच गई, जो उस वक़्त अपनी नानी के घर गई हुई थी.

बेटे दिलशाद का नाम आते ही अली हसन की आंखें भर आती हैं. वह बताते हैं कि उस वक़्त दिलशाद की उम्र आठ साल थी. दंगाइयों ने पहले तो पैर पकड़ कर उसे ज़मीन पर पटक़-पटक़ कर मारा, फिर उसके बाद जलते हुए रिक्शे पर फेंक दिया. वह ज़िंदा जलकर मर गया. दंगाइयों ने उसके घर के चिराग़ को हमेशा के लिए बुझा दिया. मेराज ने बताया कि दंगाइयों ने उनके पिता मोहम्मद अशरफ़ की गर्दन में गोली मारी और उन्होंने मौक़े पर ही दम तोड़ दिया. यामीन बताते हैं कि दंगाइयों ने उनके वालिद मोहम्मद अकबर को पहले तो बुरी तरह पीटा, बाद में उन्हें ज़िंदा जला दिया गया.

महमूदन बताती हैं कि दंगाइयों ने उनके घर में आग लगा दी थी, जिसमें उनके ससुर अब्दुल रशीद और सास इदिया की जलकर मौत हो गई. आग इतनी भयानक थी कि उनके सास-ससुर की लाशें तक नहीं मिली. उनके शौहर नवाब अपने भाई साबिर, मुज़फ़्फ़र के साथ किसी दूसरे घर में गए हुए थे. वह अपनी ननदों शबाना एवं बानो और बच्चों रहीसुद्दीन, रईसा एवं शहाबुद्दीन को लेकर पहले ही घर से निकल कर वहां आ चुकी थीं, जहां गांव के लोग इकट्ठा थे. यहां उन्होंने कई-कई दिनों तक फ़ाक़े किए. इस हादसे के बाद वह परिवार समेत अपने मायके शैदपुर चली गईं. कुछ वक़्त बाद उनके शौहर मलियाना आए और एक अदद छत का जुगाड़ किया.

रज़िया बताती हैं कि उस वक़्त उनकी शादी हुई थी. घर में अच्छी ख़ासी रौनक़ थी, लेकिन दंगाइयों ने उस ख़ुशी के माहौल को मातम में बदल दिया. दंगाइयों ने पहले तो घर में लूटपाट की, फिर आग लगा दी. उनके ससुर अल्ला राज़ी को बुरी तरह पीटा गया. उनका परिवार इस हादसे से अभी तक उबर नहीं पाया है. शकीला रोते हुए कहती हैं कि दंगाइयों ने उनके शौहर अशरफ़ को गोली मारकर उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह कर डाली. अगर दंगाइयों ने उन्हें भी मार दिया होता तो अच्छा होता. जन्नत बताती हैं कि दंगाइयों ने उनके घर में भी आग लगा दी थी, किसी तरह उन्होंने भागकर जान बचाई. आठ दिनों बाद जब उनका परिवार घर लौटा तो देखा कि राख अब भी गरम थी. गर्भवती कनीज़ को तलवार से काट डाला गया. इसी तरह शहाना के पेट को भी तलवार से काट दिया. उसकी आंतें बाहर आ गईं और वह अपनी आंतों को हाथ में लेकर बदहवास दौड़ पड़ी. इस हादसे के बाद उसने गांव ही छोड़ दिया. भूरा की भांजी के पैर में गोली मारी गई.

बिजली के सामान की मरम्मत करने वाले हशमत अली अपने जख्म दिखाते हुए कहते हैं कि पीएसी के जवानों ने उनके घर की तलाशी ली थी और इसमें उन्हें पेचकस मिला. इस पर उन्हें बेरहमी से पीटा गया. उनकी टांग तोड़ दी गई. वकील अहमद के जिस्म पर भी गोलियों के निशान हैं. वह बताते हैं कि उनके पेट पर दो गोलियां मारी गईं, जिससे उनकी एक किडनी ख़राब हो गई. मोहम्मद रज़ा बताते हैं कि पीएसी के जवानों ने एक गोली से दो लोगों की हत्या तक की. नसीर अहमद के सिर में गोली मारी गई, जो उनके पीछे खड़े एक दूसरे व्यक्ति की गर्दन में लग गई और दोनों ने मौक़े पर ही दम तोड़ दिया. नौशाद बताते हैं कि उस वक़्त वह छोटे थे. दंगाइयों का क़हर देखकर उनका दिल दहल उठा था. वह दहशत आज भी उनके दिल पर तारी है. आज भी जब उन दंगों का ज़िक्र आता है, ऐसा लगता है जैसे यह कल का ही वाक़िया हो.

हाशिमपुरा की नसीम बानो का कहना है कि उनका एक ही भाई था सिराज अहमद. पीएसी के जवान उसे उठाकर ले गए और गंग नहर के किनारे उसे गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया. कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी. घर के चश्मो-चिराग़ की मौत के बाद उनके वालिद शब्बीर अहमद बुरी तरह टूट गए और वालिदा रशके जहां की दिमाग़ी हालत ख़राब हो गई. इस दर्दनाक हादसे के 10 साल बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन आख़िरी सांस तक उन्होंने अपने बेटे का इंतज़ार किया. उन्हें इस बात पर कभी यक़ीन नहीं आया कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है. उनकी दो बहनें अपनी ससुराल में हैं, जबकि वह और उनकी एक बहन फ़ातिमा तलाक़शुदा हैं. वह कहती हैं कि भाई की मौत ने पूरे ख़ानदान को बिखेर दिया. आज उनका भाई ज़िंदा होता तो उनकी ज़िंदगी ही कुछ और होती. हाजिरा के बेटे नईम और पीरो के बेटे निज़ामुद्दीन को भी पीएसी के जवान उठाकर ले गए थे और उन्हें भी गोली मारकर नहर में फेंक दिया गया. ज़रीना तो आज भी उस ख़ौफ़नाक मंज़र को याद कर कांप उठती हैं, जब पीएसी के जवान उनके शौहर ज़हीर अहमद और बेटे जावेद अख्तर को घर से घसीटते हुए ले गए थे, बाद में दोनों की मौत की ख़बर ही मिली. अमीना के शौहर जैनुद्दीन और दो बेटों जमशेद अहमद और शमशाद अहमद को भी पीएसी के जवान जबरन घसीटते हुए ले गए. उनके बेटों को गोली मारकर नहर के हवाले कर दिया गया और शौहर को जेल भेज दिया गया. सवा महीने बाद जैनुद्दीन घर लौटे तो उनके जख्म पुलिस की हैवानियत बयां कर रहे थे. उन पर इस क़द्र ज़ुल्म ढहाए गए कि उनके हाथ-पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए. अब वह अपाहिज जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. अमीना भी बेटों के ग़म में इस क़द्र हल्कान हो चुकी हैं कि वह अपने पैरों पर चल तक नहीं पातीं. रफ़ीकन बताती हैं कि पीएसी के जवानों ने उनके शौहर हतीमुद्दीन को बुरी तरह पीटा और बेटे अलाउद्दीन को नहर किनारे ले जाकर गोली मार दी और उसकी लाश भी नदी में फेंक दी.

औरतें ही नहीं, बुज़ुर्ग भी अपनी औलादों को याद कर ख़ून के आंसू बहा रहे हैं. जमालुद्दीन के बेटे कमरुद्दीन को भी दो गोलियां मारी गईं. पहले वह अपने बेटे के साथ मिलकर कैंचियों का कारख़ाना चलाते थे. उनका बेटा ही नहीं, बल्कि कारोबार भी दंगे की भेंट चढ़ गया. अब वह एक छोटी सी परचून की दुकान के सहारे दो वक़्त की रोटी जुटा पा रहे हैं. शाहिद अंसारी के वालिद इलाही अंसारी भी मेरठ दंगों में मारे गए और वह अनाथ हो गए. मौत के मुंह से बचकर आए ज़ुल्फ़िक़ार बताते हैं कि पीएसी ने उन्हें भी गोली मारकर नहर में फेंक दिया था, लेकिन वह किसी तरह बचकर आ गए. वह बताते हैं कि पीएसी के चंगुल से बचे लोगों के हाथ-पैर तोड़ दिए गए. वे खाने-कमाने लायक़ नहीं रहे. मोहम्मद यामीन बताते हैं कि उनसे पीएसी के जवानों ने पूछा कि कहां रहते हो और इलाक़े का नाम बताते ही उन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई. अब्दुल हमीद का भी सिर फोड़ दिया गया. उनके ज़ख़्मों के निशान आज भी उनके दर्द को बयां कर रहे हैं. शकील का कहना है कि जब पीएसी के जवान उसके भाई नईम को उठाकर ले जा रहे थे, तब वह उनके पैरों से लिपट गया था, लेकिन एक मासूम बच्चे के आंसू भी उन्हें नहीं रोक पाए. उसका कहना है कि इस हादसे के बाद इलाक़े में सिर्फ़ औरतें और बच्चे ही बचे थे. कई-कई दिनों तक उन्हें रोटी का एक निवाला तक नसीब नहीं होता था. बच्चे इसी आस में दिन भर सड़क के चक्कर लगाते थे कि कहीं से कोई गाड़ी आ जाए और उन्हें राशन दे दे. प्रशासनिक सहायता भी नाममात्र की ही थी. कभी-कभार ही सरकारी नुमाइंदे आते और उन्हें दाल-चावल और आटा दे जाते थे. उसके सहारे भला कितने दिन पेट भर पाता.

firdaus@chauthiduniya.com

अब छत छिनने का ख़ौफ़

मलियाना की दंगा पीड़ित महिलाएं आज भी बेहद बुरे दौर से गुज़र रही हैं. उनका कहना है कि पहले उनके घर को फूंका गया, परिजनों की हत्याएं की गईं और अब उनसे उनकी छत भी छीनने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में वे भला कहां जाएं, गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने को तैयार नहीं है. पिछले कई माह से नसरीन का रो-रोकर बुरा हाल है. वह बताती हैं कि पुलिसकर्मी दंगे के गवाह उनके जेठ माशाअल्लाह को उठाकर ले गए और उन्हें पीट-पीटकर जान से मार दिया. बाद में उन्हें मुआवज़े के तौर पर 20 हज़ार रुपये दिए गए. उन्होंने हकीमुद्दीन से 22 हज़ार रुपये में मकान ख़रीदा और वे बरसों से इसमें रह रहे हैं. इस मकान का बैनामा नहीं हुआ था. इसी बात का फ़ायदा उठाकर हकीमुद्दीन के बेटे रईसुद्दीन ने अब यह मकान किसी और को बेच दिया है. उन पर मकान ख़ाली करने का दबाव बनाया जा रहा है. ऐसे में वह अपने चार बच्चों को लेकर कहां जाएं. उनके पति मुज़फ़्फ़र मेहनत-मज़दूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हैं. पिछले काफ़ी वक़्त से वह और उनके पति बीमार हैं. घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं और अब गांव के प्रभावशाली लोग उनकी छत भी छीनना चाहते हैं. इसी तरह अनीसा रोते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपनी 50 गज़ ज़मीन की बुनियाद भरवाई थी, लेकिन उस पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने क़ब्ज़ा कर लिया है. अपने बच्चों को लेकर वह कहां जाएं, कौन उनकी फ़रियाद सुनेगा.

बाक़ी दंगों की तरह इन दंगों में धारदार हथियारों और आगज़नी का सहारा लिया गया. याद रखने वाली बात है कि कानपुर के दंगों में गणेश शंकर विद्यार्थी सरीखे बड़े नेता का क़त्ल चाक़ू मारकर किया गया था.

25 साल

मेरठ दंगा

दंगों के इतिहास में
हाशिमपुरा-मलियाना

फोटो-प्रभात पाण्डेय

- पहला हिंदू-मुस्लिम दंगा 1809 में बनारस में हुआ
- दंगों में पुलिस बनती है हिंदू फोर्स
- उत्तर प्रदेश में पीएसी दंगाइयों के साथ

भारतीय सामाजिक संरचना में धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं माना जाता है, लेकिन ये सारी बातें ज़रा क़ानूनी, आधिकारिक और आदर्शवादी लगती हैं, क्योंकि इसके विपरीत ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत में कई भारत हैं. अलग-अलग धर्म ऊपर से तो एक ही समाज और एक ही देश के घटक नज़र आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चेतना की निचली परतों में आपसी मनमुटाव और दुश्मनी ज़रूर है, जो कि सामान्यतः दबी रहती है, पर असामान्य परिस्थितियों में सतह पर निकल आती है. सरकार वैसे तो देश के हर धर्म को समान भाव से देखने के लिए बनी है, लेकिन देश के लोग ही नेता और अफसर होते हैं, इसलिए भारत में सरकारें शासन-सत्ता की ही प्रतीक नहीं होतीं, वे हिंदू और मुसलमान भी होती हैं. भारत ऐसा देश है, जहां अधिकारी-कर्मचारी सिर्फ़ प्रशासक नहीं होते, बल्कि हिंदू या मुसलमान भारत के प्रतीक भी होते हैं. धार्मिक पहचान ही प्राथमिक पहचान है भारत की और यही इसके भाग्य की सबसे बड़ी विडंबना भी है.

> **मायावती ने भी पूर्ववती नेताओं की तरह मुसलमानों की अनदेखी कर दी. सबसे बड़ी बात यह है कि मलियाना और हाशिमपुरा के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला. तबसे अब तक कई सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. सबसे बड़ी बात है कि यह दंगा भारत की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस की सरकार की नाक के नीचे हुआ. उस समय कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या हुआ?**

सिद्धार्थ राय

भारतीय राजनीति में भ्रष्ट और पाक-साफ़ में फ़र्क़ नहीं है. भारत के नेताओं में मूढ़ और दूरदर्शी का फ़र्क़ नहीं है. भारत की सरकारों में सुशासक और कुशासक का भी फ़र्क़ नहीं है. फ़र्क़ सिर्फ़ एक है और यही फ़र्क़ प्राथमिक है और पार्टियों को परिभाषित करता है. भाजपा सांप्रदायिक है, संघ सांप्रदायिक है और कांग्रेस, बहुजन समाज और पिछड़ी जातियों की पार्टियां और वामपंथी पार्टियां ग़ैर सांप्रदायिक. लेकिन क्या यह फ़र्क़ सही मायने में किया जा सकता है? मेरठ के अंतर्गत मलियाना और हाशिमपुरा, जहां आज से 24 साल पहले 1987 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इन सवालों केजवाब देते हैं.

आधुनिक भारत का सबसे पहला सांप्रदायिक दंगा 1809 में बनारस में हुआ था. इसका कारण ईदगाह और हनुमान टीले के बीच ज़मीन का झगड़ा था. सरकारी अभिलेखों के अनुसार, आधुनिक भारत में यह पहला मौक़ा था, जब हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर एक-दूसरे से उलझे थे. उसके बाद तो दंगों की झड़ी ही लग गई. अंग्रेज़ शासन और मज़बूत होता चला गया और भारत पर राज करने का सबसे आसान तरीक़ा था उसे तोड़ देना. उन्होंने वही किया भी. *हम 1857 की लड़ाई को आज़ादी की सबसे पहली जंग मानते हैं, लेकिन तब भी भारत एक साथ नहीं था. सरकारी अभिलेख बताते हैं कि जब मेरठ के जवान दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली की हिंदू जनता ने बहादुर शाह ज़फर से शिक़ायत की कि ये जवान हिंदुओं की दुकानों को लूट रहे हैं. आपस की बातचीत बताती है कि दिल्ली की हिंदू जनता इस क्रांति को भगवान का प्रकोप मानती थी और मुस्लिम शासन से जोड़ती थी.*

फिर आया 1931 का कानपुर दंगा, जिसे गुजरात दंगों से पहले आधुनिक भारत का सबसे बड़ा दंगा माना जाता है. चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में सांप्रदायिक दंगे एक ही तरीक़े से होते हैं. एक ही तरीक़े के मुद्दों से झगड़ा शुरू होता है और एक ही तरीक़े से लोगों को मारा जाता है और एक ही तरीक़े के लोग दंगों में शामिल होते हैं. *मेरठ दंगों को भारत के दूसरे दंगों के साथ देखा जाए तो एक पैटर्न निकल कर आता है. मेरठ दंगों की शुरुआत हुई थी स्वर्गीय राजीव गांधी के आदेश पर हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि का ताला खोलने से.* मुसलमान जनता भड़क गई और हिंदू भी पीछे नहीं रहे. दंगा भड़क गया. दोनों ही ओर से लोगों की जानें गईं. लेकिन मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले और मलियाना गांव में जो हुआ, उसने लोगों का दिल दहला दिया. यहां बड़े पैमाने पर जान-माल का नुक़सान तो हुआ ही, साथ ही भारत का आइडिया भी चकनाचूर हो गया.

हाशिमपुरा में 22 मई, 1987 की रात पीएसी के जवानों ने 50 मुसलमानों को गिरफ़्तार किया और पास ही एक पीपल के पेड़ केपास ले जाकर कतार में खड़ा कर दिया. उसमें से बच्चों और बूढ़ों को अलग कर उन्हें जाने दिया गया. शेष 42 मुसलमान युवकों को पास ही गुलमर्ग सिनेमाहाल पर खड़े पीएसी के ट्रक में बैठाकर थाने ले जाने के लिए रवाना किया गया, लेकिन *थाने के बजाय पीएसी के जवान उस ट्रक को प्लाटून कमांडर सुरिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में दिल्ली-मेरठ हाइवे पर ले गए और वहां गंग नहर के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे सभी को उतारा और फिर कतार में खड़ा करके उन्हें गोली मार दी गई और उनकी लाशें नहर में बहा दी गईं.* कुछ युवकों ने शोर मचाया और ट्रक से नहीं उतरे. उन्हें फिर माकनपुर गांव के नज़दीक हिंडन नहर के पास उतार कर गोली मारी गई और उनकी लाशें नहर में फेंक दी गईं. इनमें से केवल पांच लोग बच पाए, जिन्हें पीएसी के जवानों ने गोली मारने के बाद मरा समझ कर छोड़ दिया था. यही वहां से जान बचाकर भाग पाए और यह लोमहर्षक घटना जनता के सामने आई.

मलियाना गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ. मलियाना में एक छोटा सा इलाक़ा है, जो मुसलमानों का है. यह मुसलमान आबादी हिंदू बाहुल्य इलाक़ों से घिरी हुई है. यहां मुसलमान शेख और बनिया हिंदू ज़मींदार थे, जिनके खेतों पर दलित वर्ग के लोग काम करते थे. दंगों के दौरान एक स्थानीय बनिया नेता ने दलितों को उकसाया और मुसलमानों को काट दिया गया. एक बार फिर से पीएसी तैनात की गई. घटना के चश्मदीद मुस्लिम बताते हैं कि रात को उनके सामने ही शराब का ठेका पीएसी ने दंगाइयों से लुटवा दिया और यह साफ़ हो गया कि कुछ होने वाला है. कुछ देर बाद ही दंगाइयों की भीड़ मलियाना के मुस्लिम इलाक़े पर टूट पड़ी और पीएसी के जवान उनके साथ ही थे. दंगाई लूटपाट करने लगे और पीएसी के जवानों ने एक ऊंची इमारत पर चढ़कर मुसलमानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी. 75 लोग मारे गए-बच्चे, बूढ़े और महिलाएं.

1931 के कानपुर दंगों को दंगों का मानक माना गया है. 1931 में कानपुर में दंगे इसलिए हुए थे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते शहर बंद का आह्वान किया था. शहर में अधिकतर कपड़े की दुकानें मुसलमानों की थीं और जब बंद काफी दिनों तक जारी रहा तो मुसलमानों को घाटा होने लगा. उन्होंने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दीं. इस पर कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां जाकर दुकानें बंद कराने की कोशिश करने लगे. पहले तू तू-मैं मैं हुई और फिर मारपीट. चूंकि कांग्रेसी हिंदू थे और कपड़ा व्यापारी मुसलमान, इस वजह से यह बात हिंदू बनाम मुसलमान बन गई और दंगा शुरू हो गया. मलियाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. *दरअसल, स्थानीय बनिया बिरादरी की मुसलमानों से प्रतिस्पर्धा थी. जब मेरठ शहर में दंगा भड़का तो बनिया बिरादरी को मौक़ा मिल गया. उन्होंने दंगाइयों की अगवानी तो की, लेकिन दंगाई थे कौन? ये दो तरीक़े के लोग थे. पहले थे दलित मज़दूर. बनिया बिरादरी ने ग़रीब दलितों को लूटपाट का लालच दिया, जिससे वे मुसलमानों के घर लूटने लगे.* दूसरे तरीक़े के दंगाई वे थे, जो शहर से आए थे. ये दंगाई कोई नए अभिनेता नहीं थे. याद रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ही बलिया ज़िले में हुए दंगों में यह बात निकल कर सामने आई थी कि पास के गाजीपुर ज़िले के लोग ही रात में बलिया जाकर दंगा करते और सुबह तड़के अपने खेतों को लौट आते थे. वही यहां भी हुआ. भारत में दंगों में अफवाहों का बहुत बड़ा हाथ होता है. अफवाह फैली कि मलियाना में बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया. एक और बात ध्यान देने योग्य है कि *दंगों से पहले शराब का ठेका क्यों लुटा? कानपुर में भी पता चला था कि दंगा भड़काने में एक बड़ी भूमिका चोर-उचक्कों, गुंडों-मवालियों ने निभाई थी. ऐसा उन्होंने लूट की मंशा से किया था. वही मलियाना में भी हुआ, इसीलिए गुंडों और चोरों ने सबसे पहले शराब लूटी.*

बाक़ी दंगों की तरह इन दंगों में धारदार हथियारों और आगजनी का सहारा लिया गया. याद रखने वाली बात है कि कानपुर के दंगों में गणेश शंकर विद्यार्थी सरीखे बड़े नेता का क़त्ल चाकू मारकर किया गया था. मलियाना में चाकू और तलवार का प्रयोग हुआ. एक महिला का पेट चीर दिया गया और एक बच्चे को पैर पकड़ कर आग में झोंक दिया गया. एक ही परिवार के 11 और 6 लोगों को घरों में आग लगाकर ज़िंदा फूंक दिया गया. *मलियाना और हाशिमपुरा में एक बात जो समान थी, वह थी पुलिस-प्रशासन की दंगाइयों के साथ मिलीभगत. असल में देखा जाए तो भारत में आज़ादी के पहले से ही प्रशासन, ख़ासकर पुलिस एक हिंदू फोर्स की तरह काम करती है.* मलियाना या हाशिमपुरा में कोई नई बात नहीं हुई थी. 1931 में कानपुर में भी पुलिस ने मुसलमानों पर हर तरह के ज़ुल्म ढाए थे. इन दंगों पर बैठी जांच कमेटी ने नोट किया था कि पुलिस ने हिंदू पुलिस और हिंदू दंगाइयों की तरह काम किया था. इस कमेटी ने पोस्टमार्टम के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आम लोगों ने तो धारदार हथियार प्रयोग किए थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे, जो पुलिस की गोली से मरे थे, क्योंकि *पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नहीं, बल्कि जान से मारने की मंशा से गोलियां चलाई थीं. पुलिस की गोलीबारी में मरने वाले अधिकांश लोगों के शरीर में कमर से ऊपर ज़ख्म थे. मलियाना में भी चश्मदीद बताते हैं कि अधिकतर लोग कमर के ऊपर ही लगी गोलियों से मरे. गोलियां अधिकतर सीने और सिर में लगी थीं.* समझने की बात यह है कि पुलिस फ़ोर्स हिंदू बाहुल्य है, आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ही. वैसे भी पीएसी के इतिहास में जाएं तो आज़ाद भारत में इस पुलिस बल ने दंगों में बहुत नकारात्मक भूमिका निभाई है. कानपुर में कुछ साल पहले हुए दंगों में भी यह देखा गया कि पीएसी ने सबक सिखाने की नीयत से कई मुस्लिम इलाक़ों में गोलीबारी की और मुसलमानों को घरों से बाहर घसीट कर मारा-पीटा. उत्तर प्रदेश में तो यह संस्कृति बन गई है कि जब भी कहीं दंगे होते हैं तो हिंदू दंगाई पीएसी के आने का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके साथ मिलकर दंगा करते हैं.

मलियाना में मुसलमानों के प्रति सरकार का सौतेला रवैया साफ़ दिखता है. *मुस्लिम मोहल्ले में भीषण गंदगी है, सड़कें टूटी हैं और बिजली के तार यहां-वहां लटके हैं. जैसे ही आप मलियाना की ईदगाह से आगे बढ़ते हैं, साफ-सफाई और कंक्रीट की पक्की सड़कें आपका स्वागत करती हैं. हिंदू बनिया समुदाय और दलितों के रहन-सहन से आप उनकी समृद्धि का अंदाज़ लगा सकते हैं. मुसलमान बच्चे नंगे और फटी बनियान पहन कर घूमते दिखते हैं. मलियाना अंबेडकर ग्राम तो बन गया, लेकिन वहां के मुसलमान दोयम दर्जे की ज़िंदगी जी रहे हैं.* मायावती ने भी पूर्ववती नेताओं की तरह मुसलमानों की अनदेखी कर दी. सबसे बड़ी बात यह है कि मलियाना और हाशिमपुरा के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला. तबसे अब तक कई सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. सबसे बड़ी बात है कि यह दंगा भारत की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस की सरकार की नाक के नीचे हुआ. उस समय कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या हुआ? *तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह ने तो कहा कि केवल 10 मुसलमानों की ही मौत हुई. जबकि इन दोनों जगहों पर लगभग 150 मुसलमान मारे गए. मलियाना का तो हाल यह है कि वहां की घटना की प्राथमिकी (एफआईआर) तक अदालत के रिकार्ड से ग़ायब हो चुकी है.* मलियाना और हाशिमपुरा के लोग बताते हैं कि उनसे मिलने और न्याय दिलाने के लिए राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वी पी सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह एवं कल्याण सिंह सरीखे बड़े-बड़े नेता आए, लेकिन उनके सारे वादे केवल वोटों की राजनीति तक सीमित रहे.

अब कौन धर्मनिरपेक्ष है और कौन नहीं, कहना मुश्किल है. जो अपने को धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों का मसीहा बताते थे, उन्हीं की नाक के नीचे यह बर्बर कत्लेआम हुआ. दंगों में दंगाई थे. ये संघी और कांग्रेसी दोनों ही रहे होंगे, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, चाहे किसी की भी हो. तो फिर आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? आज पच्चीसवें साल में भी न्याय अधर में है. बच्चे जवान हो गए हैं, युवक बूढ़े हो गए हैं, लेकिन न्याय सरकारी फाइलों और अदालत की पेशियों में उलझ कर रह गया है. भारतीय संविधान ख़ुद को धर्मनिरपेक्ष बताता है या नहीं, यह इन दंगा पीड़ितों के लिए मायने नहीं रखता. उनका अपना भारत है, जो मुसलमान विरोधी है और प्रताड़ना से भरा हुआ है.

siddhartha@chauthiduniya.com

जनपद चित्रकूट मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ के किनारे बसा-तरांव गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है.

वादों का मारा बुंदेलखंड

सुरेंद्र अग्निहोत्री

बुंदेलखंड में चित्रकूट के घाट पर न तो संतों की भीड़ है और न चंदन घिसने के लिए तुलसीदास जी हैं. हां, बुंदेलखंड की व्यथा सुनने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ज़रूर बांदा आए. उन्होंने पानी की सुविधा के लिए दो सौ करोड़ रुपये देने का वादा करके आंसू पोंछने की कोशिश की है, लेकिन यहां की जनता के दु:ख-दर्द दूर होते नज़र नहीं आ रहे हैं. रो-रोकर अपना हाल बताने वालों में भूख एवं क़र्ज़ से मरे हुए किसानों के परिवारीजन थे, पेंशन एवं राशन के लिए भटक रहे वृद्ध थे. रोज़गार गारंटी से धोखा खाए श्रमिक थे और दबंगों-दलालों की लाठी-बंदूक़ों के साये में जीने वाले ऐसे युवक भी थे, जिन्हें अपने और समाज के हक़ के लिए लिखापढ़ी करने के गुनाह में असरदारों ने पुलिस से साठगांठ कर जेल भिजवाया था. खेती ने पैसा तो सोख लिया, लेकिन खाने के लिए अनाज पैदा नहीं हो पाया. घर में भुखमरी की स्थिति बन गई. आजीविका के लिए साहूकारों से क़र्ज़ लेना पड़ा. पति चिंता में भूखे सोते थे. बच्चे भूख से तड़पते तो वे दु:खी होकर रात-रात भर रोते रह जाते थे. आत्महत्या मुक्ति का मार्ग बन गई. आंकड़े बताते हैं कि बीते वर्षों में आत्महत्या करने वाले लोगों में अधिकतर किसान ही थे, लेकिन सरकारी अधिकारी हमेशा झूठ बोलते रहे. बुंदेलखंड में ग़रीबी के कारण लोगों का जीना दुश्वार है. सूखा इस क्षेत्र की नियति बन गया है. पिछले पांच वर्षों से लगातार सूखे से जूझ रहे लोगों की हालत से लगता है कि परिस्थितियां धीरे-धीरे 19वीं सदी के भयंकर अकाल जैसी बनती जा रही हैं. मानसून ने बुंदेलखंड में अपने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं. ज़्यादातर किसान सूखे की मार झेल रहे हैं और सरकार मरहम लगाने के बजाय चाबुक चला रही है. सरकार जब तक जमीनी हक़ीक़त नहीं देखेगी, तब तक पानी का टोटा रहेगा. यहां के चेक डेम राजनेताओं की जेबें भर रहे हैं. इसीलिए करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद भी बुंदेलखंड में सूखा है और यहां का किसान भूखा है.

झांसी में बैंक का क़र्ज़ चुकता न कर पाने के सदमे में एक किसान ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. ख़बर पाकर ज़िला प्रशासन सक्रिय हुआ और अधिकारियों ने मृतक की पत्नी को आर्थिक मदद प्रदान की. थाना बड़ागांव क्षेत्र के ग्राम छपरा निवासी मातादीन अहिरवार का दत्तक पुत्र रामबाबू (42) किसान था. गढ़मऊ रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर उसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली. उसके भाई हरिमोहन ने बताया कि रामबाबू के पास 5 एकड़ कृषि भूमि थी, जिसे रहन रखकर उसने स्टेट बैंक से क़रीब 6 लाख रुपये का क़र्ज़ लाया था. इस बार उसने खेत में गेहूं बोया था, लेकिन पानी न मिलने के कारण अधिकांश फ़सल बर्बाद हो गई. वह दो-तीन महीने से सदमे में था. उसे बैंक के क़र्ज़ की चिंता सता रही थी. जबकि बांदा जनपद के नहरी गांव में ग़रीबी और क़र्ज़ के चलते हुई दो मौतों के संबंध में ज़िला प्रशासन का कहना है कि उन मामलों में आत्महत्या की वजह बीमारी और घरेलू कलह थी. मालूम हो कि 27 अप्रैल को नरैनी क्षेत्र के ग्राम नहरी निवासी जग प्रसाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. वहीं 29 अप्रैल को हीरामन पुत्र मनीराम की मौत हो गई. चित्रकूट से सटे बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश भाग के सतना ज़िले के ग्राम इटमा तीर में एक वृद्धा की भूख से मौत हो गई. सरपंच ओंकार प्रसाद शुक्ला ने वृद्धा केसकली की मौत भूख से होना बताया. केसकली निराश्रित थी और विगत चार महीनों से वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से परेशान थी. चार-पांच दिनों से उसे भोजन नसीब नहीं हुआ था. जालौन जनपद के हिम्मतपुर गांव के 65 वर्षीय अरविंद सिंह की कहानी किसी को भी द्रवित कर सकती है. अरविंद सिंह की दशा पहले इतनी दीन-हीन नहीं थी. दूसरों का भला करने के जुनून में वह इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने क़र्ज़ लेने से भी परहेज नहीं किया. सूदखोरों के चंगुल में फंसकर वह अपनी पूरी आठ बीघा ज़मीन गंवा बैठे. उनके पास न राशनकार्ड है और न उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है.

झांसी में बैंक का क़र्ज़ चुकता न कर पाने के सदमे में एक किसान ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. ख़बर पाकर ज़िला प्रशासन सक्रिय हुआ और अधिकारियों ने मृतक की पत्नी को आर्थिक मदद प्रदान की. थाना बड़ागांव क्षेत्र के ग्राम छपरा निवासी मातादीन अहिरवार का दत्तक पुत्र रामबाबू (42) किसान था. गढ़मऊ रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर उसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली.

किस विकास के खुल गए, यारों आज किवाड़
डरे-डरे हतप्रभ खड़े जंगल, नदी, पहाड़

अशोक अंजुम का उक्त दोहा बुंदेली धरा पर अक्षरश: चरितार्थ हो रहा है. सूखे कुएं, खाली तालाब और आधे-अधूरे बांध देखकर यहां के किसान बदहवास घूमते हैं. कुदरत के कहर और शासन की उपेक्षा ने उन्हें इस कदर बेबस कर दिया है कि वे जान से प्यारी अपनी भूमि को राम भरोसे छोड़कर दो जून की रोटी की तलाश में पलायन कर रहे हैं. जो कहीं नहीं जाना चाहते, उन्हें जीने के लिए रोज जंग लड़नी पड़ रही है. उन्हीं में चित्रकूट जनपद के विकास खंड मानिकपुर के बगरहा गांव निवासी कोल आदिवासी महिला केसकली है, जो विकलांग है और राशनकार्ड, पेंशन एवं आवास आदि सुविधाओं से वंचित है. 20 वर्ष पूर्व अपना पति खो चुकी केसकली के जीवन में दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा है. 14 माह पूर्व बड़े पुत्र झुल्ली को डाकू बताकर पुलिस ने मार गिराया. छोटा पुत्र पुलिस के डर से भाग गया है. डेढ़ बीघा भूमि लगातार चार वर्षों के सूखे के बाद बंजर पड़ी है. गांव में भीख मांगकर वह कब तक जिंदा रहेगी, कहना कठिन है. इसी जनपद में मइयादीन पुत्र महावीर ग्राम बनाड़ी का बाशिंदा है. भूख और क़र्ज़ की चिंता में भाई राम सुमेर की मृत्यु हो गई. इसके बाद उसकी भूमि की तीन बार नीलामी हुई. 24 अप्रैल, 2006 को 22 बीघा 5 बिस्वा ज़मीन की बोली मात्र 2 लाख 90 हज़ार रुपये लगाई गई. दूसरी बार 20 बीघा ज़मीन की बोली 7 लाख 56 हज़ार रुपये और फिर तीसरी बार 9 बीघा 9 बिस्वा की बोली 3 लाख 90 हज़ार रुपये लगी और वह नीलाम हो गई. मइयादीन ने बताया कि उसी दिन तहसीलदार कर्वी ने उसे ज़बरदस्ती 2 घंटे लॉकअप में बंद रखा. भूमि नीलाम होने के बावजूद बैंक से लगातार नोटिसें आती रहीं.

जनपद चित्रकूट मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ के किनारे बसा-तरांव गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है. वर्षा पर निर्भर होने के कारण कृषि व्यवस्था चौपट है. गांव में 50 प्रतिशत आबादी दलितों की है, जिनमें अधिकांश भूमिहीन हैं. जिनके पास भूमि है, वह भी ज़्यादा से ज़्यादा बीघा-दो बीघा. कंकरीली-पथरीली भूमि होने से कृषि कार्य ठीक से हो नहीं पाता. रोजगार के अवसर न होने के कारण प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं. वर्तमान में 55 परिवारों में से 100 लोग पलायन कर चुके हैं. तरांव की श्रीमती तुलसा, राजरानी, चिरइया, कुंवरसुती, उर्मिला, हीरामनी, कमला, सत्यनारायण, देबा एवं राममिलन आदि कहते हैं कि जब तक काम मिलता है, तब तक ही चूल्हा जलता है. अगर काम नहीं तो भोजन नहीं. हम लोगों ने सुना था कि रोज़गार गारंटी योजना के तहत सौ दिनों का काम मिलेगा और मज़दूरी का भुगतान एक सप्ताह या 15 दिनों के भीतर हो जाएगा, लेकिन हमारे गांव में तो इसका उल्टा हो रहा है. रोज़गार गारंटी योजना के तहत हम लोग भी काम करने गए तो प्रधान ने हमें खदेड़ दिया और कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम नहीं है. जब हमने कहा कि हमारे पास जॉबकार्ड है तो उन्होंने कहा कि जॉबकार्ड तो पूरे गांव के बने हैं, मैं सभी को काम पर नहीं लगा सकता. काम करना है तो राजस्थान, पंजाब और सूरत चले जाओ, यहां काम नहीं है. सत्य नारायण ने कहा कि रोज़गार गारंटी योजना के तहत तालाब के भीट पर वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रधान ने गड्ढे खुदवाए, लेकिन आधा दर्जन मज़दूरों को पैसा अभी तक नहीं मिला. प्रधान एवं सचिव कहते हैं कि अभी पैसा नहीं आया है. अब हम लोग भूखों मरने के कगार पर खड़े हैं और क़र्ज़ लेकर बाहर पलायन कर जाएंगे. समाजसेवी गोपाल भाई कहते हैं कि बुंदेलखंड की बदहाली के मूल कारणों पर ध्यान दिए बिना कोई भी राहत यहां स्थायी बदलाव नहीं ला सकती. भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष हरदत्त पांडेय कहते हैं कि 2004 से लगातार सूखा और दैवीय आपदाओं के चलते किसान बर्बाद हो चुका है. हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद बीज तक वापस नहीं हो पा रहा है. सिंचाई के अभाव में फसलें सूख गईं, वहीं ओलावृष्टि ने और कमर तोड़ दी. इसलिए बैंकों की वसूली पर रोक लगाई जाए. ओलावृष्टि से नष्ट हुई फ़सलों का मुआवज़ा पंद्रह हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर हर किसान को दिलाया जाए. रघुवीर सिंह ने मांग की कि क्षेत्र के तालाब अतिशीघ्र भरे जाएं.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... महंगाई का विकास

महाराष्ट्र के एक पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ इस मुद्दे को सालों से उठा रहे हैं. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं. मसलन, सभी राज्यों से यह कहा जाए कि वे विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सूची बनाएं.

विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियां

जनगणना के साथ नज़रिया बदलने की ज़रूरत

- घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की जनसंख्या 6 करोड़
- 1952 में खत्म हुआ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871
- अब तक नहीं हुई जनगणना, न मिली सरकारी सुविधा
- लेकिन सरकार बेपरवाह, अब भी हैं ये विकास से कोसों दूर
- नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड एंड नोमाडिक ट्राइब्स का गठन

शशि शेखर

पच्चीस फीट ऊंची रस्सी पर चलता एक इंसान, सड़क के किनारे करतब दिखाता एक बच्चा. शहर के किनारे तंबू डाले कुछ परिवार. आज यहां, कल कहीं और. बिस्तर के नाम पर ज़मीन, छत आसमान. महीने–दो महीने पर शहर बदल जाता है और शायद ज़िंदगी के रंग भी, लेकिन यह कहानी सैकड़ों सालों से बदस्तूर जारी है. यह कहानी है भारत के उन 6 करोड़ घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में यायावर कहते हैं. इनकी बदनसीबी का आलम यह है कि आज़ादी के 63 सालों बाद भी न तो इनकी जनगणना हुई है और न ही इन्हें कोई सरकारी सुविधा मिली. उल्टे पुलिस–प्रशासन की निगाहों में इनकी छवि अपराधियों की बनी हुई है.

अंग्रेजों के जमाने में इन्हें रोजाना थाने में हाज़िरी लगानी पड़ती थी. इनके लिए एक काला क़ानून अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871. आज़ादी के बाद भी दो सालों तक इनकी सुध किसी ने नहीं ली. दो साल बाद इस क़ानून में संशोधन तो हुआ, लेकिन इनकी ज़िंदगी में संशोधन के नाम पर कुछ नहीं हुआ. 1949–50 में अनंतसयाम अयंगर के नेतृत्व में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनी, जिसने इस एक्ट को ख़त्म करने की सिफ़ारिश की थी. 1953 में लालबहादुर शास्त्री यवतमाल के बंजारा अधिवेशन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने इस समुदाय के बच्चों को शुल्क मुक्त शिक्षा व स्कॉलरशिप देने की बात कही थी. 1966 में दिल्ली में हुए बंजारा अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने भी शिरकत की थी और यह आश्वासन दिया था कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. फिर 31 मार्च, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी महाराष्ट्र के सोलापुर में विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय की एक बैठक में शरद पवार के साथ शामिल हुए. इस बैठक में राजीव गांधी ने इस समुदाय को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक सुविधा देने का आश्वासन दिया. हालांकि यह आश्वासन भी कोरा ही साबित हुआ.

राजग के शासनकाल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लाखों लोगों की एक रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड एंड नोमाडिक ट्राइब्स (विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग) बनाने की घोषणा की. यह आयोग बना भी, लेकिन इसके अस्तित्व में आने के बावजूद इस समुदाय का कोई भला हुआ हो, ऐसा नहीं है. यह ख़ुद आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी रिपोर्ट पर सरकार के रवैये से ही पता चल जाता है. विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया है कि इस समुदाय के लोग देश के अलग–अलग हिस्सों में अस्थायी आश्रय स्थल, तंबू या खाली ज़मीन पर रहते हैं. इनके पास स्थायी पता नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें घर के लिए ज़मीन आवंटित करने में भी मुश्किलें आती हैं. इनके पास न तो अपने परिचय का कोई सबूत है और न संपत्ति के स्वामित्व का. नतीजतन, इनका राशनकार्ड भी नहीं बन पाता है और न ही ये बीपीएल कोटे में शामिल हो पाते हैं. जाति प्रमाणपत्र मिलने में भी इन्हें काफी मुश्किल होती है और इस वजह से ये सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते. यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, लेकिन इस पर सरकार ने अब तक क्या किया है, इसका कुछ अता–पता नहीं. ख़ुद इस आयोग के पूर्व चेयरमैन ने कहा है कि डेढ़ साल बाद भी इस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. ज़ाहिर है, इनकी भलाई के लिए जो थोड़े–बहुत प्रयास हुए, घोषणाएं हुईं, वे सब काग़ज़ों तक सीमित रह गए.

कुछ संगठन और राजनेता विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लोगों की भलाई के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं. 2011 की जनगणना का प्रथम चरण तो पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के तहत जातिगत आधार पर जनगणना होनी अभी बाक़ी है. महाराष्ट्र के एक पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ इस मुद्दे को सालों से उठा रहे हैं. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं. मसलन, सभी राज्यों से यह कहा जाए कि वे विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सूची बनाएं. साथ ही उनकी मांग यह भी है कि ओबीसी को दिए जाने वाले 27 फ़ीसदी आरक्षण में से कम से कम 7 फ़ीसदी आरक्षण विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लोगों को दिया जाए. एक फरवरी, 2011 को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में राठौड़ ने विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए बजट में अलग से राशि आवंटित करने की मांग की है. साथ ही वह 2011 की जनगणना में अलग से विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की जनगणना की भी मांग कर रहे हैं. इस संबंध में गृह राज्यमंत्री ने राठौड़ को पत्र लिखकर यह ज़रूर सूचित किया है कि कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2010 को हुई बैठक में निर्णय लिया है कि जून 2011 से जातिगत आधार पर जनगणना की जाएगी.

वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय की अलग से जनगणना के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि सरकार के इस निर्णय से अभी यह साफ नहीं हुआ है कि वास्तव में जनगणना के इस दूसरे चरण में जातिगत आधार के साथ–साथ विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के 6 करोड़ लोगों की जनगणना भी एक अलग श्रेणी में की जाएगी या नहीं. इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि देश के अलग–अलग हिस्सों में फैले विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के 6 करोड़ लोगों की जनगणना आख़िर सरकार कैसे कराएगी, क्योंकि अब तक सरकार यह साफ नहीं कर सकी है कि इस तरह की जनगणना की रूपरेखा क्या होगी. बहरहाल, अगर सरकार सचमुच विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय के 6 करोड़ लोगों की भलाई के लिए चिंतित है और इस बार की जनगणना के दूसरे चरण में उन्हें शामिल करती है तो यह स्वागतयोग्य क़दम माना जाएगा. लेकिन सवाल सिर्फ़ जनगणना कराने भर का नहीं है. सवाल उस मानसिकता का भी है, जिसकी वजह से पुलिस हो या आम आदमी, इस समुदाय विशेष को एक अलग नज़रिए से देखता है. ज़रूरत इस नज़रिए में बदलाव लाने की भी है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

राज्यवार विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियां

जनजाति	राज्य
बहारूपी	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक
बावा	गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश
बेलदार	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं बंगाल
भामता	आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र
भोई	कर्नाटक, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र
बुदबुदके	आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र
चलवाड़ी	आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र
चितपरधी	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक
दवारी गोसावी	गुजरात, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश
गदी–लोहार	गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान
घंटी–चोर	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली
गरौड़ी	गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश
घिसाड़ी	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली
बोल्ला	गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं त्रिपुरा
गोंधाली	गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक
गोपाल	गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश
जोगी	गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु
कहार	महाराष्ट्र एवं त्रिपुरा
कपाड़ी	गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश
कोल्हाटी	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक
मसान	महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश
शिकलगार	महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश
तिरमाली	गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश
वासुदेव	गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश

लालबहादुर शास्त्री यवतमाल के बंजारा अधिवेशन में शामिल हुए थे. दिल्ली में हुए बंजारा अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने शिरकत की थी. राजीव गांधी सोलापुर में विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय की बैठक में शामिल हुए. इन सभी लोगों ने इस समुदाय की भलाई के लिए घोषणाएं कीं. राजीव गांधी ने केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक सुविधा देने का आश्वासन दिया था.

डी पी मुखर्जी, देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय जैसे लोगों ने हमें हिंदू रहस्यवाद के बजाय तार्किक ज़िंदगी का आधार दिया था. अब वे दिन लौट कर नहीं आने वाले.

वर्ष 1996 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी एन भगवती ने टाइम मैगजीन में कहा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व में सबसे ताक़तवर न्यायिक संस्था है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

अवकाश और श्रम का समन्वय

बंटवारे के लिए देश में रुपये हों, धन हों, तो उसके पहले काम या मेहनत का होना ज़रूरी है. बिना काम या मेहनत किए धन अर्जन ही नहीं होगा तो फिर बंटवारा किस चीज का और कैसे होगा? बिना ज़मीन को जोते-बोए अनाज पैदा ही नहीं होगा. इसके लिए किसान को परिश्रम करना ही होगा. बाद में रोटी बनाने वाले रसोइए को परिश्रम करना होगा, तब कहीं जाकर रोटियां बन पाएंगी. हज़ारों वर्ष पहले अपने पूर्वज जंगलों या पहाड़ों पर रहते थे, पर आज तो वह युग नहीं है. हम सबके लिए अब यह संभव नहीं है. बिना अथक परिश्रम किए, हम भूखों मर जाएंगे. अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बैठा है तो निश्चित है कि कोई दूसरा व्यक्ति उन दोनों जितना काम कर रहा है, नहीं तो उन दोनों के लिए ही खाने को कुछ नहीं होगा. इसी नैसर्गिक सूत्र को ध्यान में रखते हुए पाश्चात्य विद्वान महर्षि पाल ने कहा था कि जो आदमी काम न करे, उसे खाने को न मिले. काम करने की ज़िम्मेदारी प्रकृति ने हमारे ऊपर लादी है. जिस तरह उपार्जित धन का बंटवारा निश्चित है, उसी तरह काम करने की ज़िम्मेदारी का बंटवारा भी आवश्यक है.

यह ज़रूरी नहीं है कि जो काम करे, वही खाए. एक आदमी अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा पैदा कर सकता है और करता है, नहीं तो छोटे बच्चे भूखे ही रहेंगे और वृद्ध आदमी, जिनकी काम करने की शक्ति समाप्त हो गई है, क्षुधा से पीड़ित होकर मर जाएंगे. कई एक मेहनती पुरुष देखने में आए हैं, जिनके पास अपने दो हाथों के सिवाय कोई सहारा नहीं था, तो भी उन्होंने अपने परिवार का, बच्चों का पालन-पोषण किया, वृद्ध माता-पिता की देखभाल की और अपने परिश्रम द्वारा ही जमींदार को अच्छी-खासी रकम भाड़े या लगान के रूप में दी.

आज के युग में जब बिजली और मशीनरी का आविष्कार हो गया है, निश्चय ही आज का मानव 100 वर्ष पहले के मानव की अपेक्षा एक हज़ार गुना से भी ज़्यादा पैदा कर सकता है. इस तरह मानव बुद्धि द्वारा उपयोग में लाई गई मशीनरी, बिजली, वाष्प आदि से मानव का परिश्रम कम हो जाता है और उसे अवकाश का समय अधिक मिल जाता है. यह अवकाश या फुरसत एक आरामदेह चीज है. इसका भी बंटवारा होना उतना ही आवश्यक है, जितना कि धन या काम का. मान लीजिए, एक आदमी 10 घंटे काम करके 10 आदमियों को 1 दिन के लिए सहारा देता है. वे 10 आदमी उस काम को बांट सकते हैं कि रोजाना 1-1 आदमी 10-10 घंटे काम करें और बाक़ी 9-9 दिन अवकाश में आराम करें या यह भी कर सकते हैं कि हर एक आदमी 1-1 घंटा नित्य काम करे और नित्य 9-9 घंटे आराम करे. इसी तरह के कई नुस्खे अपनी इच्छानुसार या सुविधानुसार मानव बना सकता है.

यह भी तो हो सकता है कि उन 10 में से 3 आदमी 10-10 घंटे काम करें. वे जो पैदा करेंगे, वह निश्चय ही 30 के लिए पर्याप्त होगा, जिससे बाक़ी 7 को केवल काम ही न करना पड़े, बल्कि 14 जितना खा भी सकें और उन 3 आदमियों को अनवरत काम करते रख सकें. एक यह भी व्यवस्था हो सकती है कि सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक दैनिक रूप से काम करें. पूर्ण शिक्षित या वयस्क होने तक काम करते रहें, बाद में काम बंद करके जीवन भर आराम करें.

इसी तरह के बीसों विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से काम और अवकाश का वितरण हो सकता है. इन्हीं काम और अवकाश के विभिन्न वितरण क्रमों को अलग-अलग नाम से संबोधित किया जाता है: 1. गुलामी, 2. दासता, 3. सामंतशाही, 4. पूंजीवादी परंपरा, 5. समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था.

क्रांति का इतिहास इन्हीं तथ्यों का सूचक है. मानव अपनी तत्सामयिक परिस्थितियों को बदलने के लिए जो संघर्ष करता है, अपने हित में जो उचित व्यवस्था समझ कर उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, उसे क्रांति कहते हैं. ख़ैर, इस समय तो हमें यही विचार करना है कि परिश्रम से जो आय होती है, उसका वितरण किस ढंग से किया जाए? काम और अवकाश के वितरण में ज़्यादा कठिनाई नहीं है. आदमी आदमी के काम और अवकाश में आप बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं कर सकते, पर आधुनिक आविष्कृत बिजली और मशीनों से आय में बहुत बड़ा फ़र्क़ हो सकता है. एक धनी व्यक्ति के दिन-रात में आप 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं बना सकते, पर उसके कोष में आप 24 करोड़ रुपये आसानी से बना सकते हैं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

वामपंथियों का लोकतांत्रिक स्टालिनवाद

इस बात पर कोई बाजी नहीं लगाई गई कि पश्चिम बंगाल में मिली बुरी हार के बाद सीपीएम के कितने नेता इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे और इस्तीफ़ा देंगे. ज़ाहिर है, कम्युनिस्ट पार्टी इस तरीक़े से काम भी नहीं करती. भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व थोड़ा दूसरे ढंग का है. यहां के कम्युनिस्टों ने लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकारा, जबकि दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्टों ने इस प्रक्रिया को नहीं स्वीकारा, लेकिन जब बात पार्टी के आंतरिक संगठन की आती है तो वहां स्टालिनवाद का ही शासन दिखता है. मैं स्टालिनवाद शब्द का इस्तेमाल किसी अभद्र भाषा के तौर पर नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे एक विवरणात्मक शब्द के तौर पर देख रहा हूं. मैं लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण शब्द का भी इस्तेमाल करता रहा हूं. महासचिव कोई ग़लती नहीं कर सकते, न कभी इस्तीफ़ा देते हैं.

कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी अपनी असफलता पर एक खुली और लोकतांत्रिक बहस की इजाज़त नहीं देती. वह परिशोधन और सुधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है. यह शर्मनाक स्थिति ही है कि भारत में 60 साल के चुनावी लोकतंत्र में जहां कम्युनिस्ट पार्टी एक अहम हिस्सा रही है, अब महज़ एक विचारधारा की पार्टी बनकर रह गई है. उसके पास सिर्फ़ ऐसे लोक लुभावन मुद्दे हैं, जिनका विचारों और जनता की समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता. मसलन, पेट्रोल के दाम में बढ़ोत्तरी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि धनी मध्य वर्ग को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, का मामला सहज ही विपक्ष और यहां तक कि सत्ता में शामिल गठबंधन के कुछ सहयोगियों का ध्यान भी आकर्षित कर लेता है.

वामपंथियों को अब अपनी हार के बारे में सोचना होगा. न सिर्फ़ भारत, बल्कि मंदी के दौरान पूरी दुनिया में वामपंथ जनता का समर्थन पाने में असफल साबित हुआ. यह सच न सिर्फ़ वामपंथियों, बल्कि सोशल डेमोक्रेटिक दलों के लिए भी है. असल में, ट्रोट्स्कीवाद सहित लेनिनवाद के सभी गुट जनता की निराशा को प्रदर्शन और आंदोलन का स्वरूप तो देते हैं, लेकिन उसे चुनावी सफलता में नहीं बदल पाते. असल समस्या पूंजीवाद की कार्यप्रणाली समझने को लेकर है. लेनिनवाद यह समझ रहा था कि पूंजीवाद अपने अंतिम संकट से जूझ रहा है और समय से पहले ही यह व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी. जबकि हुआ ठीक इसके उलट. यूएसएसआर में लेनिनवादी राज्य पूंजीवाद से पहले ही ढह गया. यह सही बात है कि पूंजीवाद असमानता को बढ़ाता है और असुरक्षा का भाव पैदा करता है, लेकिन इसका इलाज यह नहीं है कि आप इसके अंत की प्रतीक्षा करें, बल्कि ऐसी कोशिश करनी होगी, ताकि इसे नियंत्रित किया जा सके और इसका इलाज निकाला जा सके. चूंकि पूंजीवाद नवीन प्रक्रिया अपनाने और विशाल परिवर्तन कर पाने में सक्षम है, इसलिए हर पीढ़ी को नई चुनौतियों का नए सिरे से सामना करना ही होगा.

भारत में वामपंथ पर एक व्यापक और मुक्त बहस की आवश्यकता है. भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी सहानुभूति वामपंथ के साथ है और वह इनकी सहायता कर सकते हैं. मुझे याद है, 1950 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी पुराने एवं अप्रचलित धार्मिक अंधविश्वास की कड़ी मुखालफत करती थी. डी पी मुखर्जी, देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय जैसे लोगों ने हमें हिंदू रहस्यवाद के बजाय तार्किक ज़िंदगी का आधार दिया था. अब वे दिन लौट कर नहीं आने वाले. अब वामपंथ अपनी आलोचनात्मक कार्य पद्धति से भटक गया है. आज यह बिना किसी नई आर्थिक सोच के सिर्फ़ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता दिख रहा है, जो कि वामपंथ की एक पुरानी परंपरा है. मानों वही सब फिर से दोहराया जा रहा हो.

इंदिरा गांधी से लेकर हरकिशन सिंह सुरजीत तक के दिनों को देखें तो ऐसा लगता है कि वामपंथी कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक सहायक पार्टी के तौर पर ही काम कर रहे थे. कांग्रेस ने वामपंथियों को अपनी विचारधारा के हिसाब से यूनिवर्सिटी चलाने, शोध करने की छूट दे दी थी. यही वजह है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथ का गहरा प्रभाव रहा, लेकिन इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील पर बखेड़ा खड़ा होने के बाद स्थिति बदली है. उन दिनों के बाद से वामपंथी लगातार पीछे खिसकते जा रहे हैं. वामपंथियों को यह समझना होगा कि वे एक पौधे के रूप में तभी फल-फूल सकते हैं, जब तक उन्हें कांग्रेस रूपी छाया मिलती रहेगी. यदि वामपंथी चाहें तो बड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब वे साधारण राजनीतिक भाषा एवं विमर्श को अपनाएं. इसका मतलब यह कि सबसे पहले तो वामपंथियों को पोलित ब्यूरो जैसे मूर्खतापूर्ण शब्दों से ख़ुद को दूर करना चाहिए, जहां हर एक सदस्य के पास ख़ुद की एक कार्यसमिति होती है. उन्हें जाति और दलित आरक्षण पर विचार करना चाहिए और यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या इससे समतावादी समाज का निर्माण और विकास संभव है. वामपंथियों को हमारे राजनीतिक जीवन पर गुरु, स्वामी, मंदिर एवं दरगाह के प्रभाव और पकड़ को चुनौती देनी चाहिए. इसी का अर्थ होगा व्यापक बदलाव. सिर्फ़ सुधार या संशोधन से काम नहीं चलने वाला.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

गर्भनाल का आगमन हिंदी साहित्य के लिए शुभ माना जा रहा है. चौथी दुनिया में कहानी और कविताओं को भी स्थान दें. यह अख़बार पाठकों में अपनी विशेष पहचान बनाता जा रहा है.

-अशोक कुमार ठाकुर, *दरभंगा, बिहार.*

आम आदमी की ज़रूरत

सूचना का अधिकार 2005 अब आम आदमी का हथियार बन चुका है. सच तो यह है कि सरकारी विभागों में आरटीआई का ख़ौफ़ साफ़ देखा जा सकता है. आरटीआई का इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है. चौथी दुनिया में हर सप्ताह इस विषय पर प्रकाशित होने वाली सामग्री पाठकों के लिए निस्संदेह कारगर सिद्ध हो रही है, ख़ासकर उन युवाओं के लिए, जो आरटीआई कार्यकर्ता बनकर देश के सरकारी महकमों में पारदर्शिता लाना चाहते हैं.

-आदिल ख़ान, *ओखला, नई दिल्ली.*

जनता बेहाल

आज़ादी के कुछ वर्षों बाद से ही देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई थी. विभिन्न सरकारों द्वारा अपने स्वार्थ के कारण इस पर अंकुश नहीं लगाए जाने और इसे बढ़ावा देने के कारण यह लगातार बढ़ता ही गया. आज इसने देश के सामने एक विकराल समस्या का रूप धारण कर लिया है, जिससे सारी जनता त्रस्त है और किसी भी तरह इससे निजात पाना चाहती है, लेकिन यह देश की नस-नस में समा चुका है और हमें खोखला कर रहा है. हमें संकल्प लेना होगा कि हम भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लेंगे.

-एनजे, *छपरा, बिहार.*

कहानी-कविता को स्थान दें

आलेख-पत्रिकाओं से बनता परिवेश पढ़ा. साहित्यिक पत्रिका तद्भव और गर्भनाल के बारे में जानकारी मिली. तद्भव और

ओसामा का इतिहास

आवरण कथा-एक था ओसामा पढ़ी. ओसामा का वैसा इतिहास जैसा आप चाहते हैं, लिखने वालों की कमी नहीं रहेगी. आप निश्चिंत रहें. हां, अमेरिका विरोध के नाम पर कोई वैचारिक हद भी उतनी ही जरूरी है.

-प्रवीण त्रिवेदी, *ईमेल से.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

राजनीतिज्ञों से डरना चाहिए

सच कहा आपने, राजनीतिज्ञों से डरना चाहिए. सचमुच अन्ना से चूक हो गई. लोग तंग आ गए हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार से और हर दिन नए घोटालों से. अन्ना हज़ारे चूंकि सियासत के खिलाड़ी नहीं हैं और धुरंधर राजनीतिक भेड़ियों के बीच एक सीधा-सादा मेमना क्या कर सकता है. शुरुआत में ही वंशवाद का ठप्पा रामदेव ने ठोंक दिया, जिससे संभल नहीं पाए थे कि दिग्विजय के शोर ने सिर चकरा दिया. कभी किरण बेदी के नाम पर राजनीति की तो कभी अन्ना हज़ारे पर दांव खेला कि इतने पैसों का हिसाब बताओ. बेचारे बौखला गए, सियासी दांव-पेच भला वह क्या जानें.

-लक्ष्मी नारायण प्रधान, *धर्मशाला कैंट, हिमाचल प्रदेश.*

एक नज़र

चौथी दुनिया ने जो दिखाया एक नज़र में
हमने भी बहुत कुछ देख लिखा एक नज़र में
पहन लंगोटी, हाथ में लाठी, चल पड़ा था गांधी
उसी राह पर चलकर, भ्रष्ट व्यवस्था को
उड़ा ले जाएगी अब अन्ना की आंधी
राजनीति में क्या उचित है, एक दिन समझेगी
जनता, चौथी दुनिया के सहारे हमने आशा बांधी
देश में जाली नोट का धंधा, प्रशासन है अंधा
एक नज़र पड़ेगी जनता की, तो कोई न बचेगा बंदा
एक नज़र चौथी दुनिया की, एक नज़र साई बाबा की
भ्रष्टाचार मिट कर रहेगा, चेष्टा है रामदेव बाबा की
एक-एक नज़र करके जब करोड़ों नज़रें उठेंगी
सब कुछ बदल देंगी, जब जनांदोलन की लहरें उठेंगी
-अदिति भारद्वाज, हुगली, पश्चिमी बंगाल.

भ्रष्टाचार की जड़

आलेख-अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं पढ़ा. पैसे से नाचती है दुनिया और दुनिया वालों को नचाता है पैसा, बात यही है. कितने नेताओं को जेल होती है? अब रही बात उद्योगपतियों की, वे तो हमेशा फ़ायदा देखकर ही कोई काम करते हैं, इसमें उनका कसूर क्या है? सच तो यह है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा.

-कमलेश पांडेय, *ईमेल से.*

■ क़ानून तो सिर्फ़ ग़रीबों और किसानों के लिए बना है, जिनके साथ उद्योगपति मनमानी करते हैं. क़ानून और अदालत ने उन्हें खुली छूट दे रखी है. लगता है, उनसे कहा गया है कि कुछ भी करो और हमारी शरण में आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे. लुटेरों, गद्दारों, आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के लिए न तो कोई कानून है और न कोई जेल बनी है. ये लोग क़ानून को अपनी बगल में दबाकर घूमते हैं और कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता.

-सुभाष, *ईमेल से.*

राजकमल प्रकाशन समूह
राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002 फ़ोन 011-23274463, 23288769, फ़ैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से लेखन विधा को सम्मान
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपये की किताबें

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपये की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029
पाठक पूरे नाम, पते व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें : संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

उत्तर प्रदेश का चुनाव कई पार्टियों का भविष्य तय करेगा

अगला घमासान उत्तर प्रदेश में होने वाला है. मुख्यमंत्री मायावती राजनीतिक तौर पर सबसे आगे हैं. मायावती ने अपनी पार्टी के ऐसे सदस्यों को, जिनके प्रति स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा हुआ है, बदला है और ऐसे लोगों को साथ लेने की कोशिश की है, जो उन्हें वोट दिलवा सकें. मायावती सर्वजन की भाषा बोल रही हैं. उत्तर प्रदेश में राज करने की चाबी भी इसी भाषा में है. अगर कोई भी पार्टी किसी एक वर्ग या एक जाति की पार्टी बनकर सामने आती है तो शायद उसे उस समुदाय या जाति का समर्थन तो मिल सकता है, लेकिन सत्ता उसके पास आएगी या वह सत्ता में आ पाएगा, इसमें शक़ है. मायावती के साथ दलित वर्ग अभी भी संगठित है. हालांकि राजनीतिक तौर पर लोगों का यह कहना है कि अब दलित धीरे-धीरे मायावती से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि दलितों को लगता है कि अपनी क्षमता से मायावती इस पद को प्राप्त कर लेंगी. पर मायावती मुख्यमंत्री हैं, उनके किए हुए कामों का आकलन शुरू हो चुका है. लखनऊ में जिस तरह से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से लखनऊ का चेहरा बदला, उससे ग़रीबों में भी बहुत ख़ुशी नहीं है. जब भी लखनऊ जाना हुआ, ग़रीब वर्ग में ऐसे बहुत सारे लोग मिले, जिनका कहना है कि सड़क, पानी, बेरोज़गारी, भूख और स्वास्थ्य जैसे एजेंडे मौजूदा सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं. शायद ये प्राथमिकता में हों, पर ये ज़मीन पर ट्रांसलेट होते नहीं दिखाई देते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं चाहेगी तो कोई भी अच्छी योजना धरती पर आकार नहीं ले पाएगी.

उत्तर प्रदेश में एक तरफ़ राजनीतिज्ञ कितनी इच्छाशक्ति रखते हैं, यह जनता को पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ब्यूरोक्रेसी खुलकर यह कहने लगे कि हम ऊपर पैसा देते हैं, हम नीचे काम करें या ना करें, तो फिर चिंता बढ़ जाती है और उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी एक-दो नहीं हैं, बड़ी संख्या में हैं. मैं ख़ुद एक घटना का गवाह हूं. एक बड़े प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी ने मेरी उपस्थिति में कहा कि इतने प्रतिशत तो मुझे लखनऊ में देना पड़ता है. इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा. वह अधिकारी मुझे पहचानता नहीं था. मैंने भी उसे परिचय नहीं दिया, पर मैं उस घटना का गवाह हूं. शायद मायावती जी को नहीं पता कि उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में कितनी लूट चल रही है. कोई भी ठेका, कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट बिना एक निश्चित कमीशन लिए नहीं दिया जाता. मायावती जी को शायद कोई बताएगा भी नहीं, पर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के महत्वपूर्ण लोग इस बात को जानते हैं. अफ़सोस इस बात का है कि इसे सुधारने की कोई योजना न प्रमुख अधिकारियों के पास है और न स्वयं मुख्यमंत्री के पास.

मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं. उन्हें लगता है कि वह दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की छवि समाजवादी नेता से ज़्यादा एक जाति विशेष के नेता जैसी बन गई है. इसे उनके आसपास के लोगों ने बहुत मज़बूत किया है. मुलायम सिंह को अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री पद का दावा करना है या दावेदार होना है तो उन्हें जनता के सभी वर्गों को साथ लेने की कोशिश करनी होगी और अपने नेतृत्व में विभिन्न वर्ग के नेताओं को चलता हुआ दिखाना होगा. लोगों को बताना होगा कि लोग उनके बारे में जो ग़लत प्रचार कर रहे हैं, वैसा है नहीं. कांग्रेस की हालत बहुत ही ढुलमुल है. कांग्रेस को जिस तरह ख़ुद को संगठित करना चाहिए, अफ़सोस की बात है कि उस तरह वह उत्तर प्रदेश में ख़ुद को संगठित नहीं कर पा रही है. परिणाम यह हो रहा है कि ज़िलों में कांग्रेस का संगठन बिल्कुल कोमा

उत्तर प्रदेश में एक तरफ राजनीतिज्ञ कितनी इच्छाशक्ति रखते हैं, यह जनता को पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ब्यूरोक्रेसी खुलकर यह कहने लगे कि हम ऊपर पैसा देते हैं, हम नीचे काम करें या ना करें, तो फिर चिंता बढ़ जाती है और उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी एक-दो नहीं हैं, बड़ी संख्या में हैं. मैं ख़ुद एक घटना का गवाह हूं. एक बड़े प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी ने मेरी उपस्थिति में कहा कि इतने प्रतिशत तो मुझे लखनऊ में देना पड़ता है. इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा.

की हालत में पहुंच गया है, मूर्छित अवस्था में पहुंच गया है. राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की ज़िम्मेदारी नए सिरे से अपने कंधों पर ली है. उन्होंने वाराणसी अधिवेशन में यह घोषणा कि है कि वह उत्तर प्रदेश की गली-गली में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे. राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गांवों और गलियों में जाने की बात कही है, लेकिन एक वर्ष से भी कम समय रह गया है और अभी तक ऐसी कोई योजना नज़र नहीं आ रही है, जिसमें राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के गांवों में जाते हुए दिखाई दे रहे हों या उत्तर प्रदेश के सवालों को लेकर लड़ने के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हों.

भारतीय जनता पार्टी टेक ऑफ की स्थिति में नज़र नहीं आती. उत्तर प्रदेश में पहले स्थान के लिए दो पार्टियों में लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी. ज़ाहिर है, इन्हीं में से कोई पहले स्थान और दूसरे स्थान पर होगा. तीसरे स्थान के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कौन इस जगह को अपने लिए सुरक्षित कर पाता है, यह देखना इस बार मज़ेदार होगा. एक और पार्टी बीच में धीरे-धीरे अपनी पैठ बना रही है, पीस पार्टी. इसके अध्यक्ष डॉ. अयूब हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश से इसका सफ़र शुरू हुआ और यह लखीमपुर खीरी तक पहुंच गया. पिछले जितने चुनाव हुए हैं, उनमें कहीं दूसरे नंबर पर, कहीं तीसरे नंबर पर पीस पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं. पीस पार्टी के साथ मुस्लिम समाज का समर्थन ज़्यादा दिखाई दे रहा है. हालांकि पीस पार्टी का कहना है कि उसकी लीडरशिप या उसके सदस्यों में सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि समाज के सभी तबकों के लोग हैं. वह बहुजन समाज पार्टी के रास्ते पर चल रही है, जिसमें लीडरशिप दलित वर्ग की है, पर बाकी दूसरे वर्ग भी उससे जुड़ रहे हैं. यही रणनीति पीस पार्टी ने बनाई है. पीस पार्टी का भविष्य कैसा होगा, यह चुनाव बताएंगे. एक और पार्टी उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में सामने दिखाई देगी, जमात-ए-इस्लामी हिंद द्वारा प्रवर्तित पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया. यह पार्टी भी मुस्लिम वोटों की दावेदार है. अब एक तरफ़ समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट चाहती है, दूसरी तरफ़ कांग्रेस चाहती है. बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करे, ताकि उसे मुस्लिम मत मिलें. और मुसलमानों की दो पार्टियां आ गई हैं, जिनमें एक पीस पार्टी है और दूसरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया. मुसलमान वोट आने वाले चुनाव में निर्णायक रह पाएगा या नहीं, इसका फ़ैसला भी इस बार मुसलमान ही करेंगे. अगर वे तीन या चार जगह बंट गए तो ज़ाहिर है कि उनके वोटों का कोई भी राजनीतिक असर चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन अगर वोट नहीं बंटे और उन्होंने बुद्धिमानी से फ़ैसला किया और किसी एक पार्टी का साथ दिया तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का समीकरण बदल जाएगा. जिसके साथ मुसलमान पूरी तरह से होंगे, वह पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता की सशक्त दावेदार होगी.

इसके अलावा बहुत सारी छोटी-छोटी पार्टियां हैं. उत्तर प्रदेश दरअसल पार्टियों का दलदल है. यहां पर पार्टियां ही पार्टियां हैं. इन पार्टियों के बीच में कहां दलित रहता है, कहां ग़रीब रहता है, कहां अल्पसंख्यक रहता है और वह अपना असर बनाए रख भी पाता है या नहीं, यह सवाल बड़ा है, महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश में आम लोगों को अपने हितों के हिसाब से वोट देते देखने का मौक़ा देश को मिलेगा या नहीं, अभी नहीं कह सकते. लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर बिहार और बंगाल की तर्ज पर हुआ और लोगों ने जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमा से अलग हटकर वोट डाले तो सत्ता में कौन आएगा? क्या उस संभावना का लाभ मायावती जी को मिलेगा या मुलायम सिंह जी को मिलेगा या राहुल गांधी जी की कांग्रेस को मिलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, अभी नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बहुत दिलचस्प, इसमें कोई दो राय नहीं है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

के के वेणुगोपाल

सुप्रीम कोर्ट में बदलाव ज़रूरी है

इस विषय के बारे में लिखने में एक अलग रोमांच है, इसलिए मैं बहुत सी ऐसी बातें यहां लिख सकता हूं, जो कि मैं उच्चतम न्यायालय में जजों के सामने बहस करते समय नहीं बोल सकता. जब बात होती है कि भारतीय न्यायपालिका के साथ क्या परेशानियां हैं तो हमें जवाब में हां या न कहना पड़ता है, लेकिन मेरा जवाब हां भी है और न भी. मैं उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1979 से हूं. वर्ष 1950 के अंत में उच्चतम न्यायालय के सामने केवल 600 मामले थे, जिनका निस्तारण लंबित था और आज इनकी संख्या 54,000 है. इसका मतलब यह है कि तबसे आज तक मुक़दमों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है. बात यह है कि शुरू से ही इस समस्या पर सरकारों, विधायिका और ख़ुद जजों को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन सभी तंत्रों ने इस समस्या की तब तक अनदेखी की, जब तक यह हाथ से निकल नहीं गई, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी जहां तक आम जनता का सवाल है, उसे न्यायपालिका में अटूट विश्वास है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कोर्ट ने न्याय करने के अलावा देश में हर ग़लत चीज़ को मिटाने में, चाहे वह भ्रष्टाचार ही क्यों न हो, एक सक्रिय भूमिका निभाई है. हम सभी 2-जी घोटाले से वाकिफ हैं और सुप्रीम कोर्ट ही वह संस्था है, जिसने इस मामले की रोजाना निगरानी करने का दायित्व लिया है. जब भी भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट ही सीबीआई के माध्यम से उस पर नज़र रखती है. अगर आज

सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है. यह संविधान द्वारा बनाया गया है और संविधान का रक्षक है. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही मसले उठाने चाहिए, जो संवैधानिक हों, जिनमें संवैधानिक प्रश्न निहित हों, जिनका सरकार के सभी अंगों से सरोकार हो, जिनका केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों से सरोकार हो या कोई ऐसा मसला, जिसमें ऐसा वैधानिक और क़ानूनी पेंच हो, जिसका पूरे देश पर असर पड़ सकता हो.

भारत में जंगल बचे हैं तो वह सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हस्तक्षेप से.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जनजीवन के हर पक्ष पर हस्तक्षेप किया है. यह अनुच्छेद 21 के माध्यम से किया गया है. यह बहुत ही सीधा सा अनुच्छेद है, जो कहता है कि भारत के हर नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को समग्र रूप से देखा है और यह कहा है कि जीवन का अधिकार केवल जानवरों जैसा अस्तित्व मात्र नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकार मर्यादा गौरव और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें सिर पर छत और भर पेट खाना आदि शामिल हैं. इसी कारण बहुत से ऐसे न्यायिक आदेश पारित हुए, जिन्होंने जीवन को बेहतर बनाया है. इसी कारण लोगों की नज़र में सुप्रीम कोर्ट का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है.

वर्ष 1996 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी एन भगवती ने टाइम मैगजीन में कहा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व में सबसे ताक़तवर न्यायिक संस्था है. ऐसा है भी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट देखे जाएं तो यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे कर्तव्य अधिग्रहीत कर लिए हैं, जो कार्यपालिका के हैं. तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों पर क़ब्ज़ा कर लिया है? हां ऐसा हुआ है, क्योंकि अलग-अलग समय पर कोर्ट ने सरकारों को आदेश जारी किए हैं, जो देखा जाए तो दिशा निर्देशों से ज़्यादा क़ानून और विधान दिखाई पड़ते हैं. लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट यह काम वैधानिक तरीक़े से कर सकता है, इसलिए जस्टिस काटजू ने एक बड़ी बेंच का गठन किया है, जो इस विषय को देखेगी.

बहुत लोग यह बात नहीं जानते कि सोमवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को सुनने के लिए बैठता है, जिन्हें मिस्लेनियस कहते हैं और कुछ ऐसे मामले, जिन्हें अपने आप ही कोर्ट लेना चाहे. इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौदह पीठें बैठती हैं और हर पीठ के पास 50 से लेकर 70 मामले तक होते हैं. यह सोचने की बात है कि क्या कोई एक पीठ एक दिन में इतने सारे मामले निपटा सकती है, जबकि कुछ मामले वैधानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. लेकिन ऐसा होता है. सोचने की बात यह है कि हर बेंच, एक को छोड़कर, दो जजों की होती है और एक तीन की होती है. अब ऐसा होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं. वकील यह नहीं जानते कि उनका मामला किस बेंच के सामने रखा जाएगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो मामला एक बेंच के सामने ख़ारिज हो जाएगा, वही मामला दूसरी बेंच उठा लेगी. किसी और देश में ऐसा नहीं होता. अमेरिका में पूरा सुप्रीम कोर्ट एक साथ बैठता है यानी वहां के सभी नौ जज एक साथ सुनवाई करते हैं. इसी वजह से वहां क़ानून का विकास सामंजस्यपूर्ण और समग्र तरीक़े से होता है. लेकिन यहां की व्यवस्था के अनुसार तो हर जज अपने आप में ही सुप्रीम कोर्ट भी है और क़ानून भी. इस वजह से हमें अलग-अलग फ़ैसले मिलते हैं. इन अलग-अलग फ़ैसलों का आपस में सामंजस्य कम होता है और कई बार तो ये विरोधाभासी होते हैं. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी अमेरिका जैसी ही व्यवस्था है.

सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है. यह संविधान द्वारा बनाया गया है और संविधान का रक्षक है. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही मसले उठाने चाहिए, जो संवैधानिक हों, जिनमें संवैधानिक प्रश्न निहित हों, जिनका सरकार के सभी अंगों से सरोकार हो, जिनका केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों से सरोकार हो या कोई ऐसा मसला, जिसमें ऐसा वैधानिक और क़ानूनी पेंच हो, जिसका पूरे देश पर असर पड़ सकता हो. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. यदि कोई सुप्रीम कोर्ट जाए तो देख सकता है कि सुप्रीम कोर्ट शादी के मसले सुलझा रहा है. पति-पत्नी खड़े हैं और जज उनमें सुलह कराने में लगे हैं और यह कम से कम आधे घंटे चलता रहता है और कभी-कभी तो सुलह न हो पाने पर दोनों पक्षों को वे अपने चैंबर में आने को कहते हैं. ऐसे ही मकान मालिक और किराएदार के बीच के विवाद, कामगारों के मामले एवं जमानत के मामले. यह काम देश के सुप्रीम कोर्ट का नहीं है. इसी तरह 80 फ़ीसदी मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए. लेकिन प्रश्न यह भी है कि अगर हाईकोर्ट में फ़ैसला न्यायसंगत न हो तो व्यक्ति कहां जाए? इस समस्या से निपटने के लिए कई देशों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक कोर्ट ऑफ़ अपील होता है, जो वे सारे मामले सुन लेता है, जिन्हें सुनने के लिए आज हमारा सुप्रीम कोर्ट अपना समय नष्ट करता है.

इन सभी समस्याओं के बावजूद सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता की आख़िरी उम्मीद है. अगर सुप्रीम कोर्ट न होता तो सरकारें बहुत कुछ मनमाने ढंग से करके निकल जातीं और देश की जनता उसे भुगतती. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता के बचाव के लिए बहुत काम किए हैं और इसीलिए आज भारत का विश्वास न्यायपालिका में और भी मज़बूत हुआ है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं)

feedback@chauthiduniya.com

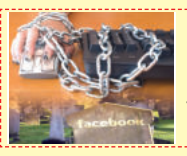

पुलिस के मुताबिक़ , ब्रिसबेन में रहने वाला यह 20 वर्षीय युवक भी सातवीं मंज़िल पर मौजूद अपने घर की बालकनी में रेलिंग पर लेटकर अपने दोस्त के ज़रिए फोटो खिंचवा रहा था.

दिल्ली, 06 जून–12 जून 2011 चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

प्रथम अपील क्या है

इस कॉलम की शुरुआत में हमने आपको प्रथम अपील, द्वितीय अपील एवं शिकायत के बारे में बताया था. एक बार फिर से हम आपको अपील एवं शिकायत के बारे में जानकारी दे रहे हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि आरटीआई आवेदन डालने के बाद आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है. ऐसी स्थिति में अपील एवं शिकायत करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता. मान लीजिए, आपने सूचना पाने के लिए किसी सरकारी विभाग में आवेदन दिया और 30 दिन बीत जाने के बाद भी आपको सूचना नहीं मिली. सूचना मिली भी तो गलत या आधी–अधूरी या भ्रामक. या फिर सूचना का अधिकार क़ानून की धारा 8 के प्रावधानों को तोड़–मरोड़ कर आपको सूचना देने से मना कर दिया गया. यह कहा गया कि फलां सूचना दिए जाने से किसी के विशेषाधिकार का हनन होता है या फलां सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी है. अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ज़ाहिर है, चुपचाप तो बैठा नहीं जा सकता. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप सूचना का अधिकार क़ानून के तहत ऐसे मामलों में प्रथम अपील करें. जब आप आवेदन जमा करते हैं, उसके 30 दिनों बाद लेकिन 60 दिनों के अंदर, लोक सूचना अधिकारी के ही एक वरिष्ठ अधिकारी, जो सूचना क़ानून के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, के यहां अपील करें. यदि आपके द्वारा अपील करने के बाद भी कोई सूचना या संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है या आपकी प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब आप दूसरी अपील कर सकते हैं.

दूसरी अपील के लिए आपको राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में जाना होगा. फ़िलहाल, इस अंक में हम सिर्फ़ प्रथम अपील के बारे में ही बात कर रहे हैं. इस अंक में हम प्रथम अपील का एक प्रारूप भी प्रकाशित कर रहे हैं. अगले अंक में हम आपकी सुविधा के लिए द्वितीय अपील का प्रारूप भी प्रकाशित करेंगे. प्रथम अपील के लिए साधारणतया कोई शुल्क निर्धारित नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां प्रथम अपील के लिए भी शुल्क निर्धारित किया है. प्रथम अपील के लिए कोई निश्चित प्रारूप (फॉर्म) नहीं होता है. आप चाहें तो एक सादे काग़ज़ पर भी लिखकर प्रथम अपील तैयार कर सकते हैं. हालांकि इस मामले में भी कुछ राज्य सरकारों ने प्रथम अपील के लिए एक ख़ास प्रारूप तैयार किया है. प्रथम अपील आप चाहें तो डाक या व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यालय में जाकर भी जमा करा सकते हैं. प्रथम अपील के साथ आरटीआई आवेदन, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (यदि उपलब्ध कराई गई है तो) और आरटीआई आवेदन के साथ दिए गए शुल्क की रसीद की फोटो कॉपी लगाना न भूलें. इस क़ानून के प्रावधानों के अनुसार, यदि लोक सूचना अधिकारी आपके द्वारा मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराता है तो आप प्रथम अपील में सारी सूचनाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए भी कह सकते हैं. इस कानून में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है. भले ही सूचना हज़ार पन्नों की क्यों न हो. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अंक में प्रकाशित प्रथम अपील के प्रारूप का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे. अगले अंक में हम आप तक द्वितीय अपील एवं शिकायत का प्रारूप भी पहुंचाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301,
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

प्रथम अपील का प्रारूप

सेवा में,
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,
मैंने सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है. (आवेदन की प्रति संलग्न है)

सूचना का अधिकार कानून 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद
–लोक सूचना अधिकारी द्धारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है.
और/या
–मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है.
और/या
– मुझे जो जवाब उपलब्ध कराया गया है, वह गलत है.
और/या
–मुझे जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, वह भ्रामक है.
और/या
–मुझे जो जवाब उपलब्ध कराया गया है, वह मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है.

आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें और लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दें. इस कानून के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्धारा मांगी गई सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें. साथ ही सूचना कानून के प्रावधान के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर इस कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दें.

नाम.....
हस्ताक्षर.....
पता.....

ज़रा हट के

फेसबुक में मौत का खेल

इंटरनेट पर लोग प्लैंकिंग से जुड़ी तस्वीरें अपलोड करते हैं. ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इंटरनेट के एक अजीब खेल के चलते एक इमारत की सातवीं मंज़िल से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई. यह व्यक्ति प्लैंकिंग नामक खेल खेल रहा था और इसके चलते उसने बालकनी की रेलिंग पर ख़तरनाक परिस्थितियों में लेटकर फोटो खिंचवाने की कोशिश की. ग़ौरतलब है कि इंटरनेट एवं कुछ सोशल नेटवर्किंग बेवसाइट्स पर इन दिनों प्लैंकिंग का जुनून छाया है. यह एक अजीब शौक़ है, जिसके तहत लोग ख़तरनाक परिस्थितियों और जगहों पर लेटकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं और उन्हें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपलोड करते हैं. इंटरनेट पर अपलोड की गई तस्वीरों में लोगों को चिमनी, लिफ्ट, ऊंट और कई ख़तरनाक जगहों पर लेटा हुआ देखा जा सकता है. फेसबुक पर बने एक ऐसे ही अकाउंट में 90 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने इस तरह खतरों से खेलने में अपनी रुचि ज़ाहिर की है. पुलिस के मुताबिक़ , ब्रिसबेन में रहने वाला यह 20 वर्षीय युवक भी सातवीं मंज़िल पर मौजूद अपने घर की बालकनी में रेलिंग पर लेटकर अपने दोस्त के ज़रिए फोटो खिंचवा रहा था. क्वींसलैंड के पुलिस उपायुक्त रॉस बारनेट के मुताबिक, सुबह हमने देखा कि एक युवक ने प्लैंकिंग के अपने शौक़ को एक कदम आगे ले जाते हुए बालकनी जैसी खतरनाक जगह पर इस खेल को खेला. रॉस के मुताबिक़, प्लैंकिंग का जुनून जैसे–जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे–वैसे लोगों के इसका शिकार होने का ख़तरा भी बढ़ रहा है.

टीवी और ब्लड प्रेशर

यदि आपके बच्चे जरूरत से ज्यादा टेलीविज़न देखते हैं या टीवी पर वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें रोकिए, क्योंकि यह दोनों चीजें बच्चों केरक्तचाप को बढ़ा सकती हैं. यह बात अमेरिका में हुए एक अध्ययन में सामने आई है. 111 बच्चों पर किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि टेलीविज़न और वीडियो देखने, कंप्यूटर के उपयोग और वीडियो गेम खेलने के कारण शारीरिक रूप से निष्क्रिय गतिविधियों की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. लोवा विश्वविद्यालय के डेविड मार्टिनेज–गोमेज और उनके सहायकों द्धारा किए गए इस अध्ययन में पाया गया है कि निष्क्रिय शारीरिक व्यवहार और हाई ब्लड प्रेशर बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है. यह अध्ययन 57 लड़कों और 54 लड़कियों पर किया गया. इस अध्ययन का प्रकाशन अर्काइव्स ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड एडोलसेंट मेडिसिन में किया गया है. अध्ययन के मुताबिक़ , अधिक वजन के बच्चों में हृदय संबंधी रोगो का खतरा बालपन में भी बहुत अधिक होता है. यह खतरा तब और बढ़ सकता है, जबकि वह बच्चा टेलीविजन से ज्यादा देर तक चिपका रहेगा. असल में टीवी देखते समय बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, जिससे बीमारी लगने का खतरा ज्यादा रहता है. अध्ययन में लोगों से कहा गया है कि यह केवल उनके भविष्य के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या है, जो अभी से बढ़ने लगी है. बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर में वंशानुगत कारणों, खानपान और सोने की आदत का भी योगदान होता है. हालांकि नौ वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निष्क्रिय शारीरिक व्यवहार और हाई ब्लड प्रेशर का कोई सीधा संबंध फ़िलहाल नहीं पाया गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल
पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. यात्रा–देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद रहेगी. शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई
पिता, उच्चाधिकारी, भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा. यात्रा–देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद रहेगी. मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे. ससुराल पक्ष से लाभ होगा. व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी.

मिथुन 21 मई से 20 जून
संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी होने या खोने की आशंका है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई
राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. दांपत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा. प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे. नए अनुबंध प्राप्त होंगे. आय के नवीन स्रोत बनेंगे.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त
स्थानांतरण और परिवर्तन की दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. रुपये–पैसे के लेनदेन में सावधानी अपेक्षित है. उपहार एवं सम्मान का लाभ मिलेगा. भाग्यवश कुछ ऐसा होगा, जो आपके लिए अच्छा है. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर
आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. यात्रा एवं देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद होगी. नए अनुबंध प्राप्त होंगे. शासन–सत्ता का सहयोग मिलेगा. धन एवं सम्मान में वृद्धि होगी.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर
कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आपसी संबंधों में निकटता आएगी. संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा. लंबी यात्रा की दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. व्यक्ति विशेष का भरपूर सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर
संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. यात्रा–देशाटन के अवसर पैदा होंगे. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. दांपत्य जीवन सुखमय होगा. पारिवारिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर
दांपत्य जीवन सुखमय होगा. किसी अभिन्न मित्र से मुलाकात होगी. कोई सुखद समाचार मिलेगा. व्यवसायिक मामलों में व्यवधान रहेगा. तनाव एवं टकराव की स्थिति से बचें. वाणी की मधुरता बनाए रखें.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी
राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी. शासन–सत्ता का सहयोग मिलेगा. भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. नए अनुबंध प्राप्त होंगे.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी
जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. रोजी–रोज़गार की दिशा में आशातीत सफलता मिलेगी. दांपत्य जीवन सुखमय होगा. कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा. व्यर्थ की उलझनें रहेंगी.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च
यात्रा–देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद होगी. क्रोध और भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा. भाग्यवश कुछ ऐसा होगा, जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी. धन, पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद गिलानी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है.

पाकिस्तान

चीन की छत्रछाया के निहितार्थ

राजीव रंजन तिवारी

दुनिया जानती है कि हर दृष्टिकोण से सर्वाधिक ताक़तवर सिर्फ़ अमेरिका है, लेकिन बीच-बीच में चीन के उछलने से कई सवाल खड़े होते रहते हैं. ख़ासकर तब, जब वह पाकिस्तान जैसे देश के संरक्षण के लिए लाठी लेकर खड़ा दिखता है. हालांकि चीन को यह पता है कि पाकिस्तान यदि अमेरिका या भारत के विरुद्ध कुछ करना तो दूर की बात, कूटनीतिक रूप से ऐसा सोच भी ले तो ये दोनों देश उसकी ईंट से ईंट बजा देने की क्षमता रखते हैं. यदि बीच में चीन आ जाए तो उसे भी सबक सिखा सकते हैं. इस स्थिति में यह सोचनीय है कि अमेरिका और भारत जैसी शक्तियों को छोड़ चीन पाकिस्तान जैसे डूबते जहाज पर सवारी करने को क्यों बेक़रार रहता है. यह किसी से छिपा नहीं है कि आज पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक यानी हर तरह के गंभीर संकट से दो-चार है. पूरे देश में बदहाली का आलम है. अवाम परेशान है, समस्याओं का अंबार है. हाल में चीन यात्रा से लौटे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने एक बयान में चीन को भरोसेमंद दोस्त बताया है. उन्होंने कहा कि चीन ने संकट की घड़ी में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है. बकौल गिलानी, चीन हर परीक्षण पर खरा उतरा है और हर तरह के हालात में पाकिस्तान का दोस्त रहा है. पाकिस्तान और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों के साठ साल पूरे होने के अवसर पर यूसुफ रजा गिलानी चीन पहुंचे थे.

पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद गिलानी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है. वहीं गिलानी की इस मुंहजबानी दरियादिली से ख़ुश होकर चीन ने हर हाल में उसकी मदद करते रहने का आश्वासन दिया है. उसने पाकिस्तान को 50 से अधिक लड़ाकू विमान देने पर सहमति जताई है. गिलानी के साथ चीन गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने बीजिंग में कहा कि चीन ने पाक को 50 से ज़्यादा जेएफ़-17 थंडर लड़ाकू विमान देने का फ़ैसला लिया है. ये लड़ाकू विमान छह महीनों के भीतर पाकिस्तान को मिल जाएंगे. हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया है. ख़ैर, यदि मुख्तार की ही बात मानें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान की मदद के लिए चीन हर वक़्त अपने बटुए का मुंह खोले रहता है. यदि हालात की समीक्षा करें तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि चीन ने पाकिस्तान की मदद करते रहने का जो बीड़ा उठाया है, वह उसकी (पाकिस्तान) गिड़गिड़ाहट का परिणाम है. वरना चीन वहीं चारा फेंकता है, जहां से उसे कुछ मिलने वाला होता है. यानी चीन की छवि एक पेशेवर देश की है. वह अनायास किसी से दोस्ती अथवा दुश्मनी नहीं करता.

अब यदि पाकिस्तान की चर्चा करें तो पता चलेगा कि चीन के आगे उसके गिड़गिड़ाने का अनुमान इसलिए लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर आतंक के पर्याय ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिका और उसके दूसरे सहयोगी देशों द्वारा उसे लगातार फटकार लगाई जा रही है. पाकिस्तान को डर है कि यदि इन देशों की मदद बंद हो जाए तो उसे रोटी के लाले पड़ जाएंगे और अवाम जीना मुहाल कर देगी. बावजूद इसके, जानकार यह मानते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने चीन की यात्रा कर अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के पास चीन की शक्ल में एक मज़बूत कूटनीतिक विकल्प मौजूद है. ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद आतंकवाद के ख़िलाफ़ चल रहे युद्ध में आईएसआई की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिका सहित कई देशों ने पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की है कि पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसियों को ओसामा बिन लादेन की जानकारी क्यों नहीं थी. वहीं चीन एकमात्र ऐसा देश है, जिसने ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और कहा कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध में पाकिस्तान की सफलताओं को याद रखना चाहिए. चीन से मिले समर्थन की बदौलत ही पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका ने बिना बताए अभियान चलाकर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है. वरना पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कहां, जो वह अमेरिका के बारे में इस तरह की तल्ख टिप्पणी करे.

रहा सवाल चीन का तो वह अपनी आदतों के मुताबिक़ दुनिया के उन सभी देशों का दोस्त बना रहेगा, जिनकी भारत और अमेरिका से दुश्मनी है. जैसे भारत-पाकिस्तान के बीच तकरार है तो वह (चीन) पाकिस्तान के साथ है. कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका और भारत दक्षिण कोरिया के साथ हैं तो चीन उत्तर कोरिया के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है. यानी चीन को वह सब कुछ करना अच्छा लगता है, जो भारत और अमेरिका को पसंद नहीं है. चीन का दूसरा रूप यह भी है कि वह अन्य देशों से अलग विशुद्ध रूप से एक व्यवसायिक देश की छवि बनाए हुए है. यानी उसे दुनिया में बाज़ार चाहिए, जिसमें वह अपने सामान बेचकर तेजी से विदेशी मुद्रा अर्जित करे और वह ऐसा कर भी रहा है. चीन के प्रति भारत और अमेरिका के रुख़ को देखकर तो यही लगता है कि ये दोनों उसे एक व्यवसायिक देश के रूप में ही देखते हैं. चीन की इस छवि में उसकी छोटी-छोटी खामियां छिप जाती हैं. नतीजतन, उसे जानबूझ कर नज़रअंदाज़ भी किया जाता है. वैसे यह ठीक नहीं है, क्योंकि तेजी से आर्थिक रूप से समृद्ध होता चीन भविष्य में भारत-अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है. इसलिए इस ओर समय रहते ध्यान दिया जाना चाहिए, वरना कहानी बिगड़ सकती है. बहरहाल, यूसुफ रज़ा गिलानी की चीन यात्रा से लगता है कि पाकिस्तान भारत और अमेरिका के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मज़बूत सहयोगी की तलाश में है. इस मामले में चीन ने उसकी मदद करने की वचनबद्धता दोहराई है. यदि पूरे प्रकरण को कूटनीतिक नज़रिए से देखें तो भारत और अमेरिका को चाहिए कि वे इस तरह के मसलों पर अपना व्यापक और संवेदनशील दृष्टिकोण बनाए रखें, ताकि पाकिस्तान का चीन जैसा दोस्त सिर न उठा सके.

feedback@chauthiduniya.com

यूरोपीय शिष्टमंडल और हुर्रियत की लादेनपरस्ती

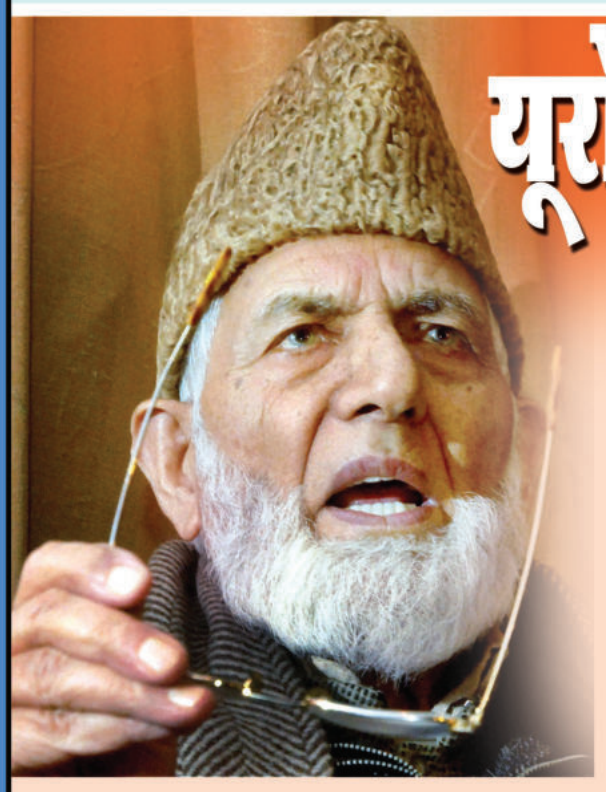

हुर्रियत कांफ्रेंस की लादेनपरस्ती ने उसे एक बार फिर कठघरे में खड़ा किया है. कश्मीर यात्रा पर आए यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल की गतिविधियों से तो यही लगता है. यूरोपीय संघ के राजनयिकों द्वारा हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने से मना करना कई अर्थों को जन्म दे रहा है. कहा जा रहा है कि अलक़ायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के नमाज़े जनाज़ा के आयोजन से नाराज़ होकर यूरोपीय राजनयिकों ने यह क़दम उठाया. हालांकि शिष्टमंडल की ओर से सिर्फ़ इतना कहा गया कि गिलानी के साथ 14 मई को बैठक होनी थी, लेकिन नवीनतम घटनाओं के मद्देनज़र शिष्टमंडल ने यह बैठक करना उपयुक्त नहीं समझा. उल्लेखनीय है कि बीती छह मई को गिलानी ने लादेन के लिए नमाज़े जनाज़ा का आयोजन किया था, जिसमें कश्मीर बार एसोसिएशन ने भी हिस्सा लिया था. इसलिए शिष्टमंडल ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मिलने से मना कर दिया. जिस लादेन को अमेरिका समेत दुनिया के कई देश बेसब्री से ढूंढ रहे थे, उसके प्रति हुर्रियत का यह रवैया यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल को नागवार गुजरा है. चिंता का विषय यह है कि हुर्रियत कांफ्रेंस जो समय-समय पर भारत के हितों की भी बात करती रहती है, उसकी गतिविधियां उसे कठघरे में खड़ा कर रही हैं.

शिष्टमंडल के उक्त निर्णय पर गिलानी धड़े की प्रतिक्रिया भी नाहक सी लगती है, क्योंकि गिलानी ने जो किया है, वह निश्चित रूप से लादेनपरस्ती की ओर संकेत करता है. गिलानी समर्थकों का यह कहना कि हुर्रियत के साथ बैठक रद्द करके शिष्टमंडल ने कश्मीरी जनता की इच्छा का अपमान किया है, ग़लत है. कश्मीर के अधिकांश लोग आतंकवाद और लादेन विरोधी हैं. फिर इसमें उनके अपमान की बात कहां से आती है. हुर्रियत के प्रवक्ता अयाज़ अकबर ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ओसामा के तरीक़ों से हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन उसके शव का निरादर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था. हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय संघ, जो मानवाधिकारों का मसीहा होने का दावा करता है, इस शर्मनाक घटना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा. बार एसोसिएशन के महासचिव गुलाम नबी शाहीन का कहना था कि यूरोपीय शिष्टमंडल के साथ बैठक बिल्कुल आख़िरी वक़्त पर रद्द की गई. शिष्टमंडल के सदस्य जम्मू कश्मीर में तथ्यों का पता लगाने आए थे, लेकिन उन्हें समाज के ज़रूरी लोगों से मिलने नहीं दिया गया या फिर वे स्वयं यहां की ज़मीनी सच्चाई को जानना नहीं चाहते थे. बार एसोसिएशन ने यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें उसने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है.

ओसामा बिन लादेन के लिए ग़ायबाना (जो मौजूद न हो) जनाज़े की नमाज़ का आयोजन किया गया था. हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के नेता गिलानी ने कहा कि ओसामा शहीद हुए हैं और एक शहीद को यह सम्मान देना उनकी ज़िम्मेदारी है. गिलानी ने एक स्थानीय इमाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों के साथ नमाज़े जनाज़ा अदा की. गिलानी ने कहा कि धार्मिक नेताओं में इस बात को लेकर बेहद रोष है कि लादेन के शहीद होने के बाद उन्हें समुद्र में दफ़ना दिया गया. नमाज़े जनाज़ा के ज़रिए हमने अपनी धार्मिक ज़िम्मेदारी निभाई है. गिलानी ने आम लोगों से नमाज़ के लिए जुटने की अपील की और कहा कि नमाज़ के बाद वे ओसामा के लिए दुआ करें. गिलानी के आह्वान पर भारत प्रशासित कश्मीर के कई शहरों और कई मस्जिदों में ओसामा के लिए नमाज़ पढ़ी गई. नमाज़ के बाद गिलानी ने कहा कि उनकी दुआएं पाकिस्तान के साथ भी हैं, क्योंकि वह एक मुस्लिम देश है और उसे पूरी दुनिया से ख़तरे का सामना करना पड़ रहा है.

पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद धार्मिक गुटों के आह्वान पर विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किए गए. उल्लेखनीय है कि यूरोपीय शिष्टमंडल ने कश्मीर के गवर्नर एन एन वोहरा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती, पीसीसी के प्रमुख सैफ़ुद्दीन सोज़, हुर्रियत के उदारवादी नेता मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ और जेकेएलएफ़ के अध्यक्ष यासीन मलिक से मुलाक़ात की. मालूम हो कि 2002 में यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि हैवियर सोलाना ने भारत के इस कथन से सहमति व्यक्त की थी कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और घुसपैठ पर स्थायी रोक लगानी होगी. सोलाना ने यह भी कहा था कि यूरोपीय संघ जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों की उम्मीद कर रहा है. भारत-यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों पर चर्चा करने आए सोलाना ने तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दे पर भी बात की थी. यशवंत सिन्हा ने कहा था कि अफ़ग़ानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के प्रयासों को काफी तेज करना होगा. इस मुलाक़ात के दौरान सोलाना ने कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी नेताओं की भी चर्चा की थी, जो भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से हमदर्दी रखते हैं. बहरहाल, मौजूदा हालात में यूरोपीय शिष्टमंडल द्वारा गिलानी से मुलाक़ात न करने का निर्णय ग़लत नहीं लगता, क्योंकि गिलानी ने अपनी कार्यशैली से अपनी अहमियत घटा दी है. देखना यह है कि गिलानी की इस गतिविधि को भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार किस नज़रिए से देखती है.

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

बस करो मां, बस भी करो, तुम्हारे पैर इतनी देर तक नाचते-नाचते थक गए होंगे, साई बाबा ने कहा और नर्तकी के पैर दबाने लगे.

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए
स्व. मालती कपूर

दयालु साईं बाबा

साई बाबा ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, फ़ौरन उतर जा. तुम्हें कुछ नहीं होगा पंडित जी...तुम्हें कुछ नहीं होगा...यह तुम्हारी आत्मा का सारा पाप ख़त्म कर देगा. पंडित जी लगभग बेहोश हो गए थे उनके मुंह से झाग निकल रहा था. सारा शरीर लगभग नीला पड़ चुका था, बड़बड़ाना शुरू हो गया था. सबको पंडित जी की हालत देखकर यह विश्वास हो चला था कि अब उनका बचना संभव नहीं है. साई बाबा ने पंडित जी का सिर अपनी गोद में रख लिया था और बार-बार बड़बड़ा रहे थे, चला जा, चला जा.

साई बाबा खाना खाने के बाद अपने भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक सारंगी के सुरों के साथ तबले पर पड़ी थाप से मस्जिद की गुम्बदें और मीनारें गूंज उठीं. सब लोग चौंक उठे. दूसरे ही क्षण मस्जिद के दालान में सारंगी के सुरों और तबले की थापों के साथ घुंघरुओं की रुनझुन भी गूंज उठी. सभी शिष्य एक रूपसी नवयौवना की ओर देखने लगे. सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वह कहां से आ गई. ज़रूर किसी आसपास के गांव की होगी. उसका नृत्य करना भी बड़ा आश्चर्यजनक था. वह नाचती रही. घुंघरुओं की रुनझुन, सारंगी के सुर और तबलों की थाप बराबर गूंजती रही. अचानक साई बाबा धीरे से उठे और नर्तकी की ओर बढ़ने लगे. नर्तकी नाच रही थी. साई बाबा एक पल उसे देखते रहे और फिर उन्होंने एकदम झुककर नर्तकी के थिरकते पैर पकड़ लिए. बस करो मां, बस भी करो, तुम्हारे पैर इतनी देर तक नाचते-नाचते थक गए होंगे, साई बाबा ने कहा और नर्तकी के पैर दबाने लगे. थिरकते पैर एकदम रुक गए, घुंघरू थम गए. तभी एक दर्दभरी चीख सुनाई दी, बचाओ...बचाओ...सांप...सांप...

सबने चौंक कर उस तरफ़ देखा, जिधर से आवाज़ आ रही थी. मस्जिद के खंभे के पीछे पंडित और गणेश खड़े थे. दोनों के सामने काला नाग फन फैलाए खड़ा था. उसने पंडित जी की कलाई में डस लिया था, वह छटपटाते हुए चीख रहे थे. अरे, नाग कहां से आया? कई लोग चौंक कर बोले. साई बाबा मुस्कराते हुए उस नाग की ओर बढ़ने लगे. देखते-देखते वह नाग मोटी रस्सी में बदल गया. लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही. थर-थर कांपते हुए गणेश ने एक नज़र उस रस्सी पर डाली और साई बाबा के पैर पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं पापी हूं, सारा कसूर मेरा ही है, कहते-कहते वह रोने लगा. नर्तकी का सारा बदन भय से कांप रहा था. साई बाबा, मुझे माफ...कर दो...मैं तुम्हें...अपना शत्रु...समझता रहा. मेरे सारे शरीर में ज़हर फैल चुका है. मुझे क्षमा कर दो...साई बाबा...

साई बाबा ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, फ़ौरन उतर जा. तुम्हें कुछ नहीं होगा पंडित जी...तुम्हें कुछ नहीं होगा...यह तुम्हारी आत्मा का सारा पाप ख़त्म कर देगा. पंडित जी लगभग बेहोश हो गए थे उनके मुंह से झाग निकल रहा था. सारा शरीर लगभग नीला पड़ चुका था, बड़बड़ाना शुरू हो गया था. सबको पंडित जी की हालत देखकर यह विश्वास हो चला था कि अब उनका बचना संभव नहीं है. साई बाबा ने पंडित जी का सिर अपनी गोद में रख लिया था और बार-बार बड़बड़ा रहे थे, चला जा, चला जा. सब लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे. कुछ ही देर बाद पंडित जी के शरीर का रंग पहले की तरह हो गया, उनकी बंद आंखें खुलने लगीं. शरीर में मानो चेतना का संचार शुरू हो गया. पंडित जी का यह रूप परिवर्तन देख सबको राहत मिली. अब उनको यह विश्वास हो गया कि पंडित जी की जान बच गई.

साई बाबा का चमत्कार सभी आंखें फाड़े आश्चर्य से देख रहे थे. थोड़ा समय और बीता, पंडित जी उठकर बैठ गए, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो. तभी द्वारका माई मस्जिद की गुम्बदें और मीनारें साई बाबा की जय-जयकार से गूंज उठीं. इस तरह बाबा के चमत्कार से पंडित जी की जान बची.

ओम साई राम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

ज्ञानोदय

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है. -प्रेमचंद

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.
-स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा

प्यार की रोटी

मैं तो स्वयं दूसरों के अधीन हूं और पैसे ख़र्च करके जो मिल जाता है, वही खा लेती हूं. मैंने आपको उसमें से भोजन कराया...

शिरडी में रहते हुए एक बार बाबा साहब की पत्नी श्रीमती तर्खड दोपहर के समय खाना खाने बैठी थीं, तभी दरवाजे पर एक भूखा कुत्ता आकर भौंकने लगा. श्रीमती तर्खड ने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर उस कुत्ते के सामने डाल दी, कुत्ता उस रोटी को बड़े प्रेम से खा गया. उसी समय वहां कीचड़ से सना हुआ एक सूअर आया तो उन्होंने उसे भी रोटी दे दी. यह एक सामान्य घटना थी, जिसे वह भूल गईं. शाम को जब श्रीमती तर्खड मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गईं तो बाबा उनसे बोले, मां, आज तो तुमने मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाया. खाना खाकर मेरा मन तृप्त हो गया, ज़िंदगी भर ऐसे ही खाना खिलाती रहना, एक दिन तुम्हें इसका उचित फल मिलेगा, मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं कहता. पहले तुम भूखों को भोजन खिलाना और फिर ख़ुद खाना, इस बात का सदा ध्यान रखना.

श्रीमती तर्खड बाबा की बात का अर्थ नहीं समझ पाईं और बाबा से कहा, हे देवा, मैं भला आपको कैसे भोजन करा सकती हूं? मैं तो स्वयं दूसरों के अधीन हूं और पैसे ख़र्च करके जो मिल जाता है, वही खा लेती हूं. मैंने आपको उसमें से भोजन कराया, मुझे तो ऐसा याद नहीं. बाबा बोले, मां, आज दोपहर में तुमने जिस कुत्ते और सूअर को रोटी दी थी, वे मेरे ही रूप थे. इसी तरह जितने भी अन्य प्राणी हैं, वे सब मेरे ही प्रतिरूप हैं. मैं उनके रूप में सर्वत्र व्याप्त हूं. जो सभी जीवों में मुझे देखता है यानी मेरे दर्शन करता है, वह मुझे अति प्रिय है. तुम इसी तरह समभाव से मेरी सेवा करती रहो. साई बाबा के इन अमृत वचनों को सुनकर श्रीमती तर्खड अत्यंत भावविह्वल हो गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, गला अवरुद्ध हो गया और अपार हर्ष होने लगा. उन्होंने साई बाबा के चरणों में अपना सिर झुका दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरकार के इस फ़ैसले के पीछे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वजहें तो हैं ही, पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण कारक है.

अनंत विजय

नक्सलियों को रोकने की क़वायद

अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की तरफ़ से वनवासियों एवं आदिवासियों के कल्याण और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए कई सकारात्मक क़दम उठाए गए हैं तथा अनेक पहल के संकेत भी मिले हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों से चौतरफा घिरी और विपक्ष के हमलों से हलकान केंद्र सरकार को अब देश के जंगलों और पिछड़े इलाक़ों में रहने वाले आदिवासियों और जंगल आधारित उत्पादों के सहारे जीवन बसर करने वाले लोगों की याद आई है. केंद्र सरकार की तरफ़ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह जंगली पेड़ों और उससे जुड़े उत्पाद को छोड़कर अन्य जंगली उत्पादों जैसे बांस, महुआ, तेंदू पत्ता आदि का समर्थन मूल्य तय करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार इनकी बिक्री और भंडारण के लिए कृषि उत्पाद और बिक्री कमीशन के अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तर्ज पर संस्थाएं बनाना चाहती है. ये जंगली उत्पाद लाखों वनवासियों के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन हैं, लेकिन पुरानी सरकारी नीतियों में इतनी खामियां हैं कि वनवासियों को अपने वाजिब हक़ के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है. सरकार के इस फ़ैसले के पीछे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वजहें तो हैं ही, पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण कारक है. पहली बात तो यह कि सरकार ऐसा करके राजनीतिक तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि वह आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों के हितों को लेकर गंभीर है. इस राजनीतिक कारण के पीछे हम सोनिया गांधी द्वारा कुछ दिनों पहले पार्टी के मुखपत्र कांग्रेस संदेश में लिखे उनके लेख में इसके संकेत पकड़ सकते हैं. अपने लेख में सोनिया गांधी ने सरकार को जंगली इलाक़ों में समावेशी विकास करने की सलाह दी थी. सोनिया गांधी का उक्त लेख छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों की जघन्य हत्या के बाद छपा था. सोनिया गांधी ने अपने लेख में नक्सल प्रभावित इलाक़ों में विकास के कामों पर जोर देने की सलाह दी थी. ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने वहीं से क्यू लेते हुए जंगली उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करने की योजना बनाई.

जंगली इलाक़ों में सक्रिय ठेकेदार और दलाल वहां के उत्पादों की ख़रीद–फरोख्त में मनमानी कर रहे हैं. जंगल के उन उत्पादों के बारे में कोई ठोस सरकारी नीति न होने या फिर दोषपूर्ण सरकारी नियमों की वजह से दलाल चांदी काट रहे हैं और आदिवासियों का जमकर शोषण हो रहा है. उन इलाक़ों में बिचौलिए ही जंगली उत्पादों की क़ीमतें तय करते हैं और भोले–भाले ग़रीब आदिवासियों को उनकी मेहनत के उचित मूल्य से महरूम कर देते हैं. बिचौलियों की यही भूमिका और ज़्यादती उन इलाक़ों में माओवादियों को वनवासियों के बीच अपनी ज़मीन पुख्ता करने का मौक़ा देती है. आदिवासियों के हक़ की बात करके और उनके शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर माओवादियों ने आदिवासियों का दिल जीता और उनके बीच अपनी पकड़ भी मज़बूत बनाई. अगर सरकार उन इलाक़ों में जंगली उत्पादों की बिक्री व्यवस्था को दुरुस्त कर और उसके भंडारण के लिए उचित इंतज़ाम कर सके तो यह एक बड़ी सफलता होगी. फूड कॉरपोरेशन जैसी कोई संस्था बनाकर अगर जंगली उत्पादों के उन्हीं इलाक़ों में भंडारण की व्यवस्था हो सके तो आदिवासियों को उनके उत्पादों का ज़्यादा दाम मिल पाएगा. इसका एक बड़ा फ़ायदा यह होगा कि उन इलाक़ों में नक्सलियों और माओवादियों की लोकप्रियता कम होगी और उनको कमज़ोर किया जा सकेगा.

इस तरह की योजना बनाते समय सरकार को देश के अलग–अलग इलाक़ों के लिए अलहदा योजना बनानी होगी. पूरे देश में अगर एकीकृत समर्थन मूल्य की नीति बनाई जाएगी तो वह दोषपूर्ण होगी, क्योंकि देश के अलग–अलग हिस्सों में इन उत्पादों की आपूर्ति और बाज़ार अलग है. इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि इलाक़े को ध्यान में रखकर वहां इन उत्पादों के भंडारण का इंतज़ाम किया जा सके, ताकि जब बाज़ार में मूल्य अधिक मिल रहा हो, उस वक़्त इन उत्पादों को बेचकर आदिवासियों को ज़्यादा मुनाफ़ा हो. इस व्यवस्था को बनाते वक़्त सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि फूड कॉरपोरेशन की तरह यहां अनियमितताएं और भ्रष्टाचार न हो. अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाने में नाकाम रहती है तो आदिवासी और उनके उत्पाद निजी ठेकेदारों और दलालों के चंगुल से मुक़्त होकर सरकारी और अर्ध सरकारी दलालों के चंगुल में फंस जाएंगे. दूसरा अहम बदलाव, जिस पर सरकार विचार कर रही है या यू कहें कि केंद्रीय कैबिनेट ने फ़ैसला ले लिया है, वह यह है कि बांस को लकड़ी न मानकर घास माना जाए, लेकिन इसका नोटिफिकेशन होना अभी शेष है.

भारतीय वन अधिनियम के तहत अब तक बांस को लकड़ी माना जाता रहा है, जिसकी वजह से किसी को भी बांस काटने के लिए तमाम सरकारी महकमों से इजाज़त लेनी पड़ती है. इस इजाज़त की जड़ से भ्रष्टाचार पनपता है और शोषण की भी नींव पड़ती है. बांस को घास मानने की बहस बेहद लंबी है और काफी समय से चल रही है. वनस्पति विज्ञान में भी बांस को घास ही माना गया है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के क़ानून में बदलाव की फ़िक्र हमें आज़ादी के 63 सालों बाद हो रही है. अगर बांस को लकड़ी मानने के क़ानून से आज़ाद कर दिया जाता है तो तक़रीबन दस हज़ार करोड़ के बांस आधारित उद्योग से वनवासियों को काफी लाभ मिलेगा और देश में नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

साहित्यकार समाज सुधारक नहीं होता

नवोदित उपन्यासकार महुआ माजी का मानना है कि साहित्यकार समाज सुधारक नहीं होता. वह सिर्फ लिखता है, ताकि लोग उस विषय पर मंथन करें कि क्या सही है और क्या ग़लत. अपने उपन्यास मैं बोरिशाइल्ला के लिए वर्ष 2007 में अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान पाने वाली महुआ माजी रांची की रहने वाली हैं. पिछले दिनों चौथी दुनिया के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आईं महुआ माजी से फ़िरदौस ख़ान ने एक लंबी बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

महुआ माजी

● सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए?

मेरा जन्म रांची में हुआ. मैंने समाजशास्त्र में एमए किया और फिर पीएचडी. 17 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हो गया. मैंने अपनी पढ़ाई विवाह के बाद पूरी की. लेखन के लिए मुझे कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान भी शामिल है.

● घरेलू महिला से लेखिका बनने तक का सफ़र कैसे तय किया?

मेरी एक सहेली थी, वह अख़बारों में लिखती थी. उसने मेरी कुछ कविताएं अख़बारों में प्रकाशित कराईं और उसी के बाद से लिखने का सिलसिला शुरू हो गया. इसके साथ ही मैं कुछ साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ गई, उनकी गोष्ठियों में जाने लगी. इस तरह लेखन का वातावरण बनता गया और मेरी रचनाएं विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं.

● बांग्लाभाषी होकर हिंदी में उपन्यास लिखने का विचार कैसे आया?

मेरे पूर्वज बांग्लादेश के रहने वाले थे, लेकिन हमारे घर में हिंदी ही बोली जाती है और मेरी शिक्षा भी हिंदी में ही हुई है, इसलिए मैंने हिंदी को लेखन का माध्यम बनाया.

● मैं बोरिशाइल्ला के विषय में कुछ बताइए?

बांग्लादेश में एक सांस्कृतिक जगह है बोरिशाल. बोरिशाल के रहने वाले एक पात्र से शुरू हुई यह कथा पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र के जन्म तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उन परिस्थितियों की भी पड़ताल करती है, जिनमें सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ और फिर भाषाई एवं भौगोलिक आधार पर पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना. उपन्यास में उस दौरान हुईं लूट, हत्या, बलात्कार एवं आगज़नी की घटनाओं, मानवीय आधार पर भारतीय सेना द्वारा पहुंचाई गई मदद, मुक्तिवाहिनी को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सीमा क्षेत्र में बनाए गए प्रशिक्षण शिविरों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की भूमिका का ज़िक्र किया गया है.

● यह कथानक क्यों चुना?

लड़ाई धर्म की नहीं होती, बल्कि स्वार्थ की होती है. इंसान स्वार्थ को धर्म का नाम दे देता है, केवल यही बात पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है. यह बात मैंने अपने उपन्यास के एक पात्र के माध्यम से सामने रखी है, जो घरों, इंसानों और इंसानियत को जलते हुए देख रहा था. धार्मिक उन्माद की उस आंच से झुलसते हुए इंसानों को देखकर वह सोच रहा था कि क्या यह लड़ाई वाक़ई धर्म की लड़ाई है? क्या यह उन्माद सिर्फ़ धर्म के लिए है? यदि ऐसा होता तो धर्म के नाम पर भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में अवश्य गहरा रिश्ता होता, प्यार का रिश्ता होता. दोनों हिस्सों के समानधर्मी भाइयों के बीच इतिहास का यह क्रूर अध्याय न लिखा गया होता. क्या धर्म से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और तत्व हैं, जो धर्म के साथ शामिल हैं या धर्म उनमें शामिल है? क्या हैं वे तत्व? यह तो हम सबने देखा कि पूर्वी पाकिस्तानियों के लिए धर्म से अधिक महत्वपूर्ण संस्कृति रही. तभी तो बांग्ला भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के लिए भाषा आंदोलन हुआ और फिर तो आंदोलनों का एक सिलसिला शुरू हो गया. पश्चिमी पाकिस्तानियों के लिए निश्चय ही धर्म से अधिक महत्वपूर्ण सत्ता रही. वर्चस्व का सुख, शोषण से प्राप्त ऐश्वर्य का सुख हमेशा उनके धर्म पर हावी रहा. इसका मतलब यह है कि धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना जताया जाता है. महत्वपूर्ण होते हैं दूसरे कारक. धर्म तो सिर्फ़ एक मुखौटा है, जिसके सहारे कुछ लोग अपना स्वार्थ साधते हैं.

● लेखन को लेकर भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

झारखंड के आदिवासी जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिख रही हूं. इसमें आदिवासियों की समस्याओं, उनके संघर्ष और डायन जैसी कुप्रथा का उल्लेख किया गया है. इसमें बताया गया है कि आदिवासी किस तरह संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं.

● आप कवयित्री भी हैं, आपने कविता संग्रह के बारे में अभी तक क्यों नहीं सोचा?

हां, मैंने कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन मुझे अपनी कविताएं हल्की लगती हैं. इसलिए कविता संग्रह के बारे में कभी नहीं सोचा. वैसे आलोचक मेरा उपन्यास पढ़कर कहते हैं कि यह एक कविता ही है. मेरी कहानियों के बारे में भी कहा जाता है कि वे कविताएं ही होती हैं. मैं कविता को कहानी और उपन्यास में इस्तेमाल करती हूं.

● देश और समाज के प्रति एक साहित्यकार की क्या ज़िम्मेदारी है?

साहित्यकार कोई समाज सुधारक नहीं होता है. वह समाज में जो कुछ देखता है, उसे ही लिखता है. उसका काम तो समाज की समस्याओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना और लोगों को उनके समाधान के लिए जगाना है. दु:ख इस बात का है कि हमेशा ऐसा हो नहीं पाता. अपनी फिल्मों को ही लीजिए, फिल्मकार सीता के दु:ख को तो संवेदनशीलता के साथ दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उर्मिला के दु:ख के बारे में नहीं सोचते. सीता तो फिर भी अपने पति राम के साथ रहीं, लेकिन उर्मिला ने तो अपने पति लक्ष्मण के बिना 14 वर्ष बिताए. यहां उर्मिला के साथ न्याय नहीं किया गया.

● देश और समाज से लेखक ख़ुद क्या अपेक्षा रखता है?

साहित्यकार देश और समाज से यही अपेक्षा रखता है कि वह उसकी रचनाओं को पढ़े और उस पर विचार करे. विचार और विकास व्यक्तिवादी न होकर समूहवादी होना चाहिए. विकास का नया मॉडल आना चाहिए. सुख–सुविधाएं जुटाना ही विकास नहीं है. प्रकृति हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन लालच का निवारण नहीं कर सकती. प्रकृति के अत्यधिक दोहन से समस्याएं पैदा होती हैं. देश और समाज को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए.

● साहित्यकार ख़ुश कब होता है और दु:खी कब होता है?

समाज में फैली विसंगतियों को देखकर साहित्यकार को दु:ख होता है, लेकिन जब उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है तो उसे ख़ुशी होती है, जैसे भ्रष्टाचार के मामले में अन्ना हज़ारे के आंदोलन ने लोगों में एक आस पैदा की.

● महिला लेखकों की स्थिति के बारे में आप क्या सोचती हैं?

वे अच्छा लिख रही हैं. पहले महिलाओं के लिए एक निश्चित दायरा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वे खुलकर लिख रही हैं. जिन विषयों के बारे में पहले महिलाएं लिखते हुए यह सोचती थीं कि लोग क्या कहेंगे, अब वे उन पर भी बेबाकी से क़लम चला रही हैं.

● लेखकों में आप किससे प्रभावित हैं और लेखिकाओं में आपको कौन पसंद है और क्यों?

मैं हर लेखक की हर कृति से प्रभावित नहीं होती. विभिन्न लेखकों एवं लेखिकाओं की ऐसी कृतियां प्रभावित करती हैं, जो कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दें, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती.

● युवा लेखकों के लिए आपका क्या संदेश है?

उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, अपनी भाषा को साधना और ख़ुद को लगातार मांजते रहना चाहिए.

firdaus@chauthiduniya.com

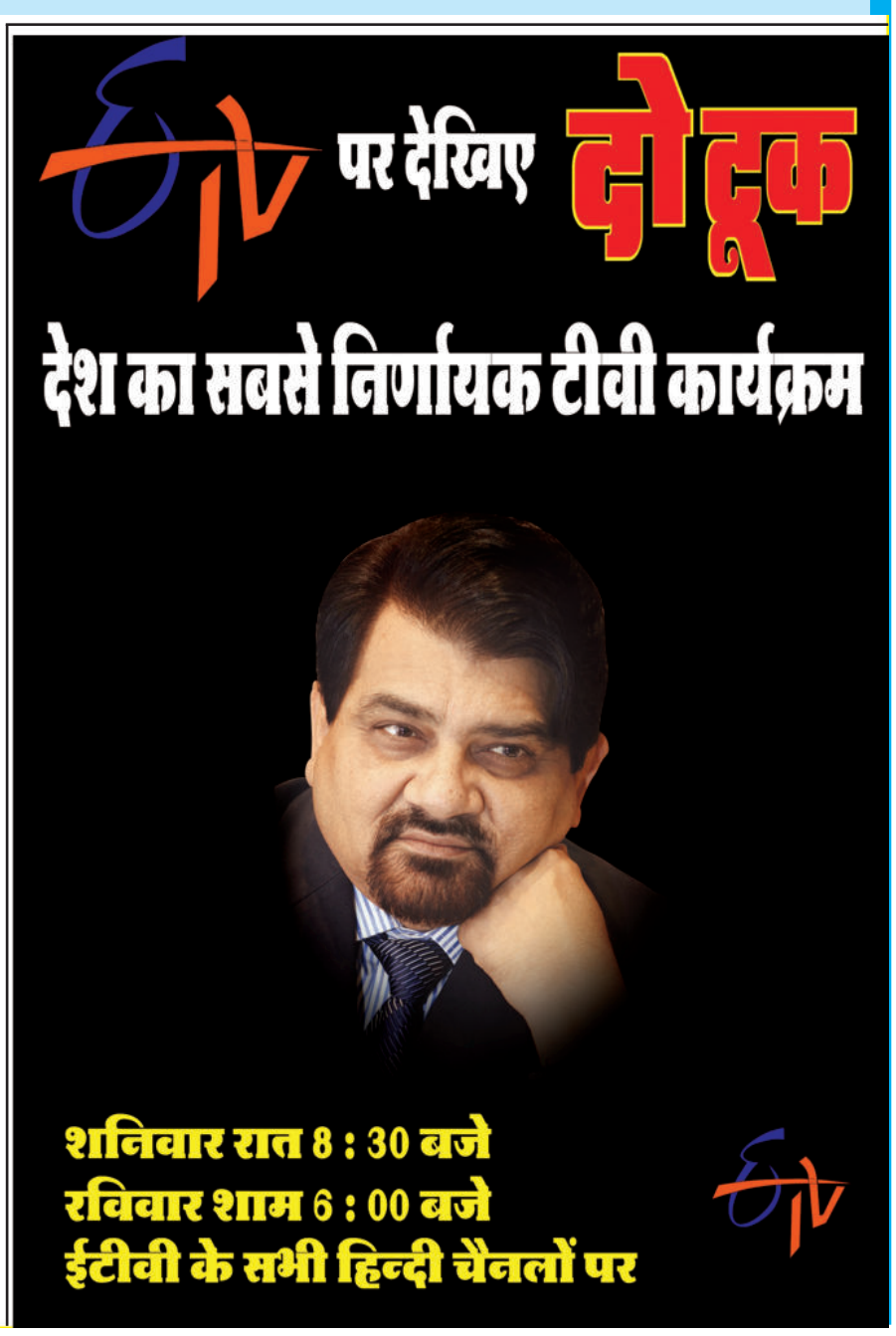

नए वर्जन में आईपॉड का वजन 101 ग्राम है. इस आईपॉड की चमकीली बॉडी पर पहले के मुक़ाबले कम स्क्रेच आएंगे.

एचटीसी ईएमईए के नए फ्लेयर टेबलेट्स

एचटीसी ईएमईए ने बाज़ार में एचटीसी फ्लेयर टेबलेट उतारे हैं. इन टेबलेट में 3 जी वाईफाई कनेक्शन की सुविधा मौजूद है. 7 इंच स्क्रीन वाले इस टेबलेट में 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है. उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीक से लैस इस टेबलेट में 3 डी डिस्प्ले है. उपभोक्ता इसमें हाई स्पीड के वायरलेस कनेक्शन केसाथ ही एचटीएमएल 5 और फ्लैश के साथ वेब ब्राउजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा भी मौजूद है. इसकी क़ीमत लगभग 600 डॉलर और 480 डॉलर रखी गई है. अभी इसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में लांच किया गया है. जल्द ही इसके भारत में भी लांच होने की उम्मीद है.

उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीक से लैस इस टेबलेट में 3 डी डिस्प्ले है. उपभोक्ता इसमें हाई स्पीड के वायरलेस कनेक्शन केसाथ ही एचटीएमएल 5 और फ्लैश के साथ वेब ब्राउजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा भी मौजूद है.

ऐसर की नई डिवाइस रेंज

इन डिवाइस में 250 डबल कोर्टेक्स ए-9 प्रोसेसर लगाया गया है. साथ ही 512 मेगाबाइट डीडीआर-2 रैम मेमोरी भी लगाई गई है.

ऐसर ने हाल में नए डिवाइसेस की रेंज बाज़ार में उतारी है. इस रेंज की डिवाइस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये ज़्यादा कारगर और बेहतर हैं. इन डिवाइस में 250 डबल कोर्टेक्स ए–9 प्रोसेसर लगाया गया है. साथ ही 512 मेगाबाइट डीडीआर–2 रैम मेमोरी भी लगाई गई है. ईएमएमसी 8 जीबी की हार्डड्राइव भी इन डिवाइस में लगाई गई है. अगर उपभोक्ताओं को ज़्यादा स्टोरेज क्षमता चाहिए तो उसका इंतज़ाम भी इन डिवाइस में है. इनमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर इनकी स्टोरेज क्षमता को 2 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. 3 जी सुविधा से युक्त इन डिवाइस में 7 इंच की टचस्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे उपभोक्ता मल्टी मीडिया सुविधा को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है.

एप्पल का आईपॉड अब नई खूबियों के साथ

कुछ ही महीनों पहले जब एप्पल ने आईपैड भारत में लांच किया तो भारतीयों ने उसे हाथोंहाथ लिया. अपने उत्पादों की भारत में शानदार कामयाबी के बाद एप्पल ने आख़िरकार अपना बहुप्रतीक्षित एप्पल आईपैड–2 भी लांच कर दिया है. देखने में बेहद स्टाइलिश और ख़ूबसूरत फीचरों वाले एप्पल आईपैड–2 का वाई–फाई वर्जन अब हिंदुस्तानियों की भी पहुंच में हो गया. एप्पल आईपैड–2 में 9.7 इंच का एलईडी–बैकलिट एलसीडी स्क्रीन, ड्युएल कोर ए 5 प्रोसेसर है. एप्पल आईपैड–2 के फ्रंट फेसिंग वीजेए कैमरे को फेस टाइम और ब्लूटूथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं आईपैड–2 के रियर फेसिंग कैमरे से 720 पी के वीडियो और क्रिस्प फोटोग्राफी की जा सकेगी. इस बेहद कम वजन वाले आईपैड की बैटरी लाइफ 10 घंटे की है. 16 जीबी के वाई–फाई एप्पल आईपैड–2 की क़ीमत 29,500 रुपये है. आईपैड–2 का 64 जीबी वाई–फाई प्लस थ्री जी मॉडल 46,900 रुपये में बाज़ार में मौजूद है. एप्पल को अपने उत्पादों में लगातार सुधार के लिए जाना जाता है. अपनी इसी पहचान के तहत कंपनी ने पहले लांच किए जा चुके टच 4 जी आईपॉड में कुछ बदलाव करके इसका नया वर्जन बाज़ार में पेश किया है. इस आईपॉड को पहले की तुलना में हल्का बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक़, नए वर्जन में आईपॉड का वजन 101 ग्राम है. इस आईपॉड की चमकीली बॉडी पर पहले के मुक़ाबले कम स्क्रेच आएंगे. नए वर्जन में 960 बाई 640 पिक्सल रेजोल्यूशन वाले दो कैमरे हैं, जिनसे ज़्यादा साफ और स्पष्ट तस्वीर खींची जा सकती है. इस आईपॉड का आकार 111 एमएम बाई 58.9 एमएम बाई 7.2 एमएम है. साथ ही 3.5 इंच आकार वाली टच स्क्रीन पहले के मुक़ाबले ज़्यादा स्पष्ट है.

16 जीबी के वाई–फाई एप्पल आईपैड–2 की क़ीमत 29,500 रुपये है. आईपैड–2 का 64 जीबी वाई–फाई प्लस थ्री जी मॉडल 46,900 रुपये में बाज़ार में मौजूद है. एप्पल को अपने उत्पादों में लगातार सुधार के लिए जाना जाता है.

ओलंपस का नया लाइनर पीसीएम रिकॉर्डर

कंपनी ओलंपस ने हाल में एसजेड-30 एमआर कैमरा लांच करने के बाद एलएस-20 एम लाइनर पीसीएम बाज़ार में उतारने की घोषणा की है.

जीवन में कुछ निजी यादगार पलों को संजोने, शादी या किसी अन्य समारोह में अच्छी गुणवत्तायुक्त पिक्चर्स या वीडियो बनाने के लिए अब आपके हाथ में होगा एक विश्वसनीय साथी. कंपनी ओलंपस ने हाल में एसजेड–30 एमआर कैमरा लांच करने के बाद एलएस–20 एम लाइनर पीसीएम बाज़ार में उतारने की घोषणा की है. कंपनी के मुताबिक़ , यह अपने आप में ऐसी पहली डिवाइस है, जो 1080 पी एचडी वीडियो बना और एडिट कर सकती है. उपभोक्ता इस डिवाइस से एचडी मूवी को तीन में से किसी भी एक फार्मेट में सेटिंग कर सकते हैं. यह एचडी वीडियो को स्पष्टता के साथ दिखाता है. इसमें सामने ही 2 इंची कलर एलसीडी डिस्प्ले भी है. इस डिवाइस से यूट्यूब, फेसबुक, आईट्यून एवं विमियो आदि किसी भी साइट पर वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं. इसमें लगे दो कंडेनसर माइक्स के कारण इस डिवाइस से रिकॉर्ड की गई आवाज की क्वालिटी काफी बेहतर होती है.

स्टेलर का फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर

अक्सर कई बार ग़लती से या अनजाने में कई सारे ऐसे फोटो डिलीट हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत यादगार होते हैं. लेकिन अब इस समस्या का समाधान बाज़ार में मौजूद है. ग़लती से डिलीट यादगार फोटो को फिर से पा सकेंगे आप. ऐसा दावा किया है स्टेलर कंपनी ने. स्टेलर इंफॉर्मेशन लिमिटेड ने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर बाज़ार में उतारा है, जिसकी मदद से आप अपने उन फोटो को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी कारणवश डिलीट हो गए.

कंपनी का कहना है कि यह सॉफ्टवेयर डिजिटल कैमरा, मेमोरी कार्ड्स, कंप्यूटर हार्डड्राइव और मोबाइल फोन में काम कर सकता है. इस सॉफ्टवेयर को हर तरह के कंज्यूमर और प्रोफेशनल्स कैमरों में इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही इसे इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बहुत आसान है. इस सॉफ्टवेयर की क़ीमत 1660 से 1690 रुपये तक रखी गई है और यह हर जगह आसानी से उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से 20-20 वर्ल्डकप का फाइनल और अब वर्ल्डकप 2011 का सेमी फाइनल, दोनों बड़े मैच फ्लाप शो साबित हुए. इन दोनों मुक़ाबलों में टीम को भारत के ख़िलाफ़ हार झेलनी पड़ी.

भद्रजनों की अभद्रता

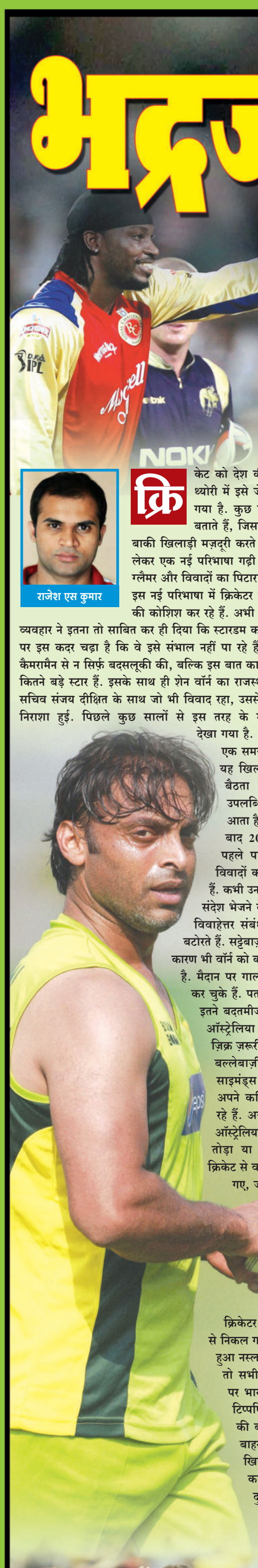

राजेश एस कुमार

क्रिकेट को देश की जनता धर्म मानती है तो थ्योरी में इसे जेंटलमैन गेम का दर्जा दिया गया है. कुछ लोग इसे सामंतों को खेल बताते हैं, जिसमें दो सामंती खेलते हैं और बाकी खिलाड़ी मज़दूरी करते हैं. लेकिन अब क्रिकेट को लेकर एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है. अब इसे पैसा, ग्लैमर और विवादों का पिटारा माना जा रहा है. ज़ाहिर है, इस नई परिभाषा में क्रिकेटर भी ख़ुद को सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हाल में क्रिस गेल के अभद्र व्यवहार ने इतना तो साबित कर ही दिया कि स्टारडम का नशा इन क्रिकेटरों के सिर पर इस कदर चढ़ा है कि वे इसे संभाल नहीं पा रहे हैं. गेल ने एक पत्रकार और कैमरामैन से न सिर्फ़ बदसलूकी की, बल्कि इस बात का भी एहसास कराया कि वह कितने बड़े स्टार हैं. इसके साथ ही शेन वॉर्न का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय दीक्षित के साथ जो भी विवाद रहा, उससे उनके प्रशंसकों को काफ़ी निराशा हुई. पिछले कुछ सालों से इस तरह के मामलों में खासा इज़ाफ़ा देखा गया है.

एक समय गेंदबाज़ी का सिरमौर रहा यह खिलाड़ी क्यों ऐसी ग़लती कर बैठता है, जिससे उसकी सारी उपलब्धियों पर पानी फिरता नज़र आता है. ड्रग टेस्ट में नाकाम होने के बाद 2003 के विश्वकप से ठीक पहले पाबंदी झेल चुके शेन वॉर्न विवादों का पिटारा साथ लेकर चलते हैं. कभी उन पर महिलाओं को अश्लील संदेश भेजने के आरोप लगते हैं तो कभी विवाहेत्तर संबंधों के कारण वह सुर्ख़ियां बटोरते हैं. सट्टेबाज़ों के साथ कथित रिश्तों के कारण भी वॉर्न को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी है. मैदान पर गाली-गलौज तो वह कई बार कर चुके हैं. पता नहीं, क्रिकेट के जेंटलमैन इतने बदतमीज क्यों होते जा रहे हैं. बात ऑस्ट्रेलिया की हो तो साइमंड्स का ज़िक्र ज़रूरी है. एक समय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ी की ज़रूरत बन चुके साइमंड्स आईपीएल में भी शायद अपने करियर का आख़िरी दौर देख रहे हैं. अजीब बात यह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से उस समय नाता तोड़ा या यूं कहें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से वह उस समय किनारे कर दिए गए, जब उनमें काफ़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बची थी, लेकिन मैदान और मैदान के बाहर अपने अजीबोग़रीब व्यवहार के कारण एक अच्छा क्रिकेटर असमय ऑस्ट्रेलियाई टीम से निकल गया. उनका हरभजन के साथ हुआ नस्लवादी टिप्पणी वाला किस्सा तो सभी को याद होगा. साइमंड्स पर भारतीय दर्शकों द्वारा नस्लभेदी टिप्पणियों और श्रीसंत के व्यवहार की बहुत चर्चा रही है. मैदान के बाहर भले ही वह अन्य देशों के खिलाड़ियों से मित्रवत व्यवहार करते हैं, पर मैदान पर उनके दुर्व्यवहार की चर्चा सभी देशो के खिलाड़ी करते हैं. कई बार तो उन्हें सचिन, सौरभ और द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के साथ बदतमीज़ी करते देखा गया है. उनके क्षेत्ररक्षकों द्वारा बल्लेबाज़ों का ध्यान भंग किया जाता, ताकि वे अपनी एकाग्रता खो बैठें और उसमें वे सफल भी रहते हैं. श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. मुरलीधरन और उनके चाहने वालों के लिए इससे बड़ी ख़ुशी और क्या हो सकती है कि मुरलीधरन ने अपने आख़िरी टेस्ट में 800वां विकेट लिया और श्रीलंका यह टेस्ट मैच जीत भी गया, लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर काफ़ी विवाद रहा और कई बार अंपायरों ने मुरली की गेंदबाज़ी पर आपत्ति भी उठाई. बार-बार मुरलीधरन इससे उबरते रहे और अपनी सफलता से आलोचकों को चुप कराते रहे.

अब थोड़ा देशी खिलाड़ियों की बात भी कर लेते हैं. अगर विवाद और भारतीय क्रिकेटरों की बात हो तो जेहन में सबसे पहला नाम श्रीसंत और हरभजन का आता है. हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मारकर पाबंदी तो झेली ही, चेतावनी भी झेली और फिर अपने में सुधार किया. श्रीसंत का आक्रामक व्यवहार एक हद तक शोभा देता है, लेकिन कभी-कभी सीमा लांघने से नुक़सान श्रीसंत का ही हुआ है. यही वजह है कि गाहे-बगाहे मैदान पर श्रीसंत के बदतमीज़ी भरे व्यवहार की चर्चा होती रहती है. कभी धोनी उन्हें समझाते नज़र आते हैं तो कभी कोई और वरिष्ठ खिलाड़ी. विश्वकप से पाकिस्तानी टीम के बाहर होने के दूसरे दिन ही कोच बॉब वूल्मर की मौत से इतना तो ज़ाहिर हो गया था कि टीम में काफी कुछ पक रहा है. 2007 के इस विश्वकप की शुरुआत से पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप की दो प्रमुख टीमों भारत एवं पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के चयन और उनकी फिटनेस को लेकर तरह-तरह के विवादों ने माहौल बिगाड़ रखा था. पाकिस्तान में शोएब अख्तर जैसा खिलाड़ी डोप टेस्ट में असफल और टीम से बाहर रहा, वहीं शोएब मलिक भी इस मामले में पीछे नहीं रहे. इसी कारण आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो दुर्दशा हुई है, उससे सभी वाक़िफ़ हैं. बॉब वूल्मर की मौत शायद यह भी दिखाती है कि इस उपमहाद्वीप में खेल के नाम पर जो राजनीति हो रही है, वह कितनी गंदी है और अगर इसमें कुछ खिलाड़ी शामिल हैं तो वे किस हद तक बैडमैन हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज़ से 20-20 वर्ल्डकप का फाइनल और अब वर्ल्डकप 2011 का सेमी फाइनल, दोनों बड़े मैच फ्लाप शो साबित हुए. इन दोनों मुक़ाबलों में टीम को भारत के ख़िलाफ़ हार झेलनी पड़ी. दोनों ही मैचों के खलनायक टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाज़ मिस्बाह उल हक बने. हक ने 20-20 वर्ल्डकप के फाइनल में घटिया शॉट जमाकर टीम की हार पर मुहर लगा दी थी तो अब वह धीमी बल्लेबाज़ी करके पाकिस्तानी जनता की नज़र में खलनायक बन गए हैं. हालांकि यहां मामला थोड़ा अलग था, पर जनता की नज़र में तो टीम विलेन बन ही गई थी. सिर्फ़ क्रिकेट ही नहीं, अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों की करतूतें सुनने में आती रहती हैं. आमतौर पर फील्ड पर अपने आचरण के चलते विवादों में रहने वाले आस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के बाद वहां के एथलीटों का भी असली चेहरा सामने आया है. पहले एक आस्ट्रेलियाई पहलवान द्वारा भारतीय पहलवान अनिल कुमार से पटखनी खाने के बाद अभद्र इशारा करने पर पदक छीन लिया गया तो अब एक साइकिलिस्ट के ग़लत आचरण के चलते आस्ट्रेलियाई अधिकारियों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. आस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट शेन पार्किंस पर आरोप है कि उन्होंने मुक़ाबले के दौरान ख़तरनाक ड्राइविंग की, जिससे दक्षिण अफ्रीका और स्कोत्लेंद के साइकिलिस्ट आपस में भिड़ गए. और तो और, इस साइकिलिस्ट ने अपने किए पर माफ़ी मांगने के बजाय अधिकारियों को दो उंगलियों से सैल्यूट करके उनका मज़ाक भी उड़ाया. परिणामस्वरूप अधिकारियों ने उसे रेस से डिसक्वालीफाई कर दिया. कुछ साल पहले शेन को शराब पीकर हुड़दंग करने के चलते आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट स्कॉलरशिप से वंचित कर दिया गया था.

अब बात हॉकी की. भारतीय महिला हॉकी तो हमेशा से कई विवादों से जूझती रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यौन शोषण वाला रहा, जिसने कोच के साथ-साथ पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया. ग़ौरतलब है कि महिला हॉकी टीम के वीडियोग्राफर की आपत्तिजनक तस्वीरों के बाद उन्हें निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन बड़ा मुद्दा कोच एम के कौशिक से जुड़ा था, जिन पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप है. आरोप लगा, तब कौशिक ने पहले तो इसे साजिश कहा और फिर जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो इस्तीफे की पेशकश कर दी. इस विवाद ने खिलाड़ियों और कोच के व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. इस विवाद ने एक लंबी बहस को जन्म दिया. कुछ लोग इसे नज़रिए से जोड़कर देखने लगे तो कुछ लोग इसे साजिश का रूप मानते हैं. लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज़ में बदन तो दिखता ही है, तो उस पर कोच की नज़र को लेकर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए. इससे समझ में आ सकता है कि टीम मैनेजमेंट में रहने वाले पुरुषों का लड़कियों को लेकर क्या नज़रिया रहता होगा और वे उनसे कैसे बर्ताव करते होंगे. यहां ग़ौर करने वाली बात यह है कि कोच एम के कौशिक पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, वे ख़ुद खिलाड़ियों ने लगाए हैं. ये वे खिलाड़ी हैं, जिन्हें मालूम है कि यदि झूठे आरोप लगाए गए तो उन्हें टीम में कभी जगह नहीं मिलने वाली. उनकी आवाज़ को कुछ पुराने खिलाड़ियों के बयानों से भी ताक़त मिली है. महिला खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और जैसे ही मामले की एक कड़ी सामने आई, उससे जुड़ी कई कहानियों के पन्ने खुलने लगे. इन खिलाड़ियों की मानें तो कोच के व्यवहार को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें होती रही हैं, लेकिन ऐसी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि शिकायत करने वाली लड़की को ही बड़ी बेशर्मी के साथ टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है.

हॉकी खिलाड़ियों के आरोपों का समर्थन वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रहीं कर्णम मल्लेश्वरी ने भी किया था. उनके मुताबिक़, खेल चाहे कोई भी हो, महिला खिलाड़ियों को हर जगह ऐसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है. अलग-अलग खेलों से जुड़ी महिलाएं विभिन्न मौक़ों पर इस तरह के यौन शोषण की शिकायत करती रही हैं. पिछले साल हैदराबाद में एक महिला मुक्केबाज़ ने ख़ुदकुशी कर ली. अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि उसे उसका एक पुरुष कोच तंग कर रहा था. आंध्र प्रदेश की महिला क्रिकेटरों ने भी आरोप लगाया था कि टीम में चयन के लिए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने उनसे सेक्स को लेकर छूट लेनी चाही थी. बिना किसी सबूत के इस तरह के आरोपों को साबित करना आमतौर पर मुश्किल होता है. पहलवान से मॉडल बनी एक लड़की ने आरोप लगाया कि उससे भी ऐसी छूट लेने की कोशिश की गई. उसका कहना है कि मामला यौन उत्पीड़न भर का नहीं, भ्रष्ट अफसरों का है, जो किसी को टीम में शामिल करने से पहले उससे तरह-तरह के फेवर चाहते हैं, चाहे वह मर्द हो या औरत. हालांकि यह कहना कि सिर्फ़ सारे कोच ही भ्रष्ट हैं, ग़लत होगा. कई बार ऐसा भी होता है कि टीम में जगह पक्की करने के लिए कई खिलाड़ी कोच को इस्तेमाल करते हैं और जब बाद में उनका शोषण होने लगता है तो फिर इस तरह के विवाद पैदा होते हैं. अब कसूर चाहे कोच का हो या फिर खिलाड़ियों का, इतना तो तय है कि इससे खेल की अस्मिता पर सवाल उठते हैं. ऐसा नहीं है कि काजल की इस काली कोठरी में सभी काले हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, जो सालों से इस क्षेत्र में हैं और अपनी गरिमा को बचाकर रखते हैं. सचिन इस बात के जीते-जागते उदाहरण हैं. इन सभी खिलाड़ियों को एक बात समझनी चाहिए कि ऐसा व्यवहार उनकी उपलब्धियों को बौना करता है. अगर उन्हें सीखना है तो सचिन जैसे खिलाड़ियों से सीखें. वरना जो जनता उन्हें सिर पर बैठाकर स्टार होने का रुतबा देती है, वही अर्श से फर्श तक पहुंचाने का भी माद्दा रखती है.

हॉकी खिलाड़ियों के आरोपों का समर्थन वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रहीं कर्णम मल्लेश्वरी ने भी किया था. उनके मुताबिक़, खेल चाहे कोई भी हो, महिला खिलाड़ियों को हर जगह ऐसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है. अलग-अलग खेलों से जुड़ी महिलाएं विभिन्न मौकों पर इस तरह के यौन शोषण की शिकायत करती रही हैं.

rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 06 जून–12 जून 2011

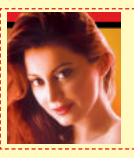

मिनिषा ने बताया न सिर्फ़ उन्हें बेहतरीन खाना खिलाया गया, बल्कि जोक्स भी सुनाए गए.

मिनिषा की ग़लती

कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेकर लौट रहीं मिनिषा लांबा को एयरपोर्ट से बाहर मीडिया वालों को कांस के अनुभवों के बजाय अपनी गिरफ़्तारी के बारे में बताना पड़ रहा था. दरअसल, उनके पास 50 लाख रुपये की ज्वेलरी बरामद की गई थी, लेकिन मिनिषा का कहना है कि उनके काग़ज़ातों में कुछ कंफ्यूज़न था, इस वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें रोक लिया था. ऐसा होने से एक बार तो वह ख़ुद भी शॉक्ड रह गई थीं, लेकिन अब नहीं जानना चाहतीं कि ऐसा किसकी ग़लती से हुआ. उन्हें 16 घंटों तक एयरपोर्ट पर रोके रखा गया, जो उनके हिसाब से ग़ैर ज़रूरी था. लेकिन काग़ज़ातों में कंफ्यूज़न होने की वजह से ऐसा करना एक तरह ज़रूरी भी था, इसलिए उन्हें कोई शिकायत भी नहीं है. क्या उनके पास 50 लाख की ज्वेलरी नहीं थी? इस सवाल को बिल्कुल नकार देती हैं मिनिषा. वह कहती हैं कि उनके पास जो हीरे थे, उनकी क़ीमत काफी कम थी. ख़ुद के बचाव में जब उन्होंने अपने काग़ज़ात पूरे कर दिए, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया. इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी का व्यवहार उनके प्रति काफ़ी फ्रेंडली था. मिनिषा ने बताया न सिर्फ़ उन्हें बेहतरीन खाना खिलाया गया, बल्कि जोक्स भी सुनाए गए. इस पूरी घटना पर लेखिका शोभा डे ने अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर जारी की, जिसमें उन्होंने मिनिषा का मज़ाक उड़ाया और इस बहाने बॉलीवुड की उन हस्तियों की तरफ़ इशारा किया, जो भारी-भरकम सामान लेकर यात्रा करते हैं और मुसीबत में फंसते हैं. क्या इस कंट्रोवर्सी से मिनिषा के करियर पर कोई ख़ास फ़र्क़ पड़ेगा? इस सवाल पर मिनिषा कहती हैं कि वह ग़लती से कंट्रोवर्सी में पड़ गईं और यह घटना उन्हें जीवन भर याद रहेगी. भविष्य में कभी वह इस तरह की स्थिति में अगर फंसीं तो उन्हें ख़ुद को संभालने में परेशानी नहीं होगी.

श्रीदेवी वापसी की राह पर

चार साल की उम्र में तमिल फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर शुरुआत करने वाली श्रीदेवी ने 1997 में बच्चों की परवरिश की ख़ातिर अलविदा कह दिया था. 14 साल के लंबे अंतराल के बाद इंडस्ट्री में उनकी वापसी की चर्चा गर्म है. इसकी वजह वह फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्टर गौरी शिंदे को मानती हैं. श्रीदेवी कहती हैं कि जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो वह उन्हें बेहद पसंद आई और लगा कि इस फिल्म में उन्हें ज़रूर काम करना चाहिए. इस फिल्म की शूटिंग जुलाई के अंत में शुरू होगी. अच्छी स्क्रिप्ट के ऑफर तो पहले भी आए होंगे, लेकिन क्या इतने लंबे अंतराल के दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को मिस नहीं किया, कहीं यही वजह तो नहीं है वापसी की?

इस सवाल पर श्रीदेवी कहती हैं कि एक प्रोड्यूसर की पत्नी होने के नाते वह इंडस्ट्री से अलग नहीं हुई थीं और उन्होंने ख़ुद को इंडस्ट्री से अलग कभी महसूस नहीं किया. हालांकि परिवार शुरू करने केलिए अपने करियर को दांव पर लगा दिया उन्होंने. वापसी से क्या उनकी बेटियों को परेशानी नहीं होगी? इसका भी उपाय निकाल लिया है श्रीदेवी ने. दरअसल वह बच्चों की छुट्टियों के दौरान शूटिंग करेंगी, ताकि वे भी उनके साथ शूटिंग पर जाएं. इसलिए न बच्चियों को मम्मी की कमी खलेगी और न श्रीदेवी को उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत होगी. वह कहती हैं कि जब उनकी छोटी बेटी उन्हें टीवी पर आ रही फिल्म में देखती है तो वह लगातार टीवी और उनके चेहरे को देखती रहती है. उसे यक़ीन नहीं होता कि उसकी मम्मी स्क्रीन पर आ रही हैं, लेकिन श्रीदेवी अपनी बेटियों को फिल्मी दुनिया में करियर बनाने पर कोई जोर नहीं देंगी, क्योंकि दोनों ही पढ़ाई-लिखाई में अच्छी हैं. इसलिए वे अपनी मर्जी का करियर तय कर सकती हैं. इस वापसी के बाद श्रीदेवी फिल्मों की तरफ़ पूरी तरह ध्यान देने वाली हैं, लेकिन वह कहती हैं कि फिल्म की शूटिंग वह बच्चों को छोड़कर नहीं कर सकेंगी.

नए अवतार में सोनल

तीन साल पहले सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों ने ख़ूबसूरत सोनल चौहान का दीदार पहली बार किया था. दर्शकों ने उनकी ख़ूबसूरती और अभिनय पर अपनी मुहर लगाने में देर नहीं लगाई और सोनल की पहली फिल्म जन्नत सफल हो गई. जन्नत की सफलता के बाद सोनल को भविष्य की स्टार अभिनेत्री के रूप में देखा जाने लगा था, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया. पिछले तीन साल में सोनल की एक भी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई और दर्शक उन्हें भूलने लगे. उन्होंने अच्छी हिंदी फिल्मों के प्रस्ताव के अभाव में दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख़ किया. उन्होंने इस बीच तेलुगु फिल्म रेनबो और कन्नड़ फिल्म चेलुवे निन्ने नेडालू की. बावजूद इसके, सोनल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी सक्रियता बरक़रार रखी. वह मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के पुत्र ओ एस हुसैन की फिल्म पहला सितारा की भी शूटिंग करती रहीं. पहला सितारा की शूटिंग ख़त्म होने के बाद सोनल को लगा कि इस फिल्म की रिलीज के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी स्थायी पहचान बन जाएगी, पर उनकी क़िस्मत ने साथ नहीं दिया. अनुराग सिन्हा और सोनल चौहान अभिनीत पहला सितारा की रिलीज की तारीख़ टलती रही. वह निराश हो गईं, लेकिन उन्हें जल्द ही ख़ुशख़बरी मिली. सोनल को पता चला कि उन्हें अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप के लिए चुन लिया गया है. वह ख़ुशी से झूमने लगीं, क्योंकि उन्हें सदी के महानायक के साथ अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा था. बुड्ढा होगा तेरा बाप के लिए पहले सोनल की जगह कंगना रानावत के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब सोनल की बात बन गई. दरअसल, उनके लिए अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मतलब बच्चन परिवार को क़रीब से जानना है. सोनल बच्चन बहू ऐश्वर्या राय की बड़ी प्रशंसक हैं. उन्हें लगा कि इसी बहाने उन्हें अपनी प्रिय अभिनेत्री को क़रीब से जानने और समझने का मौक़ा मिलेगा. शूटिंग के पहले दिन ही सोनल को ऐश से मिलने का मौक़ा मिल गया. साथ में अभिषेक बच्चन भी थे. बच्चन परिवार को देखने का अनुभव सोनल के लिए बेहद स्पेशल था. वह बताती हैं कि उन्होंने बच्चन परिवार के बारे में सिर्फ़ सुना था और अब उन्हें क़रीब से देखने का मौक़ा मिल रहा है. उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि बच्चन परिवार क्यों फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सम्मानित परिवार है. बुड्ढा होगा तेरा बाप में अभिनय का प्रस्ताव मिलने के बाद सोनल की क़िस्मत का ताला खुल गया है. उन्हें इरोज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली एक अनाम फिल्म में केंद्रीय भूमिका के लिए भी चुना गया है. चर्चा है कि इस फिल्म में सोनल नए लुक में नज़र आएंगी. उन्हें पहली बार दर्शक एक्शन करते देखेंगे. लंबे इंतज़ार के बाद सोनल की ख़ुशियों की पोटली खुली है. अब उनके पास अच्छी और बड़ी फिल्मों में अभिनय के प्रस्ताव आ रहे हैं. हिंदी फिल्मी दुनिया ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है.

नेहा के दिल के युवराज

युवराज सिंह के दिल में हिंदी फिल्मों की हीरोइनों के लिए बेहद ख़ास जगह है. उनका दिल कभी किम शर्मा पर आता है तो कभी दीपिका पादुकोण पर. अब लगता है कि युवराज को नेहा धूपिया पसंद आ गई हैं. युवराज की नेहा के साथ दोस्ती की इन दिनों ख़ूब चर्चा है. कहा तो यह भी जा रहा है कि दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी है. दरअसल, नेहा पिछले कई दिनों से युवराज सिंह के साथ विभिन्न पार्टियों में देखी जा रही हैं. ऐसे में लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही. ग़ौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल ही नेहा का स्क्वैश खिलाड़ी रित्विक भट्टाचार्य से ब्रेकअप हुआ. ऐसे में युवराज के साथ उनकी नज़दीकियों को प्यार का नाम देना और भी स्वाभाविक हो गया है. हालांकि नेहा कहती हैं कि युवराज के साथ उनके अफेयर की ख़बरों में ज़रा भी सच्चाई नहीं है. वह उन्हें लंबे समय से जानती हैं, युवराज सिर्फ़ अच्छे दोस्त हैं. एक बात ग़ौर करने वाली है कि यदि युवराज को नेहा अर्से से जानती हैं तो पहले वह उनके साथ पार्टियों में क्यों नहीं दिखती थीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाज़ी में युवराज के साथ अफेयर की ख़बरों को नेहा स्वीकारना नहीं चाहतीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रिमी सेन शो पीस नहीं

अभिनेत्री रिमी सेन की हाल में एक फिल्म आई थैंक्यू. इसके लिए उन्हें प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं बनाया गया. तिगमांशु धूलिया निर्देशित फिल्म शागिर्द में भी उन्होंने अभिनय किया. रिमी को इस फिल्म से सफलता की भी उम्मीद हुई. कई सफल फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के बावजूद रिमी आज हाशिए पर हैं. छह साल में कई बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में वह जगह नहीं मिली, जिसकी रिमी हकदार थीं. दरअसल, दूसरी हीरोइनों की तरह रिमी को फिल्मी पार्टियों में जाकर ख़ुद अपना प्रचार करना पसंद नहीं है और न दूसरों को ख़ुश करने के लिए वह झूठी तारीफ़ कर सकती हैं. वह दर्शकों को धोखे में रखकर रिलीज के पहले अपनी फिल्म के बारे में सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें करने के लिए भी तैयार नहीं रहतीं. अमूमन ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए फिल्म के प्रचार अभियान में निर्माता-निर्देशक हीरोइनों का ख़ूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात रिमी की आती है तो उन्हें फिल्म के प्रचार अभियान में तरजीह नहीं दी जाती. उन्हें फिल्म की रिलीज के समय लाइमलाइट से दूर रखा जाता है. दरअसल, निर्माता-निर्देशक रिमी के ईमानदार रवैये से डर जाते हैं. पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म थैंक्यू के प्रचार अभियान में भी रिमी को हाशिए पर रखा गया. हालांकि फिल्म देखने के बाद रिमी ने समीक्षकों को सोनम कपूर और सेलिना जेटली से अधिक लुभाया. रिमी फिल्मी चमक-दमक से दूर रहना पसंद करती हैं और न फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त है. मुंबई में उनके कुछ अच्छे दोस्त हैं, जो उन्हें बहुत समय से जानते हैं. अपना ख़ाली समय वह उन्हीं के साथ बिताती हैं. धूम, हंगामा, क्योंकि.., गोलमाल एवं बागवान जैसी बड़ी और सफल फिल्मों की हीरोइन रहीं रिमी इन दिनों इक्का-दुक्का फिल्मों में ही नज़र आती हैं. वह कहती हैं कि उन्हें इंट्रेस्टिंग फिल्में नहीं मिल रही हैं और अब वह फिल्मों में शो पीस नहीं बनना चाहतीं. रिमी छोटे बजट की अर्थपूर्ण फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती हैं, जिनमें उनकी भूमिका दमदार हो, जिन्हें दर्शक लंबे समय तक याद रखें. वह कभी यह डिमांड नहीं करतीं कि उन्हें बड़े को-स्टार के साथ ही काम करना है. उन्हें ख़ुद पर विश्वास है. वह कहती हैं कि वह रणबीर कपूर और इमरान ख़ान के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन भूमिका में वजन होना चाहिए.

फिल्म प्रीव्यू

चिल्लर पार्टी

बॉलीवुड में अभिनय की लंबी पारी खेल रहे सुपर स्टार सलमान ख़ान अब प्रोडक्शन में हाथ आजमा रहे हैं. वह फिल्म चिल्लर पार्टी के को-प्रोड्यूसर बने हैं. यह फिल्म बच्चों के लिए है और सलमान ने इसके प्रचार में भी दिलचस्पी ली है. बॉलीवुड में सलमान ही ऐसे ख़ान हैं, जिनका अपना कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है. फिल्म के प्रोजेक्ट में शामिल होकर सलमान ख़ान बेहद ख़ुश हैं और वह फिल्म के हर पहलू से जुड़ना चाहते हैं. ख़ास तौर पर उन्होंने फिल्म की मार्केटिंग और रिलीज में दिलचस्पी ली है. चिल्लर पार्टी में कॉमेडी का भी तड़का होगा. यह आठ जुलाई को रिलीज होगी. बच्चों की इस फिल्म में रणबीर कपूर ने एक आइटम सांग भी किया है. फिल्म का निर्देशन नीतेश तिवारी और विकास बहल ने मिलकर किया है. उनका मानना है कि सलमान ख़ान का साथ मिलने और उनके सह निर्माता बनने से फिल्म का सफर मनोरंजक हो गया है. बच्चे सलमान ख़ान को बेहद पसंद करते हैं और उन्हें यह फिल्म पसंद आएगी. जब वह बच्चों से फिल्म देखने के लिए कहेंगे तो बच्चे सिनेमाघरों तक ज़रूर आएंगे. इस फिल्म में मासूम, लेकिन नटखट बच्चों का एक गैंग दिखाया गया है. ये बच्चे एक कॉलोनी में बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है. इस गैंग के साथ फटका और भीड़ रहने के लिए आते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन एक नेता की वजह से भीड़ की ज़िंदगी ख़तरे में आ जाती है. बच्चे फिर राजनीति की दुनिया से टक्कर लेते हैं और दिखाते हैं कि छोटे बच्चे भी पहाड़ों की ऊंचाइयों को नाप सकते हैं. फिल्म में रणबीर कपूर का डांस देखकर बॉलीवुड की आइटम गर्ल टेंशन में आ सकती हैं. इस फिल्म में रणबीर का लुक कुछ उसी किस्म का है, जैसा उनके पिता ऋषि कपूर का फिल्म अमर अकबर, एंथोनी में था. ख़ैर, चिल्लर पार्टी का यह गाना इसलिए भी ख़ास है, क्योंकि रणबीर के अभिनय करियर का यह पहला आइटम है, जिसकी शूटिंग में जूनियर कपूर ने कमाल कर दिखाया. बच्चों के साथ शूटिंग में वह बच्चों जैसे ही बन गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 06 जून–12 जून 2011

www.chauthiduniya.com

गिराटा गांव

किसानों के साथ धोखा

प्रवीण महाजन

विदर्भ के वाशिम ज़िले में एक गांव है गिराटा. कहानी का मज़मून पुराना है. फटेहाल किसान और आत्महत्याएं, किरदार बदल गए हैं. कहानी भी कुछ अलग है. गांव के साहूकार के क़र्ज़ के कारण आत्महत्या का मामला नहीं है. यह मामला है देश के सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क़र्ज़ वसूली अभियान का. जब तक इस गांव के लोगों को क़र्ज़ के सब्ज़बाग़ नहीं दिखाए गए थे, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन स्टेट बैंक ने जैसे ही अपना गांव योजना के तहत इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए दत्तक लिया, पूरी तस्वीर ही बदल गई. दो साल में 8 मौतें इसका जीता-जागता प्रमाण हैं.

विदर्भ के लिए जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैकेज की घोषणा हुई, गिराटा ऐसा गांव था जहां के लोगों ने स्वाभिमान के साथ कहा था कि हमें क़र्ज़ माफ़ी नहीं चाहिए. ज़िलाधिकारी और बैंक के मैनेजर को बाक़ायदा लिखित में इस बात की सूचना दी गई थी. साथ ही गांव के सभी किसानों के क़र्ज़ की क़िस्त सही समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेंदूरजना शाखा में भरी जा रही थी. 2006 तक सब कुछ ठीक चल रहा था. कृषि के साथ ही समानांतर व्यवसाय और बैंक की अदूरदर्शिता ने इस गांव के लोगों के सितारे गर्दिश में ला दिए. हालात यहां तक पहुंच गए कि 2009-2010 में गांव में आठ मौतें हो गईं. इस गांव ने मौत का यह तांडव उस समय भी नहीं देखा था, जब पूरे विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएं तेज़ी से बढ़ रही थीं. वाशिम ज़िले के मानोरा तहसील का गिराटा गांव दुर्गम क्षेत्र में बसा है. इस गांव की आबादी लगभग 700 है. यह गांव में भीलखेड़ ग्राम पंचायत के तहत आता है और यहां अधिकांशतः बंजारा समुदाय के लोग रहते हैं. प्रकाश पांडुरंग राठोड़ गांव का एकमात्र उच्च शिक्षा प्राप्त युवक है. वह वाशिम के सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी पाई.

समय ने तब करवट ली जब सन 2007 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेंदुरजना शाखा के प्रबंधक शेखर नटराजन ने इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की योजना बनाई. दरअसल, स्टेट बैंक ने देश भर में 250 गांवों को दत्तक लेकर उन्हें एसबीआई अपना गांव योजना के अंतर्गत आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी. बताया गया कि इसी के तहत इस गांव को भी दत्तक लिया जा रहा है. यह भी बताया गया कि इस गांव के किसानों ने कृषि या अन्य कार्य के लिए जो भी क़र्ज़ लिए हैं, उनका भुगतान समय पर किया जा रहा है. यहां के लोगों ने एक समूह बना कर सेवालाल महाराज शेतकरी बचत गट की स्थापना की. इसके 20 सदस्य थे. फरवरी 2007 को इस बचत गट के सभी सदस्यों को दो-दो भैंसों के लिए 48 हज़ार रुपए दिए गए. इन लोगों ने भैंसें भी ख़रीदीं. 8 माह तक भैंसें दूध देती रहीं तो सब कुछ अच्छा चल रहा था. प्रति माह 1100 रुपए का भुगतान भी इस बचत गट के सदस्य समय पर कर रहे थे. जनवरी 2008 आते तक स्टेट बैंक के अकोला क्षेत्र के एजीएम करणीकर और कलेक्टर इस गांव में आए. करणीकर ने बताया कि इस गांव को दत्तक लिया जा रहा है. इसके तहत बचत गट के सभी 20 सदस्यों को 20-20 भैंसें ख़रीदने के लिए क़र्ज़ दिया जाएगा. साथ ही भैंसों के लिए तबेला बनाने के लिए तो 1-1 लाख रुपए का क़र्ज़ भी दे दिया गया. गांव के लोग ख़ुश थे कि अब उनके दिन बहुरने वाले हैं. इस बीच एक साल पहले ख़रीदी गई भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया. अब इनके दूध के लिए 8-9 माह इंतज़ार करने का समय था. दूध से होने वाली आय बंद हो गई. अब जो 1-1 लाख रुपए का क़र्ज़ मिला था, उससे तबेला बना लिया गया. कुछ लोगों ने तो रुपए कम पड़ने पर इधर-उधर से भी रुपयों का इंतज़ाम कर यह निर्माण कार्य किया. सूत्र बताते हैं कि अप्रैल 2008 में स्टेट बैंक की शेंदूरजना शाखा में इंटरनल ऑडिट शुरू हुआ. खातों में कुछ गड़बड़ियां पाई गईं और गहन जांच शुरू हो गई. इस बीच यहां के प्रबंधक नटराजन का भी स्थानांतरण हो गया. पहले की भैंसों ने तो दूध देना बंद कर ही दिया था, ऊपर से तबेले पर किया गया ख़र्च भी इन किसानों के सर पर आ पड़ा. जब इन लोगों ने एजीएम कर्णीकर से मुलाक़ात की तो उन्होंने बताया कि अभी ऑडिट जारी है और कुछ नहीं किया जा सकता है. 20 भैंसों के लिए क़र्ज़ भी नहीं दिया जा सकता है. 2009 के आते-आते बैंक ने इन लोगों से क़र्ज़ वसूली के लिए ज़बरदस्ती शुरू कर दी. वसूली के लिए क़ानूनी नोटिस दिया गया.

अब गांव को झटके लगने लगे. लोगों को कृषि से इतर व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रकाश राठोड़ का कहना है कि 2007 के बाद बारिश की कमी के कारण खेती तो चौपट हो गई, परंतु फिर भी कुछ लोगों ने जब जैसे बन पड़ा, क़र्ज़ की अदायगी जारी रखी, लेकिन बैंक का सीधा सा कहना रहा कि पहले सभी ऋण (जिसमें भैंस के तबेले के लिए दिया गया 1 लाख का ऋण भी शामिल था) वापस भरना होगा तभी नया क़र्ज़ दिया जाएगा. वैसे सूत्र बताते हैं कि बैंक की शेंदुरजना शाखा के तत्कालीन प्रबंधक शेखर नटराजन को सिर्फ़ इसलिए निलंबित कर दिया गया कि उन्होंने सीमा से अधिक ऋण बांट दिए थे. वैसे भी विदर्भ में खेती की आज यह स्थिति है कि रासायनिक खेती के चलते यहां बिना क़र्ज़ के खेती करना मुश्किल हो चला है. वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि 2007 में बैंक ने जो अपना गांव योजना लाई थी, उसके अंतर्गत इस गिराटा गांव का सर्वांगीण विकास किया जाना था. बैंक के सूत्र यह भी दावा करते हैं कि गांव का विकास होने के लिए प्रशासन और स्थानीय नागरिकों की मदद ज़रूरी थी. घुमा-फिरा कर बैंक इस असफलता का पूरा ठीकरा राज्य सरकार और किसानों पर फोड़ता है और कहता है कि हम तो सिर्फ़ धन उपलब्ध करा सकते थे. बैंक के सूत्रों का यह भी दावा है कि गांव के लोगों ने किसी पैकेज के लिए क़र्ज़ की वापसी बंद कर दी, क्योंकि उसी समय केंद्र व राज्य सरकार के पैकेज के अंतर्गत काफ़ी क़र्ज़ माफ़ किए जा चुके थे. अब जबकि 2007 में इस गांव के लोगों ने पैकेज नहीं लेने के लिए बाक़ायदा पत्र लिखा था, तो फिर एक साल बाद ही ये लोग पैकेज के लिए क्यों क़र्ज़ अदायगी बंद करेंगे? यह लाख टके का सवाल अब भी अनुत्तरित है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर अय्यर कहते हैं कि इस गांव के लोगों पर अब 70 लाख रुपए का क़र्ज़ चढ़ चुका है. क़र्ज़ की वापसी नहीं करने से सभी खाते डिफाल्टर की सूची में आ गए हैं. अब बैंक क़र्ज़ की वसूली के लिए क़ानूनी कार्यवाही कर रहा है. अय्यर की दलील भी ठीक है, लेकिन मामला यह है कि बैंक ने दुग्ध व्यवसाय के लिए लिए ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की. तबेले के लिए ऋण दिया जो अनुत्पादक था, लेकिन जो उत्पादक था वह थीं भैंसें. उनके लिए ऋण ही नहीं दिया. फिर कड़ाई से वसूली का नैतिक अधिकार कैसे.

ख़ैर, बैंक की अपनी दलील है और गांव के लोगों की अपनी. लेकिन इस सबके बीच वे लोग पिस रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य मौत के मुंह में समा रहे हैं. सवाल यह उठता है कि क़र्ज़ की अदायगी के लिए जब सरकारें पैकेज घोषित करती हैं तो फिर जब 2008 से जब इस गांव के लोगों ने क़र्ज़ की अदायगी बंद की तो उसी समय क्यों नहीं कोई योजना बनाई गई, जिसके तहत इन पर क़र्ज़ का बोझ ज़्यादा न बढ़े. क्यों सेठ-साहूकारों की तर्ज़ पर बैंक ने तीन साल तक ब्याज़ की राशि बढ़ाई. और फिर किसी गांव को दत्तक लेने के पीछे स्टेट बैंक के क्या मंसूबे थे? क्या बैंक ने सिर्फ़ सामाजिक ज़िम्मेदारी के वहन की वाहवाही लूटने के लिए यह सब किया था? अगर नहीं तो क्यों नहीं योजना के मुताबिक़ गांव के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया?

feedback@chauthiduniya.com

विदर्भ के लिए जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैकेज की घोषणा हुई उस समय गिराटा ही एक ऐसा गांव था जहां के लोगों ने स्वाभिमान के साथ कहा था कि हमें क़र्ज़ माफ़ी नहीं चाहिए. ज़िलाधिकारी और बैंक के मैनेजर को बाक़ायदा लिखित में इस बात की सूचना दी गई थी. कृषि के साथ ही समानांतर व्यवसाय और बैंक की अदूरदर्शिता ने इस गांव के लोगों के सितारे ग़र्दिश में ला दिए. हालात यहां तक पहुंच गए कि 2009-2010 में गांव में आठ मौतें हो गईं.

मौत का तांडव

गांव के गोविंद राठोड़ के तीन बेटे थे. 2009 में बड़े बेटे प्रह्लाद की मौत हार्ट अटैक से हो गई. बैंक के क़र्ज़ का बोझ ज़्यादा था. गोविंद इस सदमे को झेल नहीं सके और बाद में उन्होंने भी फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. इसके अलावा एक ही परिवार के दो भाई नामदेव राठोड़ और सुखदेव राठोड़ ने भी फांसी लगा ली. सनी प्रताप राठोड़ की मौत भी इसी तरह हुई. धनजी चौहान, रतन राठोड़ भी काल के गाल में समा चुके हैं. अब सवाल इस बात का है कि इन सब मौतों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या अब भी इस गांव की समस्या हल करने के लिए कोई प्रभावी क़दम उठाए जाएंगे?

बादलों की दग़ाबाज़ी का महीना है जून

पिछले साल मानसून ने शुरुआती आंखमिचौली के बाद अपनी कृपा बनाए रखी थी. चक्रवाती तूफ़ान लैला के कारण समय पूर्व आने की मानसून की भविष्यवाणी हालांकि ग़लत साबित हुई थी, लेकिन कुछ देर से ही सही मगर मानसून पूरी शिद्दत के साथ राज्य में सक्रिय हुआ था. औसत के आधार पर राज्य में मानसून का प्रवेश 5 से 10 जून के बीच होता है.

आलोक मिश्रा

जून माह में कोंकण, कोल्हापुर जैसे कुछ इलाक़ों को छोड़कर वैसे तो राज्य में कोई ख़ास बारिश नहीं होती है, लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र में जून माह में ही मानसून ने अच्छी सक्रियता दर्ज कराई थी. मौसम विभाग ने इस साल भी मानसून सामान्य होने की भविष्यवाणी की है. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी मानसून अच्छी ख़बर लेकर आएगा, लेकिन पिछले सालों में यह अनुभव खट्टे-मीठे रहे हैं. मुंबई और कोंकण-पुणे तक तो मानसून आम तौर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि मराठवाड़ा और विदर्भ को बारिश के लिए ललचाई नज़रों से आसमान ताकना पड़ता है. इस कारण जून को बादलों की दग़ाबाज़ी का माह भी कहा जाता है. वैसे पिछले साल जून माह में राज्य भर में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी. पिछले साल गर्मी भी अच्छी पड़ी थी. इस साल भी मई में हालांकि तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहा, लेकिन पिछले साल की तरह 47 डिग्री तक नहीं पहुंचा. इससे मानसून तरंगों की तीव्रता पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं. पिछले साल जून में सन 2009 की तुलना में दोगुनी बारिश हुई थी जो राज्य के सामान्य औसत से मात्र दो फ़ीसदी कम अर्थात 92.8 प्रतिशत रही. राज्य में सबसे कम बारिश मराठवाड़ा के नांदेड़ और परभणी ज़िले में हुई थी. विदर्भ में हालांकि मानसून कोई एक हफ्ते देरी से आया था, लेकिन माह के अंतिम दो सप्ताह में अच्छी बारिश हुई थी. मध्य व पश्चिम महाराष्ट्र में पूरे महीने मेघ जमकर बरसे थे. पिछले साल जून तक राज्य में औसतन 218.1 मिमी बारिश हुई थी जो सामान्य (222.1) से 98.2 फ़ीसदी कम थी. सन 2009 में हालात ख़राब थे. जून 2009 में मात्र 101.4 मिमी बारिश ही हुई थी जो सामान्य की 45.6 फ़ीसदी थी. पिछले साल मानसून ने शुरुआती आंखमिचौली के बाद अपनी कृपा बनाए रखी थी. चक्रवाती तूफ़ान लैला के कारण समय पूर्व आने की मानसून की भविष्यवाणी हालांकि ग़लत साबित हुई थी, लेकिन कुछ देर से ही सही मगर मानसून पूरी शिद्दत के साथ राज्य में सक्रिय हुआ था. औसत के आधार पर राज्य में मानसून का प्रवेश 5 से 10 जून के बीच होता है. 10 जून तक मुंबई और मराठवाड़ा के बाद 12 से 15 जून के बीच इसे संपूर्ण राज्य में सक्रिय हो जाना चाहिए. पिछले साल लैला के कारण मानसून शुरुआती दौर में शिथिल पड़ गया था और इसने थोड़ा विलंब यानी 10 जून को राज्य की सीमा में प्रवेश किया था. मराठवाड़ा के बाद फिर एक बार मानसून शिथिल पड़ा और विदर्भ में लगभग एक सप्ताह की देरी से माह के तीसरे सप्ताह पहुंचा था.

पिछले साल ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, अहमदनगर ज़िले में तो कमोबेश रोज़ ही बारिश ने अपनी उपिस्थिति दर्ज कराई थी. ठाणे में 91.1, रत्नागिरी में 105.3, सिंधुदुर्ग में 110.2, नासिक 119.2, अहमदनगर 166.7, पुणे 151.5, सोलापुर 143.1 मिमी बारिश हुई थी जो सामान्य से अधिक थी, लेकिन नांदेड़ और परभणी ज़िलों को बादलों की दग़ाबाज़ी का सामना करना पड़ा था और सामान्य से काफ़ी कम क्रमशः 50.5 व 55.6 फ़ीसदी बारिश दर्ज की गई थी. जंगलों के कारण गड़चिरोली में आम तौर पर अच्छी बारिश होती है, लेकिन पिछले साल अपेक्षा के विपरीत गड़चिरोली ज़िले में भी मात्र 67.7 फ़ीसदी बारिश हुई थी. मराठवाड़ा के औरंगाबाद और बीड़ ज़िलों में क्रमशः 134.2 और 113.4 फ़ीसदी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी. विदर्भ में सबसे अधिक मेहरबानी बुलढाना और वाशिम ज़िलों में हुई थी, जहां का औसत क्रमशः 121.9 व 119.1 प्रतिशत था. मराठवाड़ा में सामान्य से अधिक 119.2 फ़ीसदी बारिश हुई थी. नासिक में औसतन 154.2 मिमी बारिश होनी चाहिए, लेकिन पिछले साल जून तक तक 184.1 मिमी बारिश हो चुकी थी. शेष महाराष्ट्र में जलगांव को ही बारिश के लिए तरसना पड़ा था. यहां सामान्य की अपेक्षा सिर्फ़ 69.4 और नंदुरबार में 73.4 फ़ीसदी बारिश हुई थी. सातारा में सामान्य से दोगुनी 204 फ़ीसदी बारिश हुई थी. राज्य के अन्य हिस्सों में सामान्य के आसपास ही बारिश दर्ज की गई थी.

feedback@chauthiduniya.com

M.R. Electricals
Manufactures Representative & Govt. Order Suppliers
DILIP NARVARIYA
AREA SALES HEAD
8421236353, 9021985895
Opp. Daga Hospital, Gandhibagh, Nagpur-440002
Ph.- 0172-2766215, 2763552
Tele Fax : 0712-2763236
Email :Priyeshvijaywargi@yahoo.co.in

SU-RUCHI CATERING SERVICES
Hemant P. Borikar
Ph.: (0712)2232388 Mobile : 98230-67055
Plot No. 16, Madhav Nagar, Nagpur (M.S.)
Branch:- Raipur-opp. Shitala Mandir, Kankalipara, ph.: 0771537976

बेहतरीन वन्य जीव प्रबंधन और संरक्षण ने दिलाया आठवां स्थान

अव्वल नंबर की दौड़ में मेलघाट

देहरादून से निरीक्षण करने को आई वन्य जीव एवं पर्यावरण विशेषज्ञों के एक दल ने मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प को राज्य के सर्वोत्तम व्याघ्र प्रकल्प का ख़िताब दिया है. इसे देश के 39 प्रकल्पों में आठवां स्थान प्राप्त है. मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प शाखा सिपना के उप वन संरक्षक बड़गे ने बताया कि विशेषज्ञों के दल ने मेलघाट को हर कसौटी पर खरा पाया है. बाघों के संरक्षण, गणना और रखरखाव आदि कार्यों का मूल्यांकन करने पर मेलघाट को 300 में से 230 अंक प्राप्त हुए हैं. मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती ज़िले के धारणी, चिखलदरा, आकोट से लेकर बुलढाणा ज़िले तक फैला हुआ है. इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश से मिला हुआ है. इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी करना अपने आप में दिक्क़तों भरा कार्य है. बावजूद इसके यह आज बाघों की बेहतरीन आरामगाह है. पिछले पांच वर्षों से मेलघाट में वन्यजीव संरक्षण हेतु नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं. इसमें देहरादून वन मुख्यालय के मार्गदर्शन में चलाई जा रही कैमरा ट्रैपिंग पद्धति प्रमुख है.

देहरादून के विशेषज्ञों ने मेलघाट प्रकल्प का हर कसौटी पर मूल्यांकन किया. इसमें प्राणियों के आश्रय स्थल, मानवीय हस्तक्षेप, जलस्रोत, वृक्षारोपण, गांवों का पुनवर्सन, वन संवर्धन व प्रबंधन, वन्य प्राणियों की गणना और लक्ष्य तक पहुंचने हेतु जारी कार्यक्रम आदि सभी बातों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट दिल्ली भेजी. इसके बाद नई दिल्ली में मेलघाट को देश के दस श्रेष्ठ व्याघ्र प्रकल्पों को शामिल करने की घोषणा की गई. राष्ट्रीय स्तर पर आठवां स्थान पा चुके मेलघाट ने अब कार्बेट टाइगर प्रोजेक्ट और रणथंभोर को भी पीछे छोड़ दिया है. ज्ञात रहे कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 18 व्याघ्र प्रकल्पों की घोषणा की थी, मेलघाट भी उनमें से एक था. यह महाराष्ट्र का पहला व्याघ्र प्रकल्प हैं. इसके 72 गांवों का पुनर्वास किया जाना है. सिपना के सहायक उपवनसंरक्षक निर्लेकर ने बताया कि प्रकल्प द्वारा विगत दिनों चिखलदरा से जुड़े चुरणी, पस्तलई और वैराट इन तीन ग्रामों का पुनर्वास ज़िले की वरूड़ तहसील के घाटलाडकी में किया गया है. अब इन तीनों गांवो का क्षेत्र भी व्याघ्र प्रकल्प में समाहित हो चुका है. टाइगर प्रोजेक्ट इस वर्ष नगरतास, अमोना और धारगढ़दून गांवों का पुनर्वास करेगा. इस पर 18.86 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे. जो लोग या परिवार व्याघ्र प्रकल्प की योजना के अंतर्गत नए स्थल पर पुनर्वसन को तैयार नहीं हैं. ऐसे परिवारों के लिए दस लाख रुपए प्रति परिवार का नया पैकेज घोषित किया गया है. ताकि वे कहीं भी जाकर बस सकें. 55 बाघ रिकार्ड संपूर्ण मेलघाट में 55 बाघ रहने की पुष्टि व्याघ्र प्रकल्प के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है. ये आंकड़े विगत वर्ष 27 जनवरी से 3 फरवरी 2010 के बीच हुई व्याघ्र गणना के हैं. सिपना वनक्षेत्र में कुल 96 नियत क्षेत्र (बीट) हैं. इनमें 65 क्षेत्रों में बाघ और 66 में तेंदुए मिलते हैं. विगत गणना में सिर्फ़ सिपना क्षेत्र में ही 5546 तृणभक्षी पाए गए. इनमें गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, सुअर, बंदर, मोर, खरगोश आदि शामिल हैं.

प्रकल्प का छह सूत्री कार्यक्रम

व्याघ्र प्रकल्प का सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए छह सूत्री कार्यक्रम पर अमल किया जाता है.

1 क्षेत्रीय कर्मचारी की मुख्यालय पर अनिवार्य उपस्थिति
2 वन्यजीव संरक्षण हेतु निर्मित प्रोटेक्शन कैंप में कर्मचारियो को सभी सुविधाएं मुहैया कराना
3 सुरक्षा शिविर के माध्यम से निगेहबानी
4 माह में 9 दिन ग्रुप पेट्रोलिंग के दौरान जलस्रोतों पर कड़ी नज़र
5 आग पर क़ाबू पाने के लिए हर परिक्षेत्र में आठ कर्मियों का वाहन दस्ता
6 प्रत्येक घटना को दर्ज करने के लिए डेली डायरी रजिस्टर

संजय जोशी
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

कहीं ग़ायब न हो जाए मुस्कराहट

राज्य के जनप्रिय नेताओं के लिए आदर्श सोसायटी घोटाला अजीब मुसीबत बन गया है. कब किसको अपने घेरे में ले ले, कहना मुश्किल है. आए दिन यह बला अपना सिर उठा लेती है. ऐसा लगता है कि इस घोटाले की फ़ेहरिस्त लंबी है. अब इसके फेर में राज्य के होनहार पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री विलासराव देशमुख पड़ गए. ऐसा नहीं है कि उन पर यह कोई पहली बार मुसीबत आई है. पहले भी औरंगाबाद की वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन अपने पारिवारिक ट्रस्ट को देने के लिए चर्चा में रहे हैं, पर उनका कोई बाल-बांका भी नहीं कर सका. वह राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं. आदर्श जैसे आरोपों को पहले भी वे अपनी स्मार्ट मुस्कराहट के साथ झेल चुके हैं. उनके रुतबे का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक विधायक के साहूकार पिता की ग़ैरक़ानूनी साहूकारी के ख़िलाफ़ एफआईआर न लिखने दिए जाने के मामले पर उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद भी वे पद पर क़ायम हैं. उच्चतम न्यायालय ने उनके नाम पर राज्य सरकार पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह एक रिकॉर्ड है कि किसी मुख्यमंत्री पर इतना भारी-भरकम जुर्माना लगाया. है न कमाल की बात की कि उच्चतम न्यायालय की फटकार से तो कइयों की बत्ती गुल हो जाती है, पर देशमुख साहब पर कोई असर नहीं पड़ा. मंत्री थे, मंत्री हैं. पहले राज्य संभालते थे, अब पूरे देश के ग्रामीण इलाक़ों का विकास करने में जुटे हैं. पर लगता है उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है. मजबूरी में राज्य का मुखिया पद छोड़कर जाना पड़ा. बुरा हो 26/11 के आतंकी हमले और फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के क़रीबी होने का. देशमुख साहब तो आतंकी हमले के बाद राम गोपालजी को लेकर अपनी उसी स्मार्ट मुस्कान के साथ होटल ताज भी पहुंच गए. मानो अपने बेटे की नई फिल्म की स्क्रिप्ट की तैयारी निर्देशक महोदय के साथ कर रहे हों. मीडिया ने मामला उठाया तो गद्दी छिन गई और पहुंच गए दिल्ली. इस मामले में विपक्ष के शोर-शराबे के बीच पार्टी आलाकमान ने इस्तीफ़ा मांगा. आपने अनिच्छा से इस्तीफ़ा दे दिया. दिल्ली के दस जनपथ ने जब अशोक चव्हाण के उत्तराधिकारी की खोज शुरू की थी तो आपने ही फिर से एक बार लाबिंग शुरू कर दी थी. उसके बाद मैडम सोनिया की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी थी आपको. आधिकारिक तौर लेकिन परोक्ष रूप से आपको और राणे साहब को लाबिंग न करने की हिदायत दे दी गई थी. सब कुछ हुआ परंतु आपकी स्मार्ट मुस्कान पर कोई असर नहीं पड़ा. आपके लिए तो मानो कुछ हुआ ही नहीं. भारी उद्योग मंत्री रहते हुए भी आप पर एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के आरोप लगे. आपके आलोचक भी दंग हैं आपकी स्मार्ट मुस्कराहट पर. मगर देशमुख साहिब- अब यह क्या हो रहा है...... आपके मातहत रहने वाला एक मुलाज़िम ही आप पर आरोप लगा रहा है कि 2006 में आपने ही आदर्श सोसायटी घोटाले की नींव रखी थी. मतलब यह कि आपके अधीन काम करने वाला सरकारी मुलाज़िम जांच आयोग के सामने हल्फ़नामा देकर कह रहा कि आदर्श सोसायटी के सारे दस्तावेज़ों पर नगर विकास विभाग के मुखिया के नाते आपने ही हस्ताक्षर किए थे. ज़मीन का आरक्षण बदलने और सेना की ज़मीन को रिहायशी भूखंड में तब्दील करने का आदेश/निर्देश भी आपने ही दिया था. अब आप कहते हैं कि आपको कुछ याद नहीं है. फाइल देखनी पड़ेगी, क्योंकि दो बार आप राज्य के मुखिया के सिंहासन पर विराजमान रह चुके हैं. ऐसे में फाइलों पर हस्ताक्षर करने जैसी छोटी-छोटी बातें कहां याद रहती हैं, वह भी नेताओं को. उनके पास तो कितना सारा काम रहता है ना. देशमुख साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर आदर्श की फाइल को भुलाना चाह रहे हों. वैसे भी कहा जाता है कि अच्छे वक़्त में किए गए अपने बुरे व ग़लत कामों को हमारे नेता जल्दी भूल जाते हैं. वे नहीं भूलते अपने प्रतिद्वंद्वियों व विपक्षियों द्वारा किए गए भ्रष्ट कार्यकलापों को. लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कुकर्म कभी, किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं. सो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो-जो ग़लतियां की थीं धीरे-धीरे सामने आ रही हैं. जैसे की एक विधायक के साहूकार पिता की ग़ैर क़ानूनी साहूकारी का मामला हो या इस मुआ आदर्श सोसायटी का. एक मुख्यमंत्री का पद खाने और दो-चार अधिकारियों को निलंबित कराने के बाद भी इसकी ख़ुराक बढ़ती ही जा रही है. ऐसा न हो कि दो-चार और आपके पहले के मुलाज़िम आपके ख़िलाफ़ हल्फ़ पर हल्फ़नामा न पेश कर दें और आपको पुनः मजबूरन, अनिच्छा से इस्तीफ़ा देना पड़ जाए. इस आदर्श सोसायटी के भूत का कुछ करिए ना. कहीं यह आपकी स्माइल पर भारी न पड़ जाए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गांवों की ओर लौटने से समस्याएं ख़त्म होंगी

आधुनिक तकनीक इस दुनिया का भविष्य तय करने जा रही है. हमें भी इस दौड़ में नहीं पिछड़ना है. इसलिए योजना आयोग को सरकार को आधुनिक तकनीक के लिए शोध और विकास कार्यों में निवेश करने की सलाह देनी चाहिए.

● **पोषण** – स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है. गेहूं, ज्वार, बाजरा की रोटी, चावल, सब्ज़ियां और दूध किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त हैं. सौभाग्य से देश के विभिन्न हिस्सों में फल भी पैदा होते हैं. अपर्याप्त आय के कारण लोग भूखे रह जाते हैं. ग्रामीणों को दुधारू पशु पालने और उनका दूध हर बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पिलाने की समझाइश देनी चाहिए. जो लोग ऐसा करेंगे, उनके परिवार में कभी भी कुपोषण से गर्भवतियों और बच्चों की मृत्यु नहीं होगी. घरेलू मुर्गी पालन के द्वारा अंडे भी परिजनों को दिए जा सकते हैं.

● **आश्रय** –कुछ घर हर साल ग़रीबों को बनाकर दिए जाते हैं. ये ग़रीबों की विशाल संख्या के सामने कम पड़ते हैं. उनके लिए निर्माण लागत हैसियत से बाहर होती है. योजना आयोग सरकार को एक ऐसा सामुदायिक कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दे सकता है, जिसके अंतर्गत बांस, सागौन और चिनार जैसे सीधे बढ़ने वाले वृक्ष लगाए जाएं. पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ही सारे देश में बांस रोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. योजना आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए कि निकट भविष्य में स्टील, सीमेंट और ईंट दुर्लभ वस्तुएं हो जाएंगी और ये उपलब्ध नहीं होंगी. जबकि सागौन, चिनार और बांस जैसी प्राकृतिक प्रजातियां हमारे मकान, भंडारगृहों और पशुशालाओं के लिए काफ़ी काम आएंगी. हम आगामी सौ वर्षों की बजाय तुरंत के लिए ही सोचते हैं. उम्मीद है कि योजना आयोग केवल आज के लाभ की बजाय दूर भविष्य तक के लिए भी विचार करेगा. हमें आवास की समस्या सुलझाने के लिए प्रकृति को बिना नुक़सान पहुंचाए इसका लाभ उठाना होगा. हमारे लिए भविष्य का एकमात्र यही रास्ता है.

● **रिवर्स माइग्रेशन** – देश भर में अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है. लोग सुरक्षित रोज़गार की तलाश में बड़ी संख्या में गांवों से शहरों की तरफ़ आ रहे हैं. इसके फलस्वरूप देश के मेट्रोपोलिटन सहित सभी शहरों में गंदी झोपड़पट्टियां पनप रही हैं. मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में 70 से 80 लाख लोग अस्वस्थ वातावरण में रह रहे हैं. तीव्र जनसंख्या वृद्धि और गंदी झोपड़पट्टियों ने शहरी पर्यावरण को बिगाड़कर रख दिया है. शहरों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ यहां दिन-प्रतिदिन जीवन की गुणवत्ता घट रही है. सुनियोजित शहरों के लिए यहां जनसंख्या वृद्धि रोकना और बाहरी लोगों का यहां आगमन नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो गया है. इस दिशा में वनराई द्वारा किया गया रिवर्स माइग्रेशन का प्रयोग लाभकारी हल साबित हो सकता है. इन गांवों में कोई भी व्यक्ति रोज़गार की तलाश में शहर नहीं जाता है. शहरों में जा बसे लोग वापस लौटकर अपने इन गांवों में रहने लगे हैं. यहां लोग शहरों से ज़्यादा आय प्राप्त कर रहे हैं. वे यहां के स्वच्छ और हरे-भरे माहौल में सभी सुविधाओं के साथ जी रहे हैं. गांवों की ओर रिवर्स माइग्रेशन के विचार महात्मा गांधी के उपदेश- गांवों की ओर लौटो पर आधारित है. योजना आयोग को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम देश के सभी गांवों में लागू करना चाहिए. प्रयोग के रूप में कम से कम 500 गांवों को वापसी प्रवास के तौर पर नतीजे देखने के लिए आज़माना चाहिए. ग्रामीण भारत के ग़ैर-सरकारी संगठनों का महासंघ (सीएनआरआई) के देश भर से 6000 सदस्य मेरी अध्यक्षता में इस परियोजना को सफल बनाने के लिए तैयार खड़े हैं.

● **मीनारनुमा, गगनचुंबी इमारतों का चलन और शहरीकरण** – भारत अनियोजित ढंग से फैल रहे शहरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है. हमें आज प्रकृति के अनुकूल नए विकास केंद्रों की ज़रूरत है. इसके अलावा गगनचुंबी इमारतों और मीनारों को बनाने से पहले यातायात अवरोध, भीड़, पेयजल, नालियों आदि सुविधाओं पर बढ़ने वाले दबाव पर भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है. जब हम वापसी प्रवास को साकार कर लेंगे तो महानगरों में उड़ानपुल, मेट्रो रेल आदि पर धन ख़र्च करने की ज़रूरत ही नहीं होगी. योजना आयोग को सरकार को विचारों की नई दिशा दिखानी चाहिए.

डॉ. मोहन धारिया
feedback@chauthiduniya.com

भारतीय ग्रंथों में वर्णित शोध और चिकित्सा

भारतीय ग्रंथों में सर्जरी (शल्य चिकित्सा) सहित अनेक चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है. ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख है कि भारत में प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी. बिना वैज्ञानिक खोज के इन चिकित्सा विधाओं की विश्वसनीयता स्थापित नहीं की जा सकती. इसके बिना उनका दैनिक जीवन में भी उपयोग नहीं किया जा सकता. जैसा कि रामायण और महाभारत में वर्णित है, प्राचीन काल के युद्धों में ऐसे आयुधों का उपयोग किया जाता था, जिन पर आज हमें विश्वास नहीं होता, उन पर आज शोध करने की ज़रूरत है. योजना आयोग किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन लेकिन यदि शोध और प्रयोगों द्वारा इसे सिद्ध करने की बात हो तो भारत को इसके लिए क़तई नहीं हिचकिचाना चाहिए.

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए डॉ. मोहन धारिया द्वारा दिए गए सुझावों की पहली कड़ी आपने पिछले अंक में पढ़ा. प्रस्तुत है दूसरी कड़ी–

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अख़बार
महाराष्ट्र
आपके घर में अखबार देने वाले हॉकर के पास और सभी बुक स्टॉल पर उपलब्ध

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 06 जून–12 जून 2011

आमडी के ही रामचंद्र केलवदे की विधवा पति के मरने के बाद भीख मांगने को मजबूर है. उसका बीपीएल सूची में नाम है पर राशन कार्ड नहीं है.

बीपीएल कार्डधारक सूची

पूरी दाल ही काली है

बीपीएल सूचियों में इतनी विसंगतियां हैं कि ग़रीबों के नाम पर चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ उसके असली हक़दारों तक पहुंच ही नहीं पाता है. विशेषकर तब से, जब से बीपीएल सूची में कौन होगा, इसके फ़ैसले का अधिकार ग्राम पंचायत समिति को दिया गया है. वही बीपीएल का प्रमाण पत्र भी जारी करती है. इससे बीपीएल सुविधाओं का लाभ अपने नाते-रिश्तेदारों को दिलाने की होड़ ग्राम पंचायतों को भ्रष्ट बनाती है.

महेश पांडे

पहला दृश्य नागपुर ज़िले की रामटेक तहसील की पंचाला ग्राम पंचायत का. गांव में दुकान है, रहने के लिए ख़ुद का मकान है फिर भी उसके परिवार की गणना बीपीएल परिवार में होती है. एक पूर्व सरपंच के घर खेती है, रहने को मकान है और उसे बीपीएल परिवार में गिना जाता है. दूसरी ओर इसी गांव में रहने वाली विधवा सिरमन रमेश मारवते तीन लोगों के परिवार का भरण-पोषण मज़दूरी करके जैसे-तैसे करती है. सिमरन की तरह ही राजू दशरथ दूधपचारे(4 सदस्यों), ताराचंद मोहनकार (4 सदस्यों), बारकू बांगड़े (3 सदस्य), आत्माराम बागड़े (6 सदस्य) मज़दूरी कर जीवनयापन करते हैं. झोपड़ी में रहते हैं, जिसे हटाने के लिए हमेशा गांव के दबंग दबाव डालते रहते हैं. दूसरा दृश्य पारशिवनी तालुका की ग्राम पंचायत आमडी का. दिलीप शिवरकर का बीपीएल सूची से नाम 1998 में हटा दिया गया. हटाने का कारण नहीं बताया गया. आज वह और उसकी पत्नी दोनों कभी जंगल से बेलपत्र तोड़कर मंदिरों के सामने बेचते हैं, कभी बेर बेचकर गुज़ारा कर रहे हैं. उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, पर बीपीएल सूची में बार-बार अनुरोध के बाद भी उसका नाम नहीं जोड़ा गया. आमडी के ही रहने वाले अशोक चव्हाण के परिवार में 7 सदस्य हैं, मज़दूरी करते हैं, पर बीपीएल सूची से उनका नाम नदारद है. भोजराज बागड़े (3 सदस्य), अशोक शिवरकर (10 सदस्य) ये सभी रोज़ काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. झोपड़ा बना कर रहते हैं. उन्हें बीपीएल योजना की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ये विधायकों के आदमियों, ग्राम पंचायत-पंचायत समिति के अधिकारियों की मांग पूरी करने में असमर्थ हैं. आमडी के ही रामचंद्र केलवदे की विधवा पति के मरने के बाद भीख मांगने को मजबूर है. उसका बीपीएल सूची में नाम है, पर राशन कार्ड नहीं है. उसके नाम पर घरकुल (आवास) आवंटन हुआ, पर ग्राम पंचायत ने उसे रद्द कर दिया और अब वह एक पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है, जबकि गांव के ही उन लोगों के नाम बीपीएल राशन कार्ड हैं, जिनके अपने व्यवसाय हैं, खेती हैं, पक्के मकान हैं, जो अच्छी नौकरियों पर हैं, वे सभी बीपीएल सुविधाओं का लाभ उठाते हैं. इस तरह का दृश्य महाराष्ट्र की हर तहसील, हर ग्राम पंचायत में देखने को मिल जाएगा. बीपीएल सूचियों में इतनी विसंगतियां हैं कि ग़रीबों के नाम पर चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ उसके असली हक़दारों तक पहुंच ही नहीं पाता है. विशेषकर तब से, जब से बीपीएल सूची में कौन होगा, इसके फ़ैसले का अधिकार ग्राम पंचायत समिति को दिया गया है. वही बीपीएल का प्रमाण पत्र भी जारी करती है. इससे बीपीएल सुविधाओं का लाभ अपने नाते-रिश्तेदारों को दिलाने की होड़ ग्राम पंचायतों को भ्रष्ट बनाती है. समिति की सिफ़ारिश के बिना किसी का भला नहीं होता है और समिति उसी का भला करती है जो उसके अध्यक्ष व सदस्यों की मांग पूरी करता है.

संभवतः यही कारण है कि ग़रीबों के नाम पर योजनाएं तो बहुत हैं, पर उसमें सफल बहुत कम ही होती हैं. महाराष्ट्र का अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग क्या कर रहा है, इस बात की ख़बर सरकार को नहीं है और यदि है तो वह जानबूझकर आंख बंद किए हुए है. हक़ीक़त यह है कि सरकार की नाक के नीचे अन्न आपूर्ति विभाग बीपीएल सूची को लेकर अजीबो-ग़रीब रुख़ अख्तियार किए हुए है. 1999 और 2002 सन के सर्वेक्षण में अंतर है. ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में 22 लाख की कमी सरसरी नज़र में दिखती है. फिर भी अब भी 1999 के लगभग 66 लाख बीपीएल कार्ड धारकों के हिसाब से ग़रीबों के हक़ का राशन बांट कर सरकारी ख़ज़ाने को बट्टा लगाया जा रहा है. इतना ही नहीं सरकार के द्वारा जारी बीपीएल आंकड़ों को भी अन्न आपूर्ति विभाग झुठला रहा है. इससे सरकार बेख़बर है और जहां उसकी नाक के नीचे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है. वहीं बीपीएल राशन के असली हक़दार ग़रीब मज़दूर दो जून की रोज़ी-रोटी के लिए निरंतर संघर्षरत हैं. अफ़सोसनाक तथ्य यह है कि सरकार अन्न आपूर्ति विभाग के राशन वितरण सिस्टम में कोई सुधार करने की बजाए मेट्रिक्स सिस्टम, मोबाइल मैसेज और बायोमेट्रिक राशन कार्ड बनाने जैसी हाई-फाई योजनाओं का ढोल पीट रही है. सरकार को चाहिए कि पहले वह अजगरी प्रवृत्ति से कार्य करने वाले अन्न आपूर्ति विभाग की कार्य प्रणाली को दुरुस्त करे, तब बायोमेट्रिक जैसी आधुनिक तकनीक पर आधारित योजना की बात करे. सरकार ने 2002-2007 के बीपीएल सर्वे के पश्चात राज्य में लगभग 45 लाख बीपीएल परिवारों के होने की घोषणा की थी. इसके बावजूद अन्न आपूर्ति विभाग की बीपीएल सूची में 67 लाख 14 हज़ार 149 बीपीएल परिवार हैं, जिन्हें बाक़ायदा हर माह सरकार द्वारा निर्धारित 42 किलो अनाज (पहले 35 किलो) वितरित किया जा रहा है. इससे सवाल उठना लाज़िमी है कि अन्न आपूर्ति विभाग द्वारा लगभग 22 लाख से अधिक बोगस बीपीएल परिवारों को ग़रीबों के हक़ का अनाज वितरित करने का क्या औचित्य है? जो अनाज ग़रीबों के नाम पर जारी किया जाता है, वह उन तक पहुंचता है या नहीं अथवा खुले बाज़ार में बिक जाता है? यह जांच का विषय हो सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल ही केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय ने महाराष्ट्र की बीपीएल सूची पर सवालिया निशान लगाए थे. मंत्रालय का कहना था कि बीपीएल सूची में 25 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा यह दर्शाता है कि लगभग 55 लाख लोगों को ग़लत तरीक़े से इसमें शामिल किया गया है. मंत्रालय का यह भी कहना था कि लगभग 11 फ़ीसदी हक़दारों के नाम इस सूची से ग़ायब हैं.

बता दें कि राज्य की राशन दुकानों के माध्यम से तीन श्रेणी में ग़रीब व मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को अनाज वितरित किया जाता है. (1) अंत्योदय, (2) बीपीएल और (3) एपीएल. अंत्योदय परिवार को 2 रुपए गेहूं व 3 रुपए प्रति किलो चावल की दर से हर माह 42 किलो अनाज दिया जाता है. इसी तरह बीपीएल परिवार 5 रुपए किलो गेहूं व 6 रुपए किलो चावल और एपीएल परिवारों को 7 रुपए किलो गेहूं व 9.50 रुपए किलो चावल के हिसाब से 42 किलो अनाज दिया जाता है. इन योजनाओं के तहत अन्न आपूर्ति विभाग ने राज्य के 43 लाख 74 हज़ार 512 परिवारों को बीपीएल और 23 लाख 39 हज़ार 637 परिवारों को अंत्योदय योजना के अनुसार राशन कार्ड जारी किए हैं. इस तरह अन्न आपूर्ति विभाग की सूची में कुल 67,14,149 बीपीएल परिवार हुए जो राज्य सरकार की 2002-2007 की सूची से 22 लाख से भी अधिक हैं. इन 22 लाख अवैध बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 42 किलो के हिसाब से जो राशन दिया जाता है, उसकी बाज़ार में क़ीमत 500 रुपए होती है, यानी हर माह सरकार को करोड़ों का चूना अन्न आपूर्ति विभाग लगा रहा है. यदि जब से यह गोरखधंधा चालू तब से हिसाब लगाया जाए तो पांच साल में यह आंकड़ा हज़ारों करोड़ हो जाता है. इस दरम्यान सरकार द्वारा 2009 व 2010 में कराए गए बीपीएल सर्वे में बीपीएल परिवारों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है जो क्रमशः 24 लाख और 16 लाख दर्शाया गई है. इसके बाद भी अन्न आपूर्ति विभाग द्वारा 1999 की सूची पर राशन वितरण समझ के परे है. राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री अनिल देशमुख विदर्भ के हैं और शुरुआत में दिए गए मामले भी विदर्भ के हैं. देशमुख बोगस कार्ड धारकों के ख़िलाफ़ मुहिम के नाम पर लोगों से तरह-तरह के फॉर्म भरवा रहे हैं. लाखों बोगस बीपीएल राशन कार्ड रद्द करने की घोषणाएं कर रहे हैं. इस पूरी मुहिम की सबसे बड़ी खामी यह है कि जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वह राशन दुकानदारों के ज़रिये और राशन दुकानदारों व अन्न आपूर्ति विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों का रिश्ता जगज़ाहिर है. राशन दुकानदारों के ख़िलाफ़ शिकायतों का अंबार लगा रहता है पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है.

feedback@chauthiduniya.com

राज्य में बीपीएल की दो सूचियां

यह सरकारी लापरवाही का ही नतीजा है कि 2002-2007 की बीपीएल सर्वे में तैयार सूची को अब तक लागू नहीं किया गया है. नई सूची के न लागू होने से नए बीपीएल राशन कार्ड धारक योजना का लाभ प्राप्त करने से अब तक वंचित हैं और सरकार को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके साथ ही राज्य का राजस्व विभाग 1999 की बीपीएल सूची के आधार पर अनाज बांट रहा है, वहीं पंचायत समिति द्वारा भी पुरानी सूची का बीपीएल नंबर दिया जाता है. ग्राम पंचायत पुरानी बीपीएल सूची के आधार पर लोगों को बीपीएल प्रमाण पत्र जारी कर रहा है. लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र पर राशन नहीं मिलता है. साथ ग्राम पंचायत समिति को यह अधिकार है कि वह किसी का नाम बीपीएल की सूची हटा सकती है और जोड़ सकती है. इस तरह राज्य में दो-दो बीपीएल सूचियां लागू हैं.

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 06 जून-12 जून 2011

www.chauthiduniya.com

किसानों की ज़मीन पर वोटों की खेती

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में चुनावी साल आते ही नेतागण अपने बिलों से निकल आए हैं. सत्ता संघर्ष के लिए गोटे बिछाने और पीटने का खेल शुरू हो गया है. यही वजह है कि प्रदेश में धरनों और उपवास की बाढ़ सी आई हुई है. नेताओं, समाज सेवकों, धर्माचार्यों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और किसान-मज़दूरों आदि सभी को यह रोग लग गया है. गांधी को मानने और न मानने वाले सभी अपनी मांगें पूरी कराने के लिए गांधीवादी तरीक़ा अपना रहे हैं. कोई प्रदेश सरकार से नाराज़ है तो किसी की नाराज़गी केंद्र से है. ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो नौकरशाही या फिर पुलिसिया तानाशाही के ख़िलाफ़ आक्रोशित होकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं. केंद्र सरकार पर तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए ये धरने-प्रदर्शन अक्सर ही मुसीबत बन जाते हैं. सरकार सख्ती करती है तो नाराज़गी, सख्ती नहीं करती है तो परेशानी. धरने-प्रदर्शनों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती जा रही है जिन्हें जन समस्याओं को सुलझाने से अधिक अपनी राजनीति चमकाने की चिंता होती है. आम जनता को राजनेताओं के धरना-प्रदर्शन या फिर कहें उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रह गया है. राजनेताओं की छवि का अंदाज़ा जनता तो अपने हिसाब से लगाती ही रहती है, नेतागण स्वयं भी अपनी ही बिरादरी वालों को दाग़दार कहते रहते हैं. यही वजह है कि एक तरफ़ विभिन्न राजनीतिक दल किसानों के हितों के नाम पर लाठी-डंडे और जेल की हवा खा रहे हैं तो दूसरी तरफ़ एक-दूसरे पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे हैं. राहुल गांधी भट्टा परसौल गए तो मुख्यमंत्री मायावती ने राहुल को नसीहत दे डाली कि वह दिल्ली की लड़ाई यूपी में न लड़ें. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी राहुल के धरने को ड्रामेबाज़ी की संज्ञा दी. भाजपा ने तो यहां तक कहा कि जब कोई नेता भट्टा परसौल नहीं पहुंच पा रहा था, तब वह वहां कैसे पहुंच गए. इससे तो यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस और बसपा ठीक वैसे ही मिले हुए हैं जैसे लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के मामले में बसपा और सपा ने कांग्रेस का साथ दिया था. दुख की बात यह है कि जिन किसानों के नाम पर नेतागण ज़मीन-आसमान एक किए हुए हैं, उनकी बेचारगी न तो पहले कम हुई थी न आज कम हो पाई है. भट्टा परसौल में हुए कोहराम के बाद कई दिनों तक गांव के आदमी भागे-भागे घूमते रहे और घरों का चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया.

नेताओं की ड्रामेबाज़ी का ही नतीजा है कि कई बड़े मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाता है. यह दुखद ही है कि राजनेताओं को वहां की ही सुध आती है जहां वोट बैंक दिखाई देता है. यह अफ़सोस की ही बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यांत्रिक बूचड़खाने के विरोध में अन्न-जल त्याग कर धरने पर बैठे जैन योगी को समाज का तो साथ मिला, लेकिन नेताओं (भाजपा को छोड़ कर) का कोई ख़ास समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों को यही लगता है कि अगर उन्होंने जैन मुनि के समर्थन में कुछ बोला तो उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, जिस तरह से बाग़पत में 12 मई को रातोंरात जैन मुनि को धरना स्थल से हटाकर वहां लगे टैंट आदि उखाड़ कर फेंक दिए गए और उसके बाद बाग़पत की जनता विरोध पर उतर आई. इससे तो यही सबक़ मिलता है कि अब जनता को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, कोई नेता उसके साथ नहीं आएगा. एक तरफ़ मायावती अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ धूमधाम से मनाना चाहती थीं तो दूसरी तरफ़ विपक्ष उनके आयोजन में अड़ंगे लगाता दिखा. बात किसी एक मुद्दे की नहीं है. विपक्ष तो राजनीति करता है, लेकिन अन्ना जैसे व्यक्ति से राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती है. इसे अफ़सोसजनक ही कहा जाएगा कि अन्ना हज़ारे ने जब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू की तो नेताओं ने उन्हें भी नहीं छोड़ा. पहले तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए. जब बात नहीं बनी तो उनके क़रीबी लोगों पर हल्ला बोलने लगे. इस मामले में ख़ास बात यह रही कि सभी राजनीतिक दल क़रीब-क़रीब एक ही सुर में बोलते नज़र आ रहे थे. अन्ना के समर्थन में कई ज़िलों में रैलियां निकाली गईं, लेकिन वहां जाने का समय हमारे नेताओं या उनके कार्यकर्ताओं को नहीं मिला. मिलता भी कैसे वह तो मंच पर बैठे बिना अपनी बात कह ही नहीं पाते. नेताओं की दोमुंही नीति का ही नतीजा है जो आज अन्ना और जैन मुनि के आंदोलन में तो बिना बुलाए मजमा जुट जाता है, लेकिन इन नेताओं को मजमा जुटाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ता है. बात चाहे भाजपा नेताओं की हो या फिर सपा, कांग्रेस या किसानों के हित का ढिंढोरा पीटने वाले अजीत सिंह या अन्य किसी पार्टी की. इन दलों में अन्ना, जैन मुनि या फिर गांधी जैसा कोई क्यों नहीं मिलता जो जब किसी समस्या को लेकर धरने पर बैठे तो यह भी कह दें कि वह तब तक अन्न-जल को हाथ नहीं लगाएगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी. मात्र मीडिया की सुर्ख़ियों में आने के बाद एसी कमरों में बैठ कर इस कवरेज को देखने वाले नेताओं से जनता का कोई भला होगा इसकी उम्मीद नहीं है. किसानों के उत्पीड़न के नाम पर जुटने वाले नेतागण यदि इन पुलिस वालों के यहां भी हो आते जिनकी इस घटना में मौत हो गई तो कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन शायद यह उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं था.

बीती 11 मई की सुबह भट्टा परसौल गांव में किसानों के समर्थन में नाटकीय तरीक़े से राहुल गांधी के धरने पर बैठ जाने की बात हो या फिर देर रात उन्हें छोड़ दिए जाने का मामला, सब कुछ जैसे प्रायोजित लग रहा था. राहुल से पूछना चाहिए था कि क्या उन्होंने कभी अपनी सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान क़ानून बनना चाहिए. फिर आंदोलन तो जनवरी से चल रहा था. अब तक राहुल कहां थे. भट्टा परसौल में राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस सांसद राज बब्बर और परवेज़ हाशमी सहित पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया. नतीजतन 12 मई को कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश में रास्ता और रेल मार्ग जाम कर ख़ूब हो हल्ला मचाया. उत्तर प्रदेश विधान भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया. इसके बाद रीता बहुगुणा जोशी और कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी सहित कई नेताओं की धर-पकड़ का ड्रामा चला. वहीं लखनऊ, आगरा, बनारस, झांसी, मथुरा, कानपुर सहित अनेक ज़िलों में कांग्रेसियों ने धरना-प्रदर्शन व पथराव किया तो पुलिस ने लाठियां भांजी. प्रदेश में गुरिल्ला युद्ध की भांति प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं राहुल की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप अन्य प्रदेशों में भी धरना, प्रदर्शन की बाते सामने आईं, लेकिन इसके बाद राहुल का क़ाफ़िला मानो आगे बढ़ गया. दूसरी तरफ़ भट्टा परसौल मामले में पीछे न रह जाने को आतुर भाजपा भी हाथ-पैर मारती दिखी. ग्रेटर नोएडा में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरूण जेटली, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही उपवास पर बैठ गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. बात तब भी नहीं बनी तो 13 मई को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही समेत कई बड़े नेता, कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर गांव भट्टा पारसौल की सीमा तक पहुंच गए. गांव में घुसने का प्रयास करने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वहीं किसानों के हितों के नाम पर उत्तर प्रदेश में ज़मीन तलाश रहे राम विलास पासवान, शरद पवार आदि नेता भी सामने आ गए. पूरे राजनीतिक ड्रामे का सार 2012 के विधान सभा चुनाव पर टिका हुआ दिखा. बसपा सुप्रीमो और मुख्यमंत्री मायावती को जब लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो वह प्रेस कांफ्रेस के सहारे अपनी बात कहने के लिए सामने आ गईं. मुख्यमंत्री ने राहुल के धरने को अराजक तत्वों को बढ़ावा देने वाला तो बताया ही, साथ ही इस बात पर दुख भी व्यक्त किया कि राहुल गांधी और कांग्रेसियों को जिस समय रायबरेली में होना चाहिए था, वह भट्टा परसौल में धरने पर बैठे थे. मायावती ने आरोप लगाया कि रायबरेली में किसानों से रेल कोच फैक्ट्री के लिए ज़मीन ली गई थी, जिसका उन्हें पर्याप्त मुआवज़ा नहीं मिला और इसके ख़िलाफ़ किसान प्रदर्शन कर रहे थे. वे केंद्र सरकार और कांग्रेस से ख़फ़ा थे. उन्होंने कांग्रेस के युवराज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी अपने घर में तो चल नहीं रही है, इसलिए वह दूसरी जगह ताक़त आज़मा रहे हैं.

मायावती ने भट्टा परसौल गांव में किसान-पुलिस संघर्ष को विपक्षी पार्टियों की घिनौनी राजनीति का हिस्सा क़रार देते हुए कहा था कि विरोधी दल इस मामले को ज़मीन के मुआवज़े से जोड़कर दुष्प्रचार कर रहे हैं. मायावती ने कहा कि जब विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वे सभी झूठ और अफ़वाहों का सहारा लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर यहां की क़ानून व्यवस्था बिगाड़ने में जुट गईं. कांग्रेस के साथ बसपा की कथित साठगांठ के बारे में समाजवादी पार्टी और भाजपा के आरोपों को ख़ारिज करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि लालगंज में ये दोनों दल किसानों के मुआवज़े की बात नहीं उठाते, जिसका मतलब है कि हक़ीक़त इसके ठीक उलट हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बसपा नहीं, बल्कि सपा और भाजपा की साठगांठ है. बसपा अध्यक्ष ने कहा कि विरोधी दलों ने जब भी मेरी पार्टी या मेरी छवि ख़राब करने के लिए हमला बोला है तो हमारी पार्टी और तेज़ी से आगे बढ़ी है. विपक्ष के दुष्प्रचार से बसपा को लाभ ही मिला है. अब लगता है कि पूरा मामला राजनीतिक रूप से पीछे चला गया है. हिसाब इस बात का हो रहा है कि किसको कितना फ़ायदा हुआ. पहले लोकसभा चुनाव इसके बाद बिहार विधान सभा चुनाव में भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए राहुल के पीछे कांग्रेसी पूरी ताक़त के साथ खड़े हैं तो इसे उनकी मजबूरी ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके पास दूसरी लीडरशिप है ही नहीं. वहीं भाजपा अपने पुराने चेहरों के साथ ही फिर से चुनावी बिगुल बजा रही है. समाजवादी पार्टी जो हमेशा इस तरह के मामलों को उछालने में आगे रहती है. इस मामले में राष्ट्रीय लोकदल ने भी सपा से बाज़ी मार ली. भट्टा पारसौल पर शायद अब पर्याप्त राजनीति हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनेताओं का अगला पड़ाव बहराइच ज़िले का गांव कल्पीपारा हो, यहां भी भट्टा पारसौल की तरह आक्रोश की चिंगारी सुलग रही है. यहां 478 बीघा कृषि योग्य भूमि आवास विकास परिषद के लिए अधिग्रहित की जा रही है. किसानों को इस बात का तो दुख है कि बग़ल में पड़ी बंजर ज़मीन को परिषद ने इस काम के लिए नहीं लिया, वहीं मुआवज़ा कम होने का दुख भी उन्हें खाए जा रहा है.

माया‌वती ने कहा कि विरोधी दलों ने मेरी पार्टी या मेरी छवि ख़राब करने के लिए हमला बोला है तो हमारी पार्टी और तेज़ी से आगे बढ़ी है. विपक्ष के दुष्प्रचार से बसपा को लाभ ही मिला है. अब लगता है कि पूरा मामला राजनीतिक रूप से पीछे चला गया है. हिसाब इस बात का हो रहा है कि किसको कितना फ़ायदा हुआ. पहले लोकसभा चुनाव इसके बाद बिहार विधान सभा चुनाव में भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए राहुल के पीछे कांग्रेसी पूरी ताक़त के साथ खड़े हैं तो इसे उनकी मजबूरी ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके पास दूसरी लीडरशिप है ही नहीं.

feedback@chauthiduniya.com

खुद एस.पी. मंजिल सैनी निर्ममता से निहत्थे कांग्रेसियों पर लाठियां बरसा रही थीं. इसलिए अन्य पुलिसकर्मी भी उनका अनुसरण कर रहे थे.

दलित की बेटी से अब दौलत की बेटी कही जाने वाली मायावती भी हरिद्वार में मिले बेशक़ीमती उपहारों से प्रसन्न दिखीं.

एक नज़र

आलू से बिजली पैदा की

[illegible]

छात्रों ने हंगामा किया

[illegible] के अनेक छात्र सुबह 10 बजे कॉलेज प्रांगण में इकट्ठा हुए और हंगामा करना शुरू कर दिया. प्रधानाचार्य ने जब छात्रों से हंगामे का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वाणिज्य विषय के शिक्षक ने उनसे पास करने के नाम पर पांच-पांच हज़ार रुपये वसूले हैं. इसके बाद भी उन्हें फेल कर दिया गया. जब उन्होंने शिक्षक से अपने रुपये वापस मांगे तो उसने कॉलेज से निकालने की धमकी दी. छात्रों ने काफ़ी देर तक वाणिज्य शिक्षक के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की. प्रधानाचार्य ने छात्रों को शिक्षक के ख़िलाफ़ लिखित शिकायत मांगी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. प्रधानाचार्य ने बताया कि उक्त शिक्षक से छात्र ट्यूशन पढ़ते थे. मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के भय से महिला की मौत

आम आदमी पर पुलिस का कितना ख़ौफ़ है, इसे लखनऊ के कुराहीखेड़ा गांव में सिपाहियों को देखते ही दहशत से हुई एक महिला गुड्डी की मौत से समझा जा सकता है. कुराहीखेड़ा निवासी सगे भाई राम गणेश उर्फ़ पुत्ती और ननकऊ का वीरेंद्र से झगड़ा हुआ था. इस पर रामगणेश ने थाने में तहरीर देकर वीरेंद्र की शिकायत की थी. इस पर प्रमोद यादव और एक अन्य सिपाही छानबीन करने के लिए कुराहीखेड़ा पहुंचे थे. वीरेंद्र के परिवार में उस समय केवल उसकी पत्नी गुड्डी थी. गुड्डी ने किसी मारपीट की बात से इंकार किया. इसी दौरान वह अचानक गिर पड़ी. उसे आनन-फानन में पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां इसकी मौत हो गई. गुड्डी के चार बच्चे हैं. परिवार के लोग पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार का सीधा आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सिपाहियों के आने के बाद ही गुड्डी की मौत हुई है. पुलिस वाले यदि नहीं आए होते तो गुड्डी की मौत नहीं हुई होती.

अयोध्या की नौगज़ी क़ब्र पर बौद्धों का दावा

डॉ. भदंतश्री करुणाशील महाथेरा ने अयोध्या के प्रमोद वन में स्थित नौगज़ी क़ब्र को अशोक स्तंभ का स्थान बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. डॉ. भदंतश्री ने अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में यह दावा किया. उनका कहना है कि नौगज़ के किसी आदमी के होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. यहां सम्राट अशोक के स्तंभ को दबाया गया है, जबकि स्तंभ के शीर्ष भाग को नागेश्वरनाथ मंदिर में रखा गया है, जिस पर वर्तमान मे शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है. नागेश्वरनाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश की ओर से स्थापित करने की धारणा को कपोल-कल्पित बताया. डॉ. भदंतश्री करुणाशील महाथेरा रामजन्मभूमि को भी बौद्धों की संपदा बताते हुए कहते हैं कि खुदाई में मिली मूर्तियां तथागत एवं माता विशाखा की हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अब न बजेगी किसानों की रणभेरी

डॉ. के.एस. राणा

किसान आंदोलन का शंखनाद क्या अब हो सकेगा? यह यक्ष प्रश्न ग्रामीणों के दिमाग़ में कौंध रहा है. [illegible]

feedback@chauthiduniya.com

फ़िरोज़ाबाद

पुलिस की वर्दी में अपराधी

शिवम तिवारी

उत्तर प्रदेश के भट्टा पारसौल में की गई राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने चक्का जाम का ऐलान किया था. फ़िरोज़ाबाद जनपद में भी कांग्रेसियों का यह विरोध-प्रदर्शन चरम पर था. उत्साही कांग्रेसजन ज़िला प्रशासन की कड़ी नाकेबंदी के बावजूद नेशनल हाइवे स्थित सुहागनगर चौराहे पर चक्का जाम करने में सफल रहे. यह चक्का जाम प्रदेश मानवाधिकार कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनव चतुर्वेदी के नेतृत्व में लगाया गया. प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ सैकड़ों उत्साही नौजवानों ने नारेबाज़ी कर बसों एवं वाहनों को रोककर रास्ता जाम कर दिया था. इस बीच पुलिसवालों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी होती रही. बाद में कांग्रेसजन गर्मजोशी लेकिन अहिंसक तरीक़े से सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर कट पर बैठ गए और अपना विरोध-प्रदर्शन करने लगे. आवागमन शुरू कर दिया गया. उसी समय अचानक मौक़े पर पहुंची एस.पी मंजिल सैनी के नेतृत्व में पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के सड़क पर बैठे कांग्रेसियों पर ताबडतोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दिया. ख़ुद एस.पी. मंजिल सैनी निर्ममता से निहत्थे कांग्रेसियों पर लाठियां बरसा रही थीं. इसलिए अन्य पुलिसकर्मी भी उनका अनुसरण कर रहे थे. क्षणभर में कांग्रेसी लहुलुहान हो गए. अफरा-तफ़री मच गई. कांग्रेसियों के साथ राहगीरों और ठेले वालों को भी पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा. पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारी-कर्मचारी सबसे अलग दिखने, प्रदेश के सत्तापक्ष के मुखिया की निगाह में आने और अतिरिक्त लाभ पाने की आकांक्षा से अतिवादी क़दम उठाते हैं. ऐसा करके कुछ अधिकारीकर्मचारी सत्तापक्ष के नजदीक हो भी जाते हैं और अतिरिक्त लाभ भी उठा लेते हैं. लेकिन ऐसे अतिवादी अधिकारियों की मिट्टी उस समय ख़राब हो जाती है, जब प्रदेश या केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है. फ़िरोज़ाबाद में एक ऐसे ही अतिवादी पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी हैं, जिन्होंने अतिवादिता की सारी हदें तोड़कर निहत्थे लोगों पर ख़ुद लाठीचार्ज करके सरेआम मानवाधिकार की हत्या ही नहीं कि बल्कि पूरे पुलिस बल को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे भी उनका ही अनुकरण करके दमन का क्रूर चक्र चलायें.

इस लाठीचार्ज में सड़क पर धरना दे रहे कांग्रेसजनों को वहां से हटने की कोई चेतावनी तक नहीं दी गई, जबकि इस प्रकार के आंदोलनों में पुलिस द्वारा हटने की चेतावनी दी जाती है. यदि आंदोलनकारी नहीं मानते, तब इन्हें थोड़ा बल प्रयोगकर हटाया जाता है. लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ. एस.पी. के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसवालों ने निहत्थे बैठे लोगों पर बिना कोई चेतावनी दिए बर्बरता से लाठियां बरसाईं. आलम यह था कि एस.पी. सिटी जमकर पुलिस के साथ ख़ुद लाठियां बरसाकर अपनी ताक़त का अहसास करा रही थीं. शहर के अन्य राजनीतिक दलों और नागरिकों को यह संदेश देना चाह रहीं थीं कि कोई भी ऐसा करेगा, तो उन्हें भी ऐसी ही बर्बरता का शिकार होना पड़ेगा. पुलिस की बर्बरता का सबसे अधिक शिकार कांग्रेस नेता अभिनव चतुर्वेदी हुए. शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अमित उपाध्याय पर भी चारों तरफ से लाठियां बरसायीं गईं, जिससे उनके सिर पर पड़ी लाठी से सिर फट गया और ख़ून की धारा बहने लगी. अन्य घायलों में जिला उपाध्यक्ष संदीप तिवारी, संजय श्रोतीय, राजकुमार पालीवाल एवं पूर्व विधायक ओम प्रकाश दिवाकर, यूथ कांग्रेस के सुबुर अली, लाला राइन को भी पुलिस ने पीटा. पुलिस ने सभी घायलों को जेल भेज दिया. एस.पी. की बर्बरता को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल चतुर्वेदी, शहर अध्यक्ष शफात ख़ान राजू, पी.सी.सी. गुलाम जिलानी, कुसुम सिंह, कल्पना सिंह, उजमा देवी, सतीश नेता, राजेश शर्मा आदि भी भड़क उठे. ये सभी लोग अपने गिरफ्तार साथियों के साथ जेल जाने को अड़ गए, तब पुलिस ने उन्हें भी जेल भेज दिया. जिन 35 लोगों को जेल भेजा गया था इन पर धारा 151, 107/116 लगाई गई. इस घटना पर यहां से सांसद राजबब्बर ने ख़ेद जताते हुए कहा कि एस.पी. और पुलिस द्वारा बर्बरता से जनता की समस्याओं की लडाई को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि यह संघर्ष और बढ़ता ही जाएगा.

एस.पी. और पुलिस द्वारा बर्बरता से जनता की समस्याओं की लडाई को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि यह संघर्ष और बढ़ता ही जाएगा.
- सांसद राजबब्बर

पुलिसिया अत्याचार से कांग्रेसी हिम्मत हारने वाले नहीं, घायल साथियों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है.
-प्रदीप माथुर, विधायक, मथुरा एवं कांग्रेस विधानमंडल दल उपनेता

शांतिपूर्वक सड़क पर बैठे कांग्रेसियों पर एस.पी. ने लाठियां बरसाईं, उनकी बर्बरता अंग्रेजी हुकूमत की यादों को ताज़ा कर रही है, मेरी चोटों और मेरे साथियों की चोटें 1947 से पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लाला लाजपतराय पर हुए लाठीचार्ज को याद कराती हैं.
- अभिनव चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष

एस.पी. मंजिल सैनी और उनकी पुलिस का अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत की यादों को ताज़ा कर रहा है. प्रदेश सरकार की दमनात्मक कार्यवाही से कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ने से नहीं पीछे नहीं हटेगी.
- अतुल चतुर्वेदी, ए.आई.सी.सी. सदस्य

पुलिस अधीक्षक ने स्वयं क़ानून व्यवस्था को ध्वस्त किया. बिना चेतावनी दिए लाठीचार्ज करना सरासर लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है. विरोधी दलों को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
-योगेश बघेल, जिलाध्यक्ष

feedback@chauthiduniya.com

सोशल ऑडिट का परीक्षण

असहयोग और उपेक्षा उजागर

अरविंद त्रिपाठी

कानपुर के एक पूर्व जिलाधिकारी ने शून्य-बजट खेती, एकलव्य योजना, सास-बहू सम्मेलन, गंगा के घाटों की सफ़ाई में सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठनों का सहयोग, ग्राम पंचायतों में पॉलीथिन के ख़िलाफ़ जन-अभियान का प्रारंभ और ग्राम प्रधानों का राजनहतिक और मानवीय प्रशिक्षण जैसे प्रयोग किए गए थे. कानपुर की जनता ने इसे हाथों-हाथ लिया. समय बदला तो कानपुर का निज़ाम भी बदला. कानपुर में नए मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के आने के बाद से काफ़ी समय प्रशासन के रुटीन कामों के अतिरिक्त नवीन पहल का लंबे समय से इंतज़ार था. इस चुप्पी को तोड़ते हुए ज़िला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट का काम शुरू किया. इसका उद्देश्य ज़िले के आला अधिकारियों में प्रदेश सरकार की जनोपयोगी योजनाओं का वास्तविकता के धरातल पर मूल्यांकन था. यह एक परीक्षण था कि निचले पायदान के प्रशासन के नुमाइंदे योजनाओं को किस बेतरतीबी से क्रियान्वित कर रहे हैं, दरअसल, यह आम जनता के सामने खुली जांच प्रक्रिया के माध्यम से सरकार आप के द्वार जैसा क़दम ही था. सोशल ऑडिट के परीक्षण में जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में मनरेगा, पंचायत भवन और आदर्श जलाशय योजना जैसी अति महत्वाकांक्षी जनउपयोगी योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीण समाज तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है या नहीं, और किया जा रहा है तो किस गति से.

प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शुरू किए गए सोशल ऑडिट सर्वे में प्रदेश के विकासोन्मुखी नज़रिए और क्रियान्वयन के स्तर पर असहयोग और उपेक्षा साफ़ तौर पर उजागर हुई. कानपुर जिला प्रशासन द्वारा ज़िला पंचायतराज अधिकारी के.एस.अवस्थी को कानपुर के घाटमपुर विकास खंड के गुच्चूपुर एवं मखौली ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था. उन्होंने दोनों ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में आम ग्रामीणों के साथ खुली बैठक कीं. अपनी आख्या में उन्होंने ग्राम पंचायत गुच्चूपुर में परित्यक्त पंचायत भवन की तकनीकी जांच कराने के मौक़े पर ही आदेश कर भवन की पुनरोपयोगिता के आदेश किए. नवनिर्मित पंचायत भवन में चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग इकाई को किराया जमा न करने की दशा में सील करने के आदेश मौक़े पर ही जारी किए. पंचायत सफाईकर्मी की कार्य के प्रति उपेक्षा की शिकायत पर प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश दिए. ग्राम पंचायत मखौली में सफाईकर्मी विगत पांच माह से अनुपस्थित पाया गया, जिसका वेतन रोके जाने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया गया. इसी ग्राम पंचायत मखौली में विद्यालय में निर्मित शौचालय में दरवाज़ा नहीं लगा पाया गया. ग्राम पंचायत सचिव और सहायक विकास अधिकारी (पं.) को प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश दिया गया. यहां आंगनवाड़ी केंद्र की कमी को पूरा करने की जनता की मांग को उच्चाधिकारियों के सामने लाने का आश्वासन देते हुए अवस्थी ने ढाई वर्षों से एएनएम के नहीं आने की शिकायत भी अपनी जांच आख्या में की. प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री दद्दू प्रसाद के आदर्श जलाशय योजना को हर हाल में लागू करने के निर्देशों को पूरी तरह से ग्राम पंचायतों में लागू नहीं किया जा रहा है. इन दोनों ग्राम पंचायतों में की गई जांच में पाया गया कि एक भी आदर्श जलाशय का निर्माण अभी तक नहीं किया गया था, जबकि विगत वर्ष शासन से इस संबंध में मांगी गई सूचना पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श जलाशय के खुदवा लिए जाने की सूचना दी जा चुकी थी. ग्राम पंचायत गुच्चूपुर में विगत तीस वर्षों से कोई तालाब नहीं खोदा गया था, जबकि मखौली में एकमात्र तालाब खोदा गया, जिसे आदर्श जलाशय के मानकों के अनुरूप नहीं खोदा गया था, जबकि दोनों ग्राम पंचायतों के खातों में लाखों रुपये शेष हैं और उनका अभी तक किसी जनउपयोगी योजना में उपयोग नहीं किया गया. आदर्श जलाशय योजना के प्रति उपेक्षा का कारण यह भी सामने आया कि अधिकतर तालाबों पर क़ब्ज़े हो चुके हैं. जबकि सर्वोच्च न्यायालय का तालाबों से अतिक्रमण हटवाने के बारे में स्पष्ट निर्णय है. वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से तालाबों की कमी के कारण पेयजल संकट दिनोदिन गहराता जा रहा है. कुओं के समाप्त प्राय: हो जाने की दशा में हैंडपंपों पर पेयजल आपूर्ति का बोझ बढ़ता जा रहा है. जल संरक्षण के महत्व को मानते हुए अवस्थी कहते हैं कि गांवों में अब तालाबों के संरक्षण की परंपरा समाप्त होती जा रही है, जिसका ख़ामियाज़ा मानव और पशु-पक्षियों को उठाना पड़ रहा है. यदि ग्रामीणों ने इस प्रकार से जलाशयों के निर्माण में शासन की मदद और मंशा का लाभ नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ़ नहीं करेंगी. केंद्र सरकार की सुनिश्चित ग्रामीण रोज़गार मुहैया कराने की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का सबसे बुरा हाल आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है. समय पर भुगतान न होना और विगत वर्ष के कराए गए काम का लगभग 35 से अधिक मज़दूरों का मेहनताना न दिया जाना ग्राम पंचायत गुच्चूपुर में एक गंभीर विषय मानते हुए अवस्थी ने तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत की. इसी प्रकार काम में लगे श्रमिकों की संख्या और मस्टर रोल में श्रमिकों की संख्या में भिन्नता की समस्या पूरे देश में पाई जा रही है. इसी प्रकार मनरेगा के शासनादेश में श्रममूलक और तकनीकी मूलक कामों के अनुपात का सही अनुपालन भी नहीं पाया गया. अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरलॉकिंग टाइल्स का उपयोग मनरेगा के कामों में किया जा रहा है, जबकि शासनादेश में इसे पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जा चुका था. ग्राम पंचायत गुच्चूपुर में भी इंटरलाकिंग टाइल्स के प्रयोग का मामला प्रकाश में आने पर वसूली के आदेश जारी किए गए.

feedback@chauthiduniya.com

एसडीएम का पुलिस से भरोसा उठा

देवेंद्र कौशिक

मथुरा में तैनात एसडीएम सदर राकेश मालपानी को कुछ असामाजिक तत्वों ने बंधक बनाकर घायल कर दिया और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने से बच रही है. मामला आईजी और कमिश्नर दोनों के संज्ञान में आया तो उन्होंने भी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश कर दिए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात ही रहा है. गोवर्धन में 1 जुलाई 2010 को गुरु पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मथुरा दिनेश कुमार सहित जनपद के तमाम अधिकारी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए रणनीति बना रहे थे. अचानक विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने और रोड जाम करने की सूचना मिली. मौक़े पर एसडीएम राकेश मालानी पहुंचे तो उन्हें बंधक बना लिया गया. बाद में विधायक के रिश्तेदार श्रीधर पाठक और उनके साथियों ने पत्थर बरसाए. एसडीएम राकेश मालपानी का इसमें सिर फूटा था. थाना गोवर्धन में नरेश कुमार एसडीओ उपखंड अधिकारी द्वितीय विद्युत वितरण खंड ने मुक़दमा (संख्या 351 सन 2010 को 147, 323, 353, 336, 347, 427 भारतीय दंड विधान के अलावा 7 सी क्रिमिनल एक्ट के तहत सोलह लोगों को नामज़द करके) पंजीकृत कराया. मुक़दमे की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक कांतीप्रसाद भारद्वाज को सौंपी गई. तफ़्तीश शुरू होने की बात जानकर श्रीधर पाठक और अन्य लोग विधायक के दरबार में पहुंचे. लौटकर उन्होंने क़स्बे में ज़ोर शोर से प्रचार किया कि विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई भी आदमी जेल नहीं जाएगा. विवेचक भी सत्तापक्ष के इस प्रचार से प्रभावित हुए. उसने आरोपियों की गिरफ्तारी न करना ही उचित समझा. विवेचक ने चार अन्य लोगों के नाम इस मामले में बढ़ाकर कुल आरोपियों की संख्या बीस करके बिना किसी को गिरफ्तार किए आरोपपत्र न्यायालय में दाख़िल कर दिया. बिजलीघर गोवर्धन पर जाम लगाने वालों में प्रमुख रूप से बसपा नेता श्रीधर पाठक, छैलो पंडित थे, लेकिन पुलिस ने सभ्रांत अध्यापक जपाकरलाल शर्मा, चंद्रशेखर, मनोज पंडित आदि को भी आरोपियों में शामिल करके अपनी अति सक्रियता दिखा कार्रवाई की इतिश्री कर दी, जबकि ये राजस्थान में अध्यापक हैं जो सुबह घर से जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं. एसडीएम राकेश मालपानी का इस संबंध में कहना है कि हम सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर नौकरी करने आते हैं. जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं. ऐसे में कोई अराजक तत्व अगर किसी अधिकारी से बदतमीज़ी करके उसे घायल कर दे और पुलिस उसे समाज में खुला घूमने दे तो इससे अधिकारी का मनोबल गिरता है. जब पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा. मथुरा जनपद की पुलिस आरोपियों को पकड़ने से कतरा रही है. बसपा के कार्यकर्ता होने के नाम पर दसविसा क्षेत्र के दो तीन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क गोवर्धन में है. उनका काम सिर्फ़ पार्टी के नाम का पुलिस व जनता पर रौब दिखाकर क़स्बे में सट्टे की खाईवाड़ी के साथ चरस-अफ़ीम-गांजा जैसे मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करना है. उन्होंने भोले-भाले लोगों को सोने की ईंटों के नाम पर पीतल की ईंटें बेचने वाले टटलू गैंग से भी संपर्क साध लिया और गारंटी दी कि पुलिस से बचना है तो वह उनसे हाथ मिलाए. टटलू गैंग और भूमाफ़िया को साथ मिलाकर उन लोगों ने ज़मीनों पर भी अवैध क़ब्ज़ा कराना शुरू कर दिया. पूर्व थानाध्यक्ष मनीष सक्सेना ने विधायक के नाम पर उनके रिश्तेदारों व चमचों द्वारा की जाने वाली सिफ़ारिशों पर ध्यान देना बंद कर दिया और सट्टे की खाईवाड़ी से लेकर चरस-अफ़ीम-गांजा बेचने वाले या टटलुओं को छोड़ना बंद करके उन पर कार्रवाई करना शुरू किया तो बसपा नेताओं को बहुत अखरा. उन्होंने मनीष सक्सेना को उनके पक्ष में न चलने पर थाने से हटवाने की धमकी दे दी. इन दिनों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लवकुमार की ईमानदारी से जनपद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था. पंचायत चुनावों की अधिसूचना 16 सितंबर 2010 को जारी हुई थी. इसी दिन बसपा विधायक के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव कराने के लिए पुलिस कप्तान ने दो थाना प्रभारियों का फेरबदल करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया. प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की अधिसूचना 16 सितंबर को जारी हो चुकी थी. अधिसूचना जारी होने के बाद भी थाना प्रभारी नौहझील कैलाश चंद्र शर्मा को थाना प्रभारी गोवर्धन और गोवर्धन थाना प्रभारी मनीष सक्सेना को थाना नौहझील को प्रभारी नियुक्त कर दिया गया. कांग्रेस के विधायक प्रदीप माथुर व शहर अध्यक्ष आबिद हुसैन कांग्रेस कमेटी मथुरा ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेंद्रसिंह भोनवाल से अपनी शिकायत दर्ज कराकर उपरोक्त स्थानांतरण से चुनाव प्रभावित होने की बात कही थी. अधिवक्ता डॉ. ब्रजगोपाल शर्मा के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना या विशेष परिस्थिति में निर्वाचन आयोग की परमिशन से ही कोई स्थानांतरण क़ानूनन वैध होता है. एस.एस.पी. लव कुमार ने बताया कि दोनों उपनिरीक्षकों का तबादला 15 सितंबर को किया जा चुका था तो स्थानांतरण के आदेश को क़रीब 14 घंटे क्यों, किसने और किसके आदेश से रोके रखा?

रिपोर्ट में गड़बड़ी

बीती 1 जुलाई 2010 को तोड़फोड़ और जाम की घटना गोवर्धन में हुई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट नरेश कुमार एस.डी.ओ. उपखंड अधिकारी द्वितीय विद्युत वितरण खंड ने लिखवाई, जो सौंख में तैनात थे. ऐसा इसलिए हुआ कि गोवर्धन के एसडीओ असामाजिक तत्वों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे. तथाकथित बसपा नेताओं से शत्रुता लेना उन्होंने उचित नहीं समझा. इसलिए उनके स्थान पर सौंख के एसडीओ से रिपोर्ट लिखवाई गई. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ निर्दोष लोगों को भी शामिल कर दिया. यह सब अनजाने हुआ या किसी की शह पर कहा नहीं जा सकता. बहरहाल यह सही है कि जो लोग नामज़द किए गए हैं, उनमें से कुछ तो मौक़े पर थे ही नहीं.

feedback@chauthiduniya.com

मायावती सर्वसमाज को साथ लेकर चलेंगी

मायावती की हरिद्वार रैली ने मिशन 2012 के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. इस रैली को धर्म नगरी में मिली सफ़लता ने प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है. सभा में उत्साह से लबरेज़ मायावती ने कहा कि बसपा राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और भी दल से चुनावी तालमेल नही करेगी. कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती गति को रोकने के लिए लगातार दोनों दल उन्हें कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंसाने का प्रयास करती रहती है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं हैं. मायावती ने मंच से केंद्र की कांग्रेस सरकार एवं सूबे की निशंक सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों की ग़लत आर्थिक नीतियों के कारण देश एवं प्रदेश में महंगाई बढ़ी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि बसपा के टिकट वितरण में वह सर्वसमाज के लोगों का पूरा सम्मान करते हुए उनका ख्याल रखेंगी. हरिद्वार में जिस तरह बसपा का जनाधार बढ़ रहा है इससे भाजपा कांग्रेस की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक ही है. मायावती की रैली का जवाब कांग्रेस राहुल गांधी की रैली से देना चाहती हैं. बसपा की रैली में भीड़ को देखकर लगता है कि राज्य की जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में बसपा का दामन थाम सकती है. ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय दल भाजपा कांग्रेस का क्या होगा. मायावती ने हरिद्वार में सर्वसमाज का नारा उछाल कर जिस तरह अगड़ी जाति बाहुल्य उत्तराखंड में सत्ता की चाभी बसपा के हाथ होने की बात अपने कार्यकर्ताओं को समझा कर सूबे में भाजपा कांग्रेस का विकल्प बनने का मंत्र दिया है, उससे आने वाले चुनाव में बसपा की सरकार बनाने का सपना बहुजन पार्टी के नेता भी देखने लगे हैं. पिछले संसदीय चुनाव में हरिद्वार सीट पर दलित-मुस्लिम मतदाताओं की मदद से हरिद्वार सीट पर क़ब्ज़ा करने वाली कांग्रेस के सांसद हरीश रावत को बसपा ने जिलापंचायत चुनाव में भाजपा की मदद से अपनी गोटी लाल कर चुकी बसपा ने जिस तरह आइना दिखा कर बगले झांकने को मजबूर किया है. कांग्रेस ने अपनी गुटबाज़ी पर लगाम समय रहते नहीं लगाया तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा. मायावती ने जिलापंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के सहयोग से हासिल किया है. उन्होंने जिस तरह सभी सीट पर अकेले ताल ठोकने के साथ आगामी चुनाव में किसी भी दल से ताल मेल न करने की बात कही है, इससे सत्ता की ऊंट किस करवट बैठेगी कहना कठिन है. देवभूमि के बसपा नेता अपने नेता को ख़ुश करने की हर कोशिश करने में लगे हैं, बसपा विधायकों ने इस अवसर पर सोने से बना बहुमूल्य हाथी प्रदान किया. विधायक मो. शहज़ाद, हरिदास, तस्लीम, सुरेंद्र राकेश नारायण पाल एवं प्रेमानंदजी के संयुक्त प्रयास से लगभग एक किलो से अधिक वज़न वाला हाथी का निर्माण करा कर भेंट किया. जिलापंचायत सदस्य शेषराज सैनी और इनके साथियों ने सोनी की तलवार भेंट किया तो इससे एक क़दम आगे बढ़ कर जिलापंचायत की नव नियुक्त अध्यक्ष अंजुम बेगम ने अपने नेता को नवलखा हीरे का हार भेंट किया. दलित की बेटी से अब दौलत की बेटी कही जाने वाली मायावती भी हरिद्वार में मिले बेशक़ीमती उपहारों से प्रसन्न दिखीं. मायावती की पार्टी में प्रत्याशी बनने के लिए धनवानों की बड़ी फ़ौज अपनी तिजोरी लुटाने को तैयार है. दलित उत्थान में अब तक फिसड्डी रहे उत्तराखंड में भाजपा कि सरकार ने जो भूमिका निभाई है इसका पूरा लाभ बसपा को मिल सकता है. इस राज्य में बुनियादी सुविधाओं और हक की लड़ाई में जानबुझ कर भाजपा सरकार ने दलितों को पिछे रखा. सूबे के शहरी विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण सेवा योजना सहित कई विभागों ने अनुसूचित जाति के विकास की योजनाओं में ख़र्च करने वाली धनराशि को ख़र्च करने की ज़रूरत ही नही समझी, जिससे अनुसूचित जाति सब प्लान की 750 करोड़ की राशि लैप्स हो गई, जिसे बसपा इस चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है. चुनावी दौर में इस राज्य में होने वाले चुनाव को बसपा त्रिकोणात्मक बनाने की हर कोशिश कर रही है. उक्रांद सहित सूबे की इलाक़ाई दलों के तंगहाली का लाभ भी इस चुनाव में बसपा को मिलेगा. राज्य की राजधानी गैरसैंड के नारे का समर्थन करके बसपा इस मुद्दे को भी अपने पाले में लाने की हर कोशिश कर रही है.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

गजराज ने हैंडपंप पर प्यास बुझाई

चिलचिलाती धूप में आदमी ही नहीं जानवर भी परेशान हो जाते हैं. पिछले दिनों वाराणसी के रामनगर में एक गजराज को बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी. उसने चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे एक हैंडपंप नज़र आ गया गया. गजराज इस हैंडपंप पर पहुंच गया. हैंडपंप के हैंडल को गजराज इधर से इधर हिलाने लगा. गजराज ने यह देखा था कि इससे पानी निकलता है, लेकिन उसे हैंडपंप चलाना नहीं आ रहा था. वहां से गुज़र रहे दो बच्चों ने समझ लिया कि गजराज प्यासे हैं. अत: बच्चों ने आकर हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया. गजराज ने पेट भरकर पानी पीया और बच्चों की ओर कृतज्ञता से देखकर अपने रास्ते पर आराम से चला गया.

पौधे प्रदूषित जल को साफ़ करेंगे

पिछले दिनों बीएचयू में हिमालय क्षेत्र के छह पौधों पर हुए शोध से पता चला कि ये पौधे प्रदूषित पानी को साफ़ कर सकते हैं. इसके बाद अब इन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है. बीएचयू और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संयुक्त योजना पर काम कर रहे हैं. पहले चरण में इस तरह के पौधे गंगा में गिरने वाले 16 बड़े नालों में लगाए जाएंगे. शोधकर्ताओं का दावा है कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी में मौजूद हानिकारक क्रोमियम, निकिल, जिंक और कॉपर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हिमालय क्षेत्र के आइकॉर्निया, पिस्ट्रिया, लेमना, ट्रापा, एजोला और माइक्रोफ्रिस्टिल आदि पौधे इन रासायनिक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं. इन पौधों का परीक्षण बनारस के गंदे नाले में किया जा चुका है. अब इन पौधों को कानपुर के नालों में लगाया जाएगा. इसी क्रम से बाद में इन पौधों को गंगा क्षेत्र के अन्य नालों में लगाकर गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा.

प्रधानों ने दस हज़ार मानदेय मांग की

सहारनपुर में सरसावा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने बैठक कर सरकार से दस हज़ार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग की. समिति के कार्यालय में हुई बैठक में बिन्नाखेड़ी की प्रधान पार्वती ने कहा कि सांसद व विधायकों को चुनाव जीतते ही क्रमश: चार करोड़ और एक करोड़ 25 लाख रुपये की राशि विकास के लिए दे दी जाती है. उन्हें मानदेय और विभिन्न भत्तों में भी हज़ारों रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं. साथ ही कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनकी पेंशन भी बांध दी जाती है, जबकि प्रधान का चुनाव जोखिम भरा होता है. इस कारण उन्हें हर समय अपनी जान का ख़तरा बना रहता है. हर कोई चुनावी रंजिश को स्वीकार कर चुनाव जीतता है. इसके बदले में प्रधानों को मात्र 750 रुपये का मानदेय ही मिलता है. प्रधानों का मानदेय दस हज़ार रुपये प्रतिमाह होना चाहिए. साथ ही कार्यकाल के बाद पेंशन मिलनी चाहिए. इसके लिए सभी प्रधानों को संगठित होकर अपने हक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए. बैठक की अध्यक्षता पूर्व मेजर फूलसिंह, संचालन सतपाल टपराना ने की.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com